चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

कहां गया संसद का सेंस ऑफ हाउस

पेज-3

आरटीआई कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं

पेज-4

नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़

पेज-5

दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर माफिया बन गए हैं

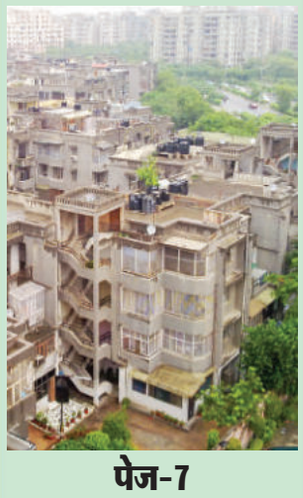

पेज-7

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 02 जनवरी–08 जनवरी 2012 | मूल्य 5 रुपये

मुसलमानों को आरक्षण

यह चुनावी स्टंट है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र यही कहा जा सकता है कि यहां हर राजनीतिक दल मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर खेल खेल रहा है. उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों में इस बात की प्रतियोगिता हो रही है कि कौन कितने बेहतर तरीक़े से मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर उनके वोट ले सकता है. सभी पार्टियां मुसलमानों में कन्फ्यूज़न फैला रही हैं, क्योंकि उनकी नज़र राज्य की 18 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी पर है, जिसे वे आज तक सिर्फ़ एक वोट बैंक समझती आई हैं.

मनीष कुमार

राजनीति का खेल भी बड़ा अजीब है. इस खेल में हर खिलाड़ी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है और करता कुछ और ही है. क्या कांग्रेस पार्टी सचमुच मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना चाहती है या फिर यह सिर्फ़ एक चुनावी स्टंट है. यह एक ऐसा सवाल है, जो हर व्यक्ति के मन में उठ रहा है. कांग्रेस अगर मुसलमानों के विकास के लिए वाकई कुछ करना चाहती है तो सालों से धूल फांक रही सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर उसने कार्रवाई क्यों नहीं की. चुनाव से पहले अचानक मुसलमानों को आरक्षण देने की बात क्यों याद आ गई. कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर राहुल गांधी की क्या-क्या मजबूरियां हैं, इसे समझना ज़रूरी है.

मुस्लिम आरक्षण के पीछे कांग्रेस की रणनीति साफ है. एक तरफ़ जनता महंगाई की मार झेल रही है, किसान आंदोलित हैं, विकास थम गया है, उद्योगों की हालत ख़राब है, स्टॉक एक्सचेंज में नुक़सान हो रहा है, ग़रीबों का जीना मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ़ एक के बाद एक घोटालों का ख़ुलासा हो रहा है, जिसमें कांग्रेस और सरकार के बड़े-बड़े नेताओं-मंत्रियों के नाम उजागर हो रहे हैं. केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए लोग कांग्रेस को ज़िम्मेदार मान रहे हैं. इस बीच खुदरा बाज़ार में विदेशी पूंजी निवेश के मामले में सरकार की सहयोगी पार्टियों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया. इन सबके ऊपर लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने ऐतिहासिक आंदोलन छेड़ दिया. कांग्रेस पार्टी अकेली और चारों तरफ़ से घिरी हुई दिख रही है. इस बीच पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. पांच राज्यों में से एक राज्य उत्तर प्रदेश है और यही कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता है. उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाला सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है. वह इसलिए, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का भविष्य दांव पर लगा है.

लोकपाल और अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से कांग्रेस घिर गई तो पार्टी में मंथन शुरू हुआ. यह मंथन भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पार्टी की साख कैसे बचाई जाए और उसके लिए रणनीति क्या बनाई जाए. अन्ना हजारे आंदोलन की धमकी दे रहे थे. उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अन्ना का असर कैसा और कितना होगा, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले इसका आकलन किया. कुछ दिनों पहले कुछ राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी सीटें जीतने में कामयाब हो गई. महाराष्ट्र में भी स्थानीय चुनाव हुए, जिनमें अन्ना हजारे के आंदोलन का असर नहीं दिखा. इसके अलावा एसी नेल्शन और स्टार टीवी का चुनावी सर्वे दिखाया गया, जिसमें कांग्रेस की स्थिति मज़बूत बताई गई. कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाया. यह तय किया गया कि सरकार सुझावों को दरकिनार करके लोकपाल बिल लेकर आएगी और कांग्रेस पार्टी अन्ना हजारे से सीधी लड़ाई करेगी. यह भी तय किया गया कि सोनिया गांधी अन्ना हजारे को चुनौती देंगी और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगी. इस रणनीति का सार यही है कि अगर लोकपाल के मामले में सरकार अन्ना के आंदोलन की हवा निकालने में कामयाब हो गई तो कांग्रेस विजयी बनकर उभरेगी.

कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह भी पता है कि अगर अन्ना का आंदोलन फिर से कामयाब हो गया तो उत्तर प्रदेश में पार्टी को भारी नुक़सान हो सकता है. इससे निपटने के लिए उन्होंने एक अहम फ़ैसला लिया. अन्ना के आंदोलन से होने वाले नुक़सान से निपटने के लिए मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा. कहने का मतलब यह कि अगर अन्ना आंदोलन नहीं करते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाएगी और अगर अन्ना आंदोलन करते हैं तो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया जाएगा. यह भी तय किया गया कि इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछड़ी जातियों को मिलने वाले 27 फ़ीसदी आरक्षण के अंदर ही 4.5 फ़ीसदी सीटें मुसलमानों को दी जाएंगी. समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की रणनीति का आधार न तो मज़बूत लोकपाल लाना है और न मुसलमानों को आरक्षण देना है. कांग्रेस की सारी रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आधारित है.

इस रणनीति को लागू करने में भी कांग्रेस पार्टी ने काफी मशक्कत की. पसंदीदा टीवी चैनलों और अख़बारों के रिपोर्टरों एवं संपादकों को प्रायोजित ख़बरें दी गईं. भ्रम फैलाया गया. कभी सीबीआई को लेकर अलग-अलग ख़बरें आती रहीं. कभी सीबीआई डायरेक्टर (प्रोसिक्यूशन) को नियुक्त करने की झूठी ख़बर फैलाई गई. मीडिया में कभी यह बताया गया कि सी और डी ग्रुप के कर्मचारी लोकपाल के अंदर हैं तो कभी यह भी ख़बर आई कि उन्हें बाहर रखा गया है. कांग्रेस के नेताओं को टीवी चैनलों पर बार-बार यह कहते सुना गया कि सरकार एक मज़बूत लोकपाल लेकर आ रही है. जब लोकपाल बिल लोगों के सामने आया तो पता चला कि बिल के आने से पहले की सारी ख़बरें झूठी थीं. इसका मतलब यही है कि सरकार लोगों में भ्रम फैला

(शेष पृष्ठ 2 पर)

कोटे में कांटा

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव, ऊपर से लोकपाल पर अन्ना के आंदोलन का डर. कांग्रेस के लिए परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. इस सबके बीच केंद्र सरकार ने अक़लियतों को 4.5 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान कर दिया और कैबिनेट ने अपनी मंज़ूरी भी दे दी. यह आरक्षण ओबीसी कोटे के 27 फ़ीसदी में से दिया जाएगा, लेकिन आरक्षण की यह राह इतनी आसान भी नहीं होने जा रही, क्योंकि कांग्रेस की इस सियासी चाल की सियासी मुख़ालफ़त भी शुरू हो गई है. जहां भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसका खुलकर विरोध किया है. मुलायम सिंह का कहना है कि इससे ओबीसी को नुक़सान होगा. ज़ाहिर है, अगले कुछ दिनों में वे राजनीतिक दल भी इस निर्णय का विरोध करेंगे, जिनकी राजनीतिक ज़मीन ही ओबीसी आबादी तैयार करती है. इसके अलावा अक़लियती रिजर्वेशन के हिमायती भी 4.5 फ़ीसदी कोटे से ख़ुश नहीं होने वाले हैं. उनकी दलील के मुताबिक़, जितनी आबादी है, उन्हें उतना रिज़र्वेशन मिलना चाहिए. ग़ौरतलब है कि मंडल कमीशन ने मुल्क में ओबीसी की आबादी 52 फ़ीसदी बताई थी, जिसमें 8.4 फ़ीसदी आबादी अक़लियतों की थी. आज सिर्फ़ मुसलमानों की आबादी 15 से 16 फ़ीसदी है. ज़ाहिर है, ऐसे में महज़ 4.5 फ़ीसदी रिजर्वेशन से अक़लियत ख़ुश हो जाएंगे, कहना मुश्किल है. दूसरी तरफ़ रंगनाथ मिश्र कमीशन ने तो 15 फ़ीसदी रिज़र्वेशन की सिफ़ारिश की थी, जिसमें से 10 फ़ीसदी मुसलमानों और 5 फ़ीसदी दीगर अक़लियतों के लिए. इस कमीशन ने एक और फॉर्मूला दिया था कि अगर 15 फ़ीसदी मुमकिन न हो तो ओबीसी कोटे में से 8.5 फ़ीसदी रिज़र्वेशन दिया जा सकता है. ऐसे में कांग्रेस की यह बाज़ी कहीं उल्टी न पड़ जाए.

पिछड़े मुसलमानों के पांच सवाल

ऑल इंडिया माइनॉरिटी ओबीसी फेडरेशन, उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आकिब अंसारी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाते हैं. उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी के दो चेहरे हैं. उत्तर प्रदेश में जितने भी मुसलमान हैं, उनमें 70 फ़ीसदी पिछड़ी जाति के हैं. मतलब यह कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 14 फ़ीसदी हिस्सा मुस्लिम पिछड़ों का है. उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पांच सवाल किए हैं. पहला यह कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कांग्रेस के कितने मंत्री मुस्लिम हैं और उनमें से कितने पिछड़ी जाति के हैं. दूसरा सवाल यह कि उत्तर प्रदेश के कितने मुस्लिम सांसद राज्यसभा में है और उनमें से कितने पिछड़ी जाति के हैं. तीसरा सवाल यह कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने मुसलमान हैं और उनमें से कितने पिछड़ी जाति के हैं. चौथा सवाल यह कि कांग्रेस पार्टी सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट कब लागू करेगी. पांचवां यह कि दलित मुसलमानों को लेकर संविधान की धारा 341 पर कांग्रेस की क्या राय है. अंसारी कहते हैं कि इन सवालों के जवाब जानने के बाद यह जानना ज़रूरी है कि जब उत्तर प्रदेश में 14 फ़ीसदी मुस्लिम पिछड़े हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कितने पिछड़े मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने वाली है. कांग्रेस पार्टी 403 सीटों में से 213 पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है. इनमें सिर्फ़ कानपुर के अब्दुल मन्नान ही ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार हैं, जो पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं. अब सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े मुस्लिमों से भेदभाव क्यों कर रही है. अगर मुस्लिम समाज से ऐसे सवाल उठ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए यह ख़तरे की घंटी है.

एक सेवानिवृत्त अधिकारी का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. मुलायम सिंह यादव के समय भी इससे अच्छी स्थिति नहीं थी.

दिल्ली का बाबू

बाबुओं का राजनीतिकरण

नौकरशाही का राजनीतिकरण कोई नई बात नहीं है. सभी चुनावों के पहले ऐसा देखा जाता है. उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने अपने सचिवालय के दो आईएएस अधिकारियों नवनीत सहगल एवं डी एस मिश्रा की सराहना सरकार के विकासात्मक कार्यों में उनकी भूमिका के लिए की. इसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई, वह कोई अप्रत्याशित नहीं थी. यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि चुनाव के समय बाबुओं का संबंध किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ होता है. एक सेवानिवृत्त अधिकारी का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. मुलायम सिंह यादव के समय भी इससे अच्छी स्थिति नहीं थी. 2007 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव एन सी वाजपेयी, डीजीपी बुआ सिंह और कुछ आईपीएस अधिकारियों को चुनाव कार्य से अलग कर दिया था, क्योंकि इन लोगों ने मुलायम सिंह यादव एवं उनके बेटे अखिलेश यादव की प्रशंसा की थी. चुनाव के समय अधिकारियों को अपने पक्ष में करने का यह पुराना रिवाज है. मायावती भी वही कर रही हैं, जो पहले से होता रहा है, लेकिन इससे बाबुओं को परेशानी होती है. उन्हें इसका ख़ामियाजा चुनाव के बाद भुगतना पड़ता है.

प्रसार भारती में सुधार नहीं

बीएस लाली को प्रसार भारती के सीईओ पद से हटाने और उनकी जगह पर राजीव टाकरु को नया कार्यवाहक सीईओ बनाए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस संस्था में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है. सूत्रों का कहना है कि प्रसार भारती के कर्मचारी टाकरु के रवैये, ख़ासकर कुछ बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के फ़ैसले से ख़ुश नहीं हैं. प्रसार भारती के कार्यवाहक सीईओ की दूरदर्शन के नवनियुक्त महानिदेशक त्रिपुरारी शरण सहित कई अधिकारियों के साथ अनबन चलती दिखाई दे रही है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आख़िरकार प्रसार भारती हमेशा ग़लत कारणों से ही चर्चा में क्यों रहती है. क्यों नहीं यह कोई ऐसा काम करती है, जिसके कारण इसकी सराहना की जाए. ऐसा लगता है कि सरकार प्रसार भारती को गंभीरता से नहीं ले रही है.

विनोद राय की परेशानी बढ़ी

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विनोद राय की परेशानी बढ़ गई है. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के सीईओ अतुल राय द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन की जांच कर रही संसद की विशेषाधिकार समिति ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है. पैनल का कहना है कि अतुल राय की नियुति सही तरीक़े से नहीं की गई है. ग़ौरतलब है कि अतुल राय की नियुक्ति के समय विनोद राय वित्तीय सेवाओं के सचिव थे, इसलिए संसदीय विशेषाधिकार समिति की मांग है कि विनोद राय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए. अतुल राय पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप है. सुप्रीम कोर्ट में उन्हें हटाए जाने के लिए मामला दर्ज किया गया है, जिस पर सुनवाई की जा रही है. अगर सीबीआई इसकी जांच करती है तो विनोद राय के लिए परेशानी बढ़ जाएगी. विनोद राय ने 2-जी मामले में हुए नुक़सान के जो आंकड़े पेश किए थे, उनसे सरकार की परेशानी बढ़ गई है. अब उन पर किसी दूसरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करने का क्या मतलब हो सकता है, यह तो बाद में ही पता चलेगा.

dilipcherian@gmail..com

दिलीप चेरियन

यह चुनावी स्टंट है

पृष्ठ एक का शेष

रही थी, ताकि अन्ना का आंदोलन असफल हो जाए. जहां तक बात मुस्लिम आरक्षण की है, उसके बारे में सलमान ख़ुर्शीद ने यह घोषणा कर दी कि सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने का फ़ैसला करने वाली है. सलमान ख़ुर्शीद ने इस मुद्दे की नींव रखी, सिर्फ़ ऐलान किया कि जल्द फ़ैसला लिया जाएगा. इसके बाद वह चुप हो गए. एक सप्ताह तक सारे सरकारी बिलों के बारे में बात होती रही. पेंशन बिल, फूड सिक्योरिटी बिल एवं लोकपाल बिल पर चर्चा होती रही, लेकिन कांग्रेस के एक भी नेता ने मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की. इस बीच राहुल गांधी का भी बयान आया, लेकिन वह बयान खुदरा बाज़ार में विदेशी निवेश के समर्थन में था. 22 दिसंबर को लोकपाल बिल पेश किया गया. उससे एक दिन पहले सोनिया गांधी का बयान आया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अन्ना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 22 दिसंबर की शाम को अन्ना हजारे का बयान आ गया. संसद में विपक्षी पार्टी और सहयोगी पार्टियों का रुख़ पता चल गया. कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि अन्ना और उनकी टीम को मनाया नहीं जा सकता. 22 तारीख़ की रात ख़बर आ गई कि केंद्रीय कैबिनेट ने मुसलमानों को आरक्षण देने के फ़ैसले पर मुहर लगा दी है. कांग्रेस पार्टी ने अल्पसंख्यकों को पिछड़ी जाति के 27 फ़ीसदी कोटे में से 4.5 फ़ीसदी आरक्षण देने का फ़ैसला लेकर एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया. अब सवाल यह उठता है कि क्या इस फ़ैसले का फ़ायदा कांग्रेस को होगा. दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोटों का अलग-अलग पार्टियों में बंटवारा हो जाएगा.

वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिज़ाज बदल रहा है. कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियां सारी मशक्कत दलितों के दिलों को जीतने के लिए करती थीं. आज समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पीस पार्टी के बीच मुस्लिम वोटों के लिए प्रतियोगिता हो रही है. मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लालच दिया जा रहा है. समाजवादी पार्टी कहती है कि वह सबसे पहली पार्टी है, जो मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रही है. सच्चाई यह है कि सालों से सरकारी आलमारी में सड़ रही रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट को जब चौथी दुनिया ने छाप दिया, तब मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट संसद में पेश करनी पड़ी. ग़ौर करने वाली बात यह है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने संसद में तो पेश कर दिया, लेकिन एक्शन टेकन रिपोर्ट के बिना. दो साल हो गए, लेकिन सरकार रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट को लागू करेगी या नहीं, इस पर कोई फ़ैसला नहीं आया है. इसलिए कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल उठना लाज़िमी है. चुनाव से ठीक पहले यह शिगूफ़ा छोड़ देना कि सरकार मुसलमानों को आरक्षण देने वाली है, सिर्फ़ एक चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है. मायावती भी मुसलमानों के वोटों के लिए अख़बारों में बड़े-बड़े इश्तेहार दे रही हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि जो काम पिछले 40 सालों में सरकारें नहीं कर सकीं, वह पिछले 4 सालों में मायावती ने मुसलमानों के लिए किया है. मायावती अब अपने हर भाषण में मुसलमानों के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर बोलती हैं. उन्होंने कांग्रेस की रणनीति पहले ही भांप ली थी, इसलिए वह पहले ही दिन से क़ानून में संशोधन करने की बात कर रही हैं.

मुसलमानों की कई जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं, इसलिए केंद्र सरकार की नौकरियों और विश्वविद्यालयों में उन्हें भी आरक्षण का फ़ायदा मिलता है. अन्य पिछड़ा वर्ग में मुसलमानों की कई जातियां आरक्षण ले रही हैं. हमारे संविधान में सिर्फ़ धर्म के नाम पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी. कांग्रेस पार्टी आरक्षण का ऐलान तो करती है, लेकिन संविधान में संशोधन का नाम नहीं लेती, इसलिए उसकी नीयत पर सवाल खड़ा होता है. जब सलमान ख़ुर्शीद कहते हैं कि मुसलमानों को ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाएगा तो यह भी राजनीति से प्रेरित नज़र आता है. उत्तर प्रदेश में चुनावी फ़ायदा उठाने के लिए यह एक सोची-समझी चाल है. इसके पीछे राजनीति यह है कि कांग्रेस अगर ओबीसी के कोटे से मुसलमानों को आरक्षण देगी तो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी. सिर्फ़ समाजवादी पार्टी ही नहीं, बल्कि वे सभी पार्टियां विरोध करेंगी, जिन्हें ओबीसी का समर्थन प्राप्त है. यह बात भी समझना ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने का विरोध नहीं करती है. मुलायम सिंह की वजह से रंगनाथ मिश्र कमीशन रिपोर्ट संसद में पेश की गई, लेकिन कांग्रेस की रणनीति ऐसी है कि मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन करने वाली पार्टियां भी विरोध में खड़ी हो जाएंगी. ऐसी हालत में इस घोषणा का अंजाम क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है. कांग्रेस अगर इस तरकीब से आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति करेगी तो यह कैसे माना जा सकता है कि वह वास्तव में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है. मायावती भी यह ऐलान कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी मुसलमानों को आरक्षण देने का समर्थन करती है और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए.

फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है. सब कुछ कहने का मतलब यह है कि पार्टी राहुल गांधी को 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनाना चाहती है. ऐसा लगता है कि पार्टी के लिए अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के अलावा कोई और राजनीतिक या वैचारिक युद्ध नहीं बचा है. सोनिया गांधी के हर फ़ैसले के पीछे की सोच यही है कि फ़ैसला किस तरह राहुल गांधी के लिए फ़ायदेमंद होगा. उत्तर प्रदेश का चुनाव राहुल गांधी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है. पार्टी को लगता है कि जिस तरह 2009 के चुनावों में 22 सीटें जीतकर वह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समकक्ष खड़ी हो गई, उसी तरह इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी. कुछ टीवी चैनलों पर सर्वे रिपोर्ट दिखाई गई, जिसमें कांग्रेस की स्थिति मज़बूत नज़र आ रही है. अगर कांग्रेस पार्टी को 60 से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को विजेता माना जाएगा. हो सकता है कि चुनाव के बाद कांग्रेस की सहायता से ही उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बने. ऐसी स्थिति पैदा हो, यही कांग्रेस की रणनीति है. अगर कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले जितनी रहीं या घट गईं तो यह कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हार होगी. राहुल गांधी की काबिलियत और नेतृत्व पर सवाल तो उठेगा ही, 2014 में प्रधानमंत्री बनने का दावा भी खोखला साबित हो जाएगा. कांग्रेस पार्टी फिर से उसी राह पर चल पड़ेगी, जिस पर वह राजीव गांधी की हत्या के बाद चल पड़ी थी. हार के बाद राहुल गांधी की मानसिक स्थिति क्या होगी, यह तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन पार्टी को मज़बूत बनाए रखने के लिए राहुल गांधी के अलावा किसी दूसरे नेता की तलाश करनी होगी, जिसे प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया जा सके और वह प्रियंका गांधी हो सकती हैं.

यह सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि ज़मीनी हक़ीक़त कांग्रेस के अनुकूल नहीं है. कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है. मुस्लिमों के समर्थन के बिना वह उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं जीत सकती. यही वजह है कि उसने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया है. इसके बावजूद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुस्लिम वोट पाना आसान नहीं है. यह नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सीटें इसलिए बढ़ी थीं, क्योंकि मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया था. वह भी इसलिए, क्योंकि वरुण गांधी ने मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़राब भाषण दिया था. कहीं आडवाणी प्रधानमंत्री न बन जाएं, इसलिए भी मुसलमानों ने कांग्रेस का हाथ मज़बूत किया था. मनमोहन सिंह ने मुसलमानों से कई वायदे किए थे. सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की वजह से कांग्रेस पर मुसलमानों का भरोसा जगा था. लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज़ थे. आज़म ख़ान पार्टी के ख़िलाफ़ आग उगल रहे थे. इसका असर दिखा और मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को छोड़ कांग्रेस का साथ दिया था. लेकिन अब हालात बदल गए हैं. मुसलमानों को कांग्रेस के वायदों पर भरोसा नहीं रहा. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीतने वाली नहीं है और न उसका कोई हिंदूवादी नेता मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में है. इसलिए कांग्रेस की रणनीति सफल होती नज़र नहीं आती है. कांग्रेस की दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके अपने कार्यकर्ता नाराज़ हो रहे हैं. जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, नाराज़ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ रही है. जिन युवाओं को राहुल गांधी ने पार्टी संगठन से जोड़ने की मुहिम चलाई, वे अब कांग्रेस के ख़िलाफ़ खड़े हैं. यह एहसास कांग्रेस के नेताओं को भी है. पहले राहुल गांधी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन माहौल बदलने की वजह से उन्हें अजित सिंह के साथ गठबंधन करना पड़ा. इससे कुछ सीटों पर कांग्रेस को फ़ायदा तो होगा, लेकिन नुक़सान भी झेलना पड़ेगा. जहां-जहां अजित सिंह की पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, वहां-वहां कांग्रेस पार्टी को विद्रोह का सामना करना पड़ेगा. इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को आरक्षण देने का शिगूफ़ा छोड़ा है. चुनाव से पहले मुसलमानों को आरक्षण देने की बात उठाना महज़ एक चुनावी स्टंट है.

manish@chauthiduniya.com

साउथ ब्लॉक

शंकर अग्रवाल बने एएस

1980 बैच के आईएएस अधिकारी शंकर अग्रवाल को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वह राकेश कृष्ण माथुर की जगह लेंगे. माथुर को एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

शैलेष सिंह जेएस बने

1991 बैच के आईएएस अधिकारी शैलेष कुमार सिंह को कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है. वह रजनीश कुमार महाजन की जगह लेंगे.

पंकज गर्ग बने जेडीसी

1995 बैच के आईटीएस अधिकारी पंकज गर्ग को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त विकास आयुक्त बनाया गया है. वह हुकुम सिंह मीणा की जगह लेंगे.

पांडा गृह मंत्रालय में

1981 बैच के आईएएस अधिकारी सुरेश चंद्र पांडा को गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार बनाया गया है. वह डॉ. विश्वनाथ त्रिवेदी की जगह लेंगे, जिन्हें खनन मंत्रालय में सचिव बनाया गया है.

दीप्ति विलास को शहरी विकास मंत्रालय

1981 बैच के आईएएस अधिकारी देवेरकोंडा दीप्ति विलास को शहरी विकास मंत्रालय में एएस बनाया गया है. वह आर सी मिश्रा की जगह लेंगे, जिन्हें श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भेजा गया है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 43
दिल्ली, 02 जनवरी–08 जनवरी 2012
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)
सी–20, ट्रांस यमुना, एनएच–2, आगरा
फोन : 0526–4064901, 9837082462

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन
मुरलीधर कॉम्प्लेक्स, बुटीवाडा के सामने होटल गणराज के बाजू में टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर–440012
फोन नं : 0712–2544988, 2549846

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

लोकपाल के दायरे से सीबीआई को बाहर कर दिया, ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल की जगह सीवीसी के अधीन कर दिया. जांच के बाद सीवीसी लोकपाल को रिपोर्ट करेगा.

लोकपाल के नाम पर धोखा

कहां गया संसद का सेंस ऑफ हाउस

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

रामलीला मैदान के अनशन के बाद जब संसद ने सेंस ऑफ हाउस पास किया, तब एक सशक्त लोकपाल की उम्मीद बंधी थी. सेंस ऑफ हाउस पास तो हुआ, लेकिन टीम अन्ना सहित इस देश की जनता यह नहीं समझ पाई कि इस सेंस ऑफ हाउस की वैधानिकता क्या है, क्या इसे स्थायी समिति हूबहू मान लेगी और क्या यह बाध्यकारी निर्णय होगा? ज़ाहिर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ. सरकार ख़ुद अपने सेंस को नहीं समझ पाई, जनता के मूड को नहीं समझ पाई.

शशि शेखर

इस बार दिल्ली की जगह मुंबई में अन्ना का अनशन होगा. जंतर–मंतर और रामलीला मैदान से गिरफ्तारियां दी जाएंगी. इसकी घोषणा टीम अन्ना ने कर दी है. आख़िरकार, वही हुआ, जिसकी आशंका चौथी दुनिया लगातार ज़ाहिर कर रहा था. अगस्त का अनशन ख़त्म होते ही चौथी दुनिया ने बताया था कि देश की जनता के साथ धोखा हुआ है. एक मज़बूत लोकपाल अब नहीं बन पाएगा. टीम अन्ना को तब तो ऐसी आशंका नहीं थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आते ही वह भी इसी आशंका से घिर गई. लोकपाल के सरकारी प्रारूप में 60 से भी ज़्यादा संशोधन हुए, इसे कैबिनेट ने पास भी कर दिया और इसी के साथ अन्ना के एक और अनशन की पृष्ठभूमि भी सरकार ने तैयार कर दी. इसी के साथ एक और बड़ी भूल सरकार कर रही है. वह टीम अन्ना के आंदोलन को महज़ लोकपाल से जुड़ा आंदोलन समझने की ग़लती कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है. जंतर–मंतर, रामलीला मैदान, आज़ाद मैदान या देश भर में प्रभातफेरी, रैली या प्रदर्शन करते युवा, प्रौढ़ या वृद्ध सिर्फ़ एक जन लोकपाल के लिए सड़कों पर नहीं उतरते. वे इस उम्मीद में अन्ना के साथ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जन लोकपाल पास होगा तो उनकी सारी समस्याएं दूर नहीं तो कम ज़रूर हो जाएंगी. युवाओं को उम्मीद है कि उन्हें नौकरी या एडमीशन के लिए रिश्वत या पैरवी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा. व्यापारी या नौकरीपेशा लोग सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी से राहत की उम्मीद लगाए हुए हैं. वृद्ध या प्रौढ़ आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए जन लोकपाल की मांग कर रहे हैं. दरअसल, भ्रष्टाचार जैसी समस्या से आज देश के हर तबके, हर जाति, हर धर्म के लोग पीड़ित हैं.

सरकार जनता की इस आस को, उम्मीद को लगातर कुचलने का काम कर रही है. पहले जंतर–मंतर, फिर रामलीला मैदान. हर जगह उसने टीम अन्ना और देश की जनता को छलने का काम किया. बीते 27 अगस्त को संसद में पास सेंस ऑफ हाउस को भी स्टैंडिंग कमेटी ने दरकिनार करते हुए वही किया, जो सरकार करना चाहती थी. लोकपाल के दायरे से सीबीआई को बाहर कर दिया, ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल की जगह सीवीसी के अधीन कर दिया. जांच के बाद सीवीसी लोकपाल को रिपोर्ट करेगा. वहीं जन शिकायतों और उच्च न्यायपालिका के मामले में अलग से बिल पेश कर दिया गया यानी अब लोकपाल के दायरे में न सीबीआई, न सिटीज़न चार्टर और न ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारी होंगे. हां, प्रधानमंत्री को कुछ शर्तों के साथ लोकपाल के दायरे में ज़रूर रखा गया है, लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं, उनकी वजह से प्रधानमंत्री का इसके दायरे में होना या न होना बराबर है. मसलन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामलों को छोड़कर

लोकपाल के दायरे से सीबीआई को बाहर कर दिया, ग्रुप सी के कर्मचारियों को लोकपाल की जगह सीवीसी के अधीन कर दिया. जांच के बाद सीवीसी लोकपाल को रिपोर्ट करेगा. वहीं जन शिकायतों और उच्च न्यायपालिका के मामले में अलग से बिल पेश कर दिया गया यानी अब लोकपाल के दायरे में न सीबीआई, न सिटीज़न चार्टर और न ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारी होंगे.

जन लोकपाल क्यों ख़ास है

जांच या मुक़दमा

- वर्तमान व्यवस्था: तमाम सबूतों के बाद भी कोई नेता या बड़ा अफसर जेल नहीं जाता. एंटी करप्शन ब्रांच और सीबीआई सीधे सरकारों के अधीन आती है. जांच या मुक़दमा शुरू करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है.
- जन लोकपाल पास हो तब: प्रस्तावित क़ानून के बाद केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त सरकार के अधीन नहीं होंगे. एसीबी और सीबीआई को इसके अधीन लाया जाएगा. भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुक़दमे के लिए इन्हें सरकार से इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जांच जल्द पूरी होगी.

सीवीसी

- वर्तमान व्यवस्था: तमाम सबूतों के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी सरकारी नौकरी पर बने रहते हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग केवल केंद्र सरकार को सलाह दे सकता है, जिसे अमूमन माना नहीं जाता.
- जन लोकपाल पास हो तब: प्रस्तावित लोकपाल और लोकायुक्तों के पास शक्ति होगी कि वे भ्रष्ट लोगों को उनके पद से हटा सकें. केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्यों के विजिलेंस विभागों को लोकपाल के तहत लाया जाएगा.

व्हिसल ब्लोअर

- वर्तमान व्यवस्था: अगर आम आदमी भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसकी शिकायत कोई नहीं सुनता, उसे प्रताड़ित किया जाता है, धमकी दी जाती है.
- जन लोकपाल पास हो तब: लोकपाल और लोकायुक्त किसी की शिकायत को खुली सुनवाई किए बिना ख़ारिज़ नहीं कर सकेंगे. आयोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे.

पारदर्शिता

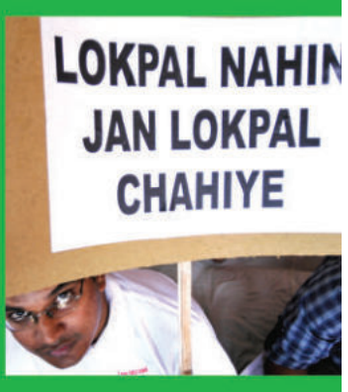

- वर्तमान व्यवस्था: सीबीआई और विजिलेंस विभागों का कामकाज गोपनीय होता है. नतीजतन भ्रष्टाचार होना लाज़िमी है.
- जन लोकपाल पास हो तब: लोकपाल और लोकायुक्तों का कामकाज पारदर्शी होगा. जांच के बाद सारे रिकॉर्ड जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे. ख़ुद के कर्मचारी के ख़िलाफ़ भी शिकायत आने पर उसकी जांच करने और उस पर जुर्माना लगाने का काम अधिकतम दो महीने में पूरा करना होगा.

नियुक्ति

- वर्तमान व्यवस्था: कमज़ोर, भ्रष्ट और राजनीति से प्रभावित लोग एंटी करप्शन विभागों के मुखिया बनते हैं.
- जन लोकपाल पास हो तब: लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति में नेताओं की भूमिका कम से कम होगी. इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीक़े और जनता की भागीदारी से होगी.

जन शिकायत

- वर्तमान व्यवस्था: सरकारी दफ्तरों में लोगों से रिश्वत मांगी जाती है. लोग ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं करते, क्योंकि वे भी इसमें शामिल होते हैं.
- जन लोकपाल पास हो तब: लोकपाल और लोकायुक्त किसी व्यक्ति का तय समय सीमा में किसी भी विभाग में काम न होने पर दोषी अधिकारियों पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगा सकेंगे, जो शिकायतकर्ता को मुआवज़े के रूप में मिलेगा.

संपत्ति वसूली

- वर्तमान व्यवस्था: भ्रष्ट व्यक्ति के पकड़े जाने पर भी उससे रिश्वतखोरी से कमाया गया पैसा वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है.
- जन लोकपाल पास हो तब: भ्रष्टाचार से सरकार को हुई हानि का आकलन कर दोषियों से उसकी वसूली की जाएगी.

सज़ा

- वर्तमान व्यवस्था: भ्रष्टाचार के मामले में 6 महीने से लेकर अधिकतम 7 साल तक कारावास का प्रावधान है.
- जन लोकपाल पास हो तब: कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा.

संवैधानिक दर्जा का क्या फ़ायदा?

कुछ समय पहले ही सीवीसी पी जे थॉमस की नियुक्ति को याद कीजिए या फिर इस देश की संवैधानिक संस्थाओं की हालत पर ग़ौर कीजिए. चुनाव आयोग या कैग का कार्यालय. 2-जी मामले में कैग की रिपोर्ट को ही सरकार में शामिल सारे मंत्री झूठी साबित करने पर आमादा थे या फिर याद कीजिए कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कब किस राजनीतिक दल की मान्यता चुनाव आयोग ने ख़त्म की. जबकि हर चुनाव के दौरान लगभग सैकड़ों उम्मीदवारों को चुनाव आयोग नोटिस जारी करता है. अब सरकार लोकपाल संस्था को संवैधानिक दर्जा देने की बात कह रही है, लेकिन सवाल है कि पहले से मौजूद संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है, उसमें यह नई संस्था कैसे और कितनी कारगर साबित होगी. जिस तरह इस संस्था का गठन होगा और लोकपाल या अन्य सदस्यों की नियुक्ति होगी, उससे यह संस्था कितनी मज़बूत बन पाएगी? इस संस्था के सदस्यों के चयन में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के जजों की चार सदस्यीय समिति की भूमिका होगी यानी लोकपाल या उसके सदस्यों को नियुक्त करने में सबसे ज़्यादा राजनेताओं की भूमिका होगी. ऊपर से 50 फ़ीसदी आरक्षण का भी प्रावधान है.

ऐसा नहीं हुआ

मुद्दा	जन लोकपाल	सरकारी लोकपाल
प्रधानमंत्री	बिना शर्त दायरे में	सशर्त दायरे में
सरकारी कर्मचारी	ग्रुप ए से डी तक	सिर्फ़ ग्रुप ए, बी
		ग्रुप सी, डी सीवीसी के दायरे में
संसद में सांसदों का आचरण	लोकपाल जांच के दायरे में	लोकपाल जांच से छूट
सीबीआई	लोकपाल के अधीन	लोकपाल के दायरे से बाहर
उच्च न्यायपालिका	लोकपाल के दायरे में	नहीं, अलग क़ानून
सिटीज़न चार्टर	लोकपाल के तहत	नहीं, अलग क़ानून
व्हिसल ब्लोअर	लोकपाल के तहत	नहीं, अलग क़ानून
लोकपाल की नियुक्ति	नेताओं की भूमिका कम	नेताओं की भूमिका ज़्यादा
बर्खास्तगी	कोई भी कर सकता है शिकायत	सौ से ज़्यादा सांसदों की शिकायत पर महाभियोग

ही प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाया गया है. इसके अलावा प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ किसी शिकायत को तभी शिकायत माना जाएगा और जांच तभी होगी, जब इसके लिए लोकपाल सहित इस संस्था के ज़्यादातर सदस्यों की सहमति हो.

बहरहाल, जहां पिछले 40 सालों में लोकपाल विधेयक को क़ानून बनाने के लिए ज़रूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था, वहीं जब यह क़ानून बनने जा रहा है, तब भी ऐसा लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन को लेकर संजीदा नहीं है. जल्दबाज़ी में कहें या किसी दबाव में, लोकपाल जैसी महत्वपूर्ण संस्था का हश्र भी सीबीआई और सीवीसी जैसा हो जाएगा, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है. व्यवस्था की खामियों का फ़ायदा उठाकर जिस तरह जनता की संपत्ति को अब तक लूटा गया, क्या सरकारी लोकपाल उसे रोक पाएगा, क्योंकि पहले भी सीबीआई, सीवीसी, विजिलेंस जैसे भ्रष्टाचाररोधी विभाग तो थे ही. अब एक और संस्था यानी लोकपाल का नाम इस सूची में जुड़ जाएगा. दरअसल, भ्रष्टाचार का कैंसर इतना फैल चुका है कि उसे मौजूदा सरकारी लोकपाल बिल के सहारे ख़त्म नहीं किया जा सकता. एक उम्मीद थी कि स्वतंत्र लोकपाल के तहत सीबीआई एवं सीवीसी जैसी संस्थाएं होंगी तो लोकपाल निष्पक्ष, स्वतंत्र और सक्षम रूप से जांच कर पाएगा, जनता की शिकायतों का निवारण हो सकेगा, रिश्वतखोरी पर अंकुश लगाया जा सकेगा, लेकिन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी नियंत्रण में रहते हुए जो हाल सीबीआई या सीवीसी का हुआ, वही सरकार के इस लोकपाल का भी होगा, इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. अब सवाल उठता है कि जन लोकपाल के लिए सड़कों पर उतरी जनता क्या करेगी, भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन छेड़ चुकी जनता के पास क्या विकल्प बचेगा?

shashishekhar@chauthiduniya.com

शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगांव के मराठीभाषियों के साथ अन्याय और उनका उत्पीड़न करने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया.

बिहार

आरटीआई कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं

अपराधियों से कहीं ज़्यादा पुलिस-प्रशासन की उदासीनता उन्हें परेशान करने लगी. आख़िरकार वही हुआ, जिसका डर था. बीते आठ दिसंबर को वह दिनदहाड़े गोलियों से भून डाले गए. जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह चिल्लाते रहे, उसी बमबम सिंह के ख़िलाफ़ उनकी हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है. दुःख की बात यह है कि अब तक वह शातिर पकड़ा नहीं गया है. शायद पकड़ा भी न जाए. ऐसा इसलिए, क्योंकि बमबम सिंह की पुलिस से मिलीभगत की एक बानगी रामविलास सिंह द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग को लिखे एक पत्र में मिलती है.

सरोज सिंह

सूचना के अधिकार के सिपाही रामविलास सिंह अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाते रहे, पर लखीसराय सहित बिहार का सारा पुलिस अमला आराम से सोता रहा. राज्य मानवाधिकार आयोग में भी उनकी फरियाद अनसुनी रह गई. अपराधी उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे और प्रशासन ने आंखें मूंद लेने में भलाई समझी. रामविलास की दुविधा यह हो गई कि वह कई मोर्चे पर एक साथ लड़ने को मजबूर हो गए थे. अपराधियों से कहीं ज़्यादा पुलिस–प्रशासन की उदासीनता उन्हें परेशान करने लगी. आख़िरकार वही हुआ, जिसका डर था. बीते आठ दिसंबर को वह दिनदहाड़े गोलियों से भून डाले गए. जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह चिल्लाते रहे, उसी बमबम सिंह के ख़िलाफ़ उनकी हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है. दु:ख की बात यह है कि अब तक वह शातिर पकड़ा नहीं गया है. शायद पकड़ा भी न जाए. ऐसा इसलिए, क्योंकि बमबम सिंह की पुलिस से मिलीभगत की एक बानगी रामविलास सिंह द्वारा बिहार मानवाधिकार आयोग को लिखे एक पत्र में मिलती है. बमबम सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में उन्होंने लिखा था कि पुलिस अधीक्षक लखीसराय द्वारा भेजा गया जांच प्रतिवेदन सही है, लेकिन उसके साथ लगा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय का जांच प्रतिवेदन दोषपूर्ण है. उक्त दोनों मामलों में कुर्की–जब्ती लखीसराय थाने को ही करनी है.

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लखीसराय के जांच प्रतिवेदन में कहा गया है कि उक्त दोनों मामलों में कुर्की–जब्ती हो चुकी है, जबकि ऐसा आज तक नहीं हुआ. अगर कुर्की–जब्ती हुई है तो लखीसराय कोर्ट से उसकी सूची की नकल मांगने पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का काला चेहरा सामने आ जाएगा. 25 सितंबर को लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि दो–दो हत्याओं का दोषी लखीसराय पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा जा रहा है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि लखीसराय थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मोटी रकम लेकर अभियुक्त को राहत दिए हुए हैं. थानाध्यक्ष लखीसराय के मोबाइल की एक वर्ष की काल डिटेल निकाल कर देखने से पता चल जाएगा कि वह अपराधियों को किस तरह संरक्षण देते हैं. पत्र में रामविलास सिंह ने लिखा कि मेरी मांग पर पुनर्विचार करके अभियुक्त को पकड़ कर मेरी जान–माल की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, वरना यह भ्रष्ट थानाध्यक्ष कभी भी मुझे झूठे मामले में फंसा सकता है या किसी अपराधी से मरवा सकता है.

विनोद सिंह | शिवप्रकाश राय | रामकृपाल यादव | पशुपति नाथ पारस

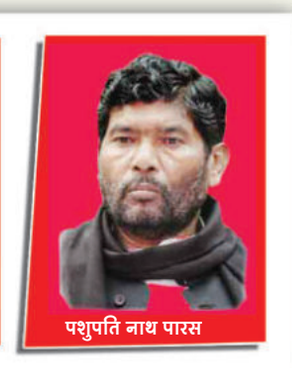

रामविलास सिंह का पत्र इस बात की ओर इशारा करता है कि बिहार में आरटीआई कार्यकर्ताओं के लिए काम करना कितना मुश्किल हो गया है. रामविलास सिंह से पहले 2010 में बरौनी में शशिधर मिश्रा की हत्या हो चुकी है. आरटीआई कार्यकर्ता शिवप्रकाश राय बताते हैं कि बिहार में एक सौ से अधिक फ़र्ज़ी मुक़दमे आरटीआई कार्यकर्ताओं पर दर्ज हो चुके हैं. मानवाधिकार आयोग ने उनमें से 54 मामले वापस लेने और दोषी लोगों को दंडित करने का निर्देश दिया है, पर दु:ख की बात यह है कि यथास्थिति बनी हुई है. रामविलास सिंह ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग समेत समस्त आला अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर सूचना के अधिकार के तहत उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई और भ्रष्ट डीएसपी की संपत्ति का ब्योरा भी मांगा था, बावजूद इसके हत्याभियुक्त के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न किया जाना हत्या की साजिश में पुलिस पदाधिकारियों के शामिल होने के कयास को पुख्ता करता है. शिवप्रकाश राय की मांग है कि हत्या की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. जिन पुलिस अधिकारियों पर पूर्व में ही उन्होंने संदेह व्यक्त किया है और जिनके इस हत्या की साजिश में शामिल होने की आशंका है, उनसे इस मामले की जांच कराना न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है. इसलिए संबंधित थानेदार एवं डीएसपी की अपराधियों के साथ साठगांठ की जांच की जाए और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई भी की जाए. मृतक के परिवारीजनों को आज भी जान का ख़तरा बना हुआ है, उनकी सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए.

नागरिक अधिकार मंच ने हत्या के विरोध में पटना में धरने का आयोजन कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की. नेशनल आरटीआई फोरम की संयोजक डॉ. नूतन ठाकुर ने कहा कि देश में सूचना अधिकार अधिनियम का ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो रहा है. रामविलास सिंह और शशिधर मिश्रा की हत्या यह बताती है कि बिहार में भी स्थिति अच्छी नहीं है. सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश कुमार ने रामविलास सिंह की हत्या की उच्चस्तरीय जांच की मांग की. जदयू विधान पार्षद विनोद सिंह कहते हैं कि हत्या किसी की हो, वह निंदनीय है. लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है. राजद सांसद रामकृपाल यादव का कहना है कि यह रामविलास सिंह की नहीं, बल्कि आम जनता को मिले लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या है. ये हत्याएं सरकार की शह पर हो रही हैं, ताकि सच की आवाज़ दबाई जा सके. सच्चाई के लिए लड़ने वालों को सरकार कोई सुरक्षा नहीं दे रही है. राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है. लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस कहते हैं कि रामविलास सिंह की हत्या सरकार की नाकामी का परिणाम है. इस सरकार में जान–माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र

बेलगांव पर सियासत गर्म

राजेश नामदेव

कर्नाटक सरकार द्वारा मराठी बाहुल्य सीमावर्ती बेलगांव (बेलगाम) की महानगरपालिका बर्ख़ास्त किए जाने को लेकर महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में अचानक गर्मी आ गई है. सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इस निर्णय की आलोचना करते हुए कर्नाटक सरकार पर मराठीभाषियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया. यह मुद्दा महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भी उठा. सरकार ने एक बार फिर बेलगांव को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने का प्रस्ताव विधानसभा एवं विधान परिषद में सर्वसम्मति से पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का फ़ैसला लिया, लेकिन इस मुद्दे ने राज्य के विपक्षी गठबंधन के दो बड़े घटकों यानी शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर आमने–सामने खड़ा कर दिया है. वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी कुछ सवाल खड़े किए हैं. ग़ौरतलब है कि मराठी बाहुल्य बेलगांव को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद राज्य गठन के साथ ही शुरू हो गया था. यहां स्थानीय निकाय के चुनावों में अक्सर मराठीभाषी प्रतिनिधियों का वर्चस्व रहता है. अक्सर देखा गया है कि जब भी मनपा की सत्ता मराठीभाषियों के पास आती है तो उसके कामकाज में राज्य सरकार द्वारा अड़चनें पैदा की जाती हैं या उसे बर्ख़ास्त कर दिया जाता है. यह भी आरोप लगाया जाता है कि कर्नाटक के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले मराठी वहां दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह गए हैं. वर्ष 2005 के बाद यह विवाद पुन: बेलगांव मनपा को कर्नाटक सरकार द्वारा बर्ख़ास्त किए जाने से सुलग उठा. बीते 10 दिसंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा जब मुंबई में कर्नाटक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने मुलुंड स्थित कालिदास नाट्यगृह पहुंचे तो वहां शिवसैनिकों ने उनके ख़िलाफ़ जमकर नारे लगाए. शिवसैनिक नारे लगा रहे थे कि कर्नाटक सरकार बेलगांव के मराठीभाषियों पर अत्याचार करना बंद करे. शिवसैनिकों के विरोध के चलते सदानंद गौड़ा को पुलिस के घेरे में नाट्यगृह के पिछले दरवाजे से निकल कर कार्यक्रम से जाना पड़ा. उसके दो दिनों बाद ही नागपुर में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया, जिसमें शिवसेना के विधायकों ने बेलगांव का मुद्दा उठाया. बेलगांव का मुद्दा राज्य की राजनीति में काफी भावनात्मक माना जाता है. शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा बेलगांव के मराठीभाषियों के साथ अन्याय और उनका उत्पीड़न करने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया. इस पर पूरे सदन ने एक स्वर में बेलगांव में मराठियों के साथ हो रहे अन्याय की बात स्वीकार की, लेकिन सदन की विषय सारणी में शामिल न होने के कारण इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकी और सदन की कार्यवाही चार बार स्थगित करनी पड़ी.

इसके बाद सरकार बेलगांव पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई. चूंकि बेलगांव मनपा में सत्तारूढ़ दल के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी उसे बर्ख़ास्त किया गया, इसलिए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दोनों सदनों में स्थगन प्रस्ताव रखते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार का क़दम संविधान सम्मत नहीं है. इससे बेलगांव वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और दोनों राज्यों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है. सरकार द्वारा सदन में रखे गए स्थगन प्रस्ताव में बर्ख़ास्त शब्द का उपयोग न किए जाने पर शिवसेना के विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई. विधान परिषद में शिवसेना के उपनेता दिवाकर रावते ने नियम 289 के तहत अपना स्थगन प्रस्ताव रखते हुए कर्नाटक सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग की. इस मांग पर भाजपा को छोड़कर लगभग सभी दल एकमत दिखे. उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. विशेष बात यह रही कि बेलगांव पर दोनों सदनों में जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसका शिवसेना ने बहिष्कार किया. शिवसेना नेता दिवाकर रावते एवं रामदास क़दम बर्ख़ास्त शब्द को प्रस्ताव में शामिल करने की मांग कर रहे थे. सरकार ने भाजपा के सहयोग से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया. प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई कि बेलगांव को लेकर कर्नाटक–महाराष्ट्र के बीच जो विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर फ़ैसला आने तक उसे केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया जाए, वहां रहने वाले मराठीभाषियों पर हो रहे अन्याय को रोका जाए, क्योंकि यह मुद्दा महाराष्ट्र की अस्मिता का है.

feedback@chauthiduniya.com

राज ठाकरे का अंदाज़ अलग

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि बेलगांव के मराठीभाषियों को कर्नाटक में ही रहना चाहिए, वहां की भाषा सीखकर स्थानीय लोगों से सामंजस्य बनाना चाहिए, जैसा महाराष्ट्र में रहने वाले कर्नाटक और आंध्र के लोग करते हैं. राज ने कहा कि यदि महाराष्ट्र में बेलगांव को शामिल किए जाने पर बेलगांव वासियों की दशा विदर्भ की तरह होनी है तो उसका कर्नाटक में ही रहना उचित होगा. इस मुद्दे पर राज ठाकरे और शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आमने–सामने हैं.

भाजपा-शिवसेना आमने-सामने

बेलगांव मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा और शिवसेना के मतभेद खुलकर सामने आए. शिवसेना जहां दोनों सदनों में पारित प्रस्ताव में कर्नाटक सरकार को बर्ख़ास्त किए जाने की मांग शामिल कराना चाहती थी, वहीं भाजपा ने बेलगांव के मराठीभाषियों के साथ अन्याय-अत्याचार रोकने की मांग का तो समर्थन किया, पर कर्नाटक सरकार को बर्ख़ास्त करने की मांग का विरोध किया, क्योंकि कर्नाटक में उसकी पार्टी की सरकार है. इसके चलते शिवसेना ने दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित किए जाने पर बहिष्कार का रास्ता अपनाया, जबकि सरकार ने भाजपा की मदद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की घोषणा कर दी.

भारत में करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पर्याप्त संख्या में स्कूल-कॉलेज नहीं हैं, जहां देश के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें.

यूआईडी

नागरिकों के मूल अधिकारों के साथ खिलवाड़

डॉ. क़मर तबरेज़

जब लोकपाल बिल को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अन्ना हज़ारे का एक दिवसीय अनशन शुरू हुआ तो उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जनलोकपाल बिल पर बहस करने की दावत दी, लेकिन सांसदों ने यह कहकर हंगामा खड़ा कर दिया कि इस बिल पर चर्चा करने का अधिकार केवल संसद को है, सड़क पर चर्चा नहीं होनी चाहिए. क्या सरकार और हमारे नेता इस बात का जवाब दे सकते हैं कि जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में जारी आधार स्कीम पर सवालिया निशान लगाते हुए उसे ख़ारिज करके सरकार से उस पर दोबारा ग़ौर करने के लिए कहा है तो फिर क्यों अभी तक यह कार्ड बनने का सिलसिला जारी है. हमारे सांसद इस बात को लेकर हंगामा क्यों नहीं करते कि संसद में चर्चा और यूआईडी बिल पास किए बिना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने नंदन नीलेकणी को इतना बड़ा अधिकार कैसे दे दिया. यूआईडी कार्ड के नामांकन के समय नागरिकों से उनके उंगलियों और आइरिस स्कैनिंग जैसे बायोमैट्रिक्स निशान लिए जा रहे हैं, जिनकी मंजूरी संसद से नहीं ली गई है. बायोमैट्रिक्स निशान तो अपराधियों के लिए जाते हैं और जब वे रिहा हो जाते हैं तो उनके बायोमैट्रिक्स निशानों को भी ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन यूआईडी के तहत नागरिकों के जो बायोमैट्रिक्स निशान लिए जा रहे हैं, वे तो हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे और वह भी यूआईडीएआई जैसी असंवैधानिक संस्था के पास, जिसने सभी डाटा को एकत्र करने का काम निजी कंपनियों को दे रखा है. क़ानून और संसद की इतनी बड़ी अवहेलना देश में हो रही है और सरकार ख़ामोश है. ये सभी सवाल ऐसे हैं, जिनका जवाब यूपीए सरकार को देना होगा.

इस कार्ड द्वारा पूरी दुनिया के नागरिकों का डाटा इकट्ठा करके कंप्यूटर के किसी एक सर्वर पर डालने की योजना बनाई जा रही है. ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में अलग-अलग राष्ट्रों की सीमाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा. जिस देश के पास ये तमाम जानकारियां होंगी, वह बड़ी आसानी से किसी एक जगह पर बैठकर पूरी दुनिया पर बेरोकटोक राज करेगा. अगर ऐसा हुआ तो यह पूरे विश्व के लिए निहायत ख़तरनाक स्थिति होगी, क्योंकि जो देश पिछड़े और ग़रीब हैं, उनके नागरिकों को ताकतवर देशों की गुलामी करनी पड़ेगी. एक शंका यह भी जताई जा रही है कि अगर इस कार्ड का धारक सात से दस वर्षों तक इसका प्रयोग नहीं करेगा तो उसे बड़ी आसानी से मृत घोषित कर दिया जाएगा.

इस योजना पर सरकार अब तक 556 करोड़ रुपये ख़र्च कर चुकी है. लोगों के बढ़ते विरोध से ऐसा लगता है कि सरकार को आज नहीं तो कल यह प्रोजेक्ट वापस लेने पर विवश होना पड़ेगा. नंदन नीलेकणी ने जितने भी तर्क इस कार्ड के पक्ष में दिए थे, उन सभी को देश का बुद्धिजीवी वर्ग ख़ारिज कर चुका है. माना जा रहा है कि यूआईडी कार्ड देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ख़तरा है. प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैथ्यू थॉमस एवं सामाजिक कार्यकर्ता वी के सोमशेखर ने बंगलुरू की एक अदालत में अपील दायर की है कि इस प्रोजेक्ट को अवैध घोषित किया जाए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह योजना कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है. उन्होंने कहा कि इसका मूल उद्देश्य नागरिकों की गतिविधियों पर नज़र रखना, उनकी जासूसी करना और क्षेत्रीय एवं भौगोलिक बुनियाद पर नागरिकों की जानकारी व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में लाना है. इसके द्वारा कुछ स्थायी और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, वित्तीय संस्थाओं, इंश्योरेंस, टेलीकॉम एवं इमेजिंग कंपनियों, हितवादी संगठनों, संदिग्ध पृष्ठभूमि वाले संगठनों को लाभ पहुंचाया जा सकता है. यह सब करदाताओं से प्राप्त धन से किया जा रहा है, जो कि सरासर क़ानून का उल्लंघन है. यह भी एक सच्चाई है कि आधार कार्ड के नामांकन के लिए जिन लोगों को लगाया गया है, न तो उनकी पृष्ठभूमि जानने की कोशिश की गई और न यह जानने की कि कहीं ये लोग देश विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं हैं.

दूसरा सवाल यह उठता है कि देश के अंदर जब किसी का पासपोर्ट बनता है तो उसके लिए पुलिस द्वारा पहले जांच-पड़ताल की जाती है, लेकिन यूआईडी कार्ड बनवाने के लिए किसी जांच-पड़ताल की कोई ज़रूरत नहीं है. इस स्थिति में कोई भी बड़ी आसानी से यह कार्ड बनवा सकता है, चाहे वह विदेशी ही क्यों न हो या फिर उसका संबंध किसी आतंकी समूह से ही क्यों न हो. मसलन, पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय में होने वाले बम धमाके के सिलसिले में पुलिस ने कश्मीर के दो लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए रिहा कर दिया गया, क्योंकि उनके पास यूआईडी कार्ड था. ऐसे में तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एवं म्यांमार जैसे किसी भी दूसरे देश का नागरिक बड़ी आसानी से यूआईडी कार्ड बनवा कर भारत विरोधी गतिविधियां चला सकता है और उस पर शक इसलिए नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास यूआईडी कार्ड है.

योजना आयोग की दलील है कि सरकार इस कार्ड द्वारा नागरिकों को यूनिक नंबर इसलिए देना चाहती है, ताकि कल्याणकारी योजनाओं का फ़ायदा उन तक भी पहुंच सके, जिनके पास अब तक कोई पहचान पत्र नहीं है. एक अनुमान के अनुसार, नामांकन के समय जो बायोमैट्रिक्स निशान (आंखों और उंगलियों के) लिए जाते हैं, वे देश के हर कोने में रहने वाले लोगों के लिए सफल नहीं हैं. मसलन, दूरदराज़ और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले ग़रीब लोगों में कुछ ऐसी बीमारियां पाई गईं, जिनकी वजह से उनकी उंगलियों या आंखों के निशान कंप्यूटर पर उतारे नहीं जा सके. फिर भला ऐसे लोगों को सरकार यह कार्ड कैसे जारी करेगी. सरकार का तर्क है कि यह कार्ड नागरिकता की पहचान के लिए जारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसका मक़सद हर व्यक्ति की पहचान स्थापित करना है. इसलिए यहां रहने वाले दूसरे देशों के लोगों को भी यह कार्ड जारी करने में कोई परेशानी नहीं है. सवाल यह है कि क्या सरकार के पास विदेशियों की पहचान के लिए मशीनरी नहीं है. जिन देशों से उनका रिश्ता है, वहां की सरकारों के पास ऐसा कोई तरीक़ा नहीं है, जिससे वे अपने नागरिकों को पहचान पत्र जारी कर सकें. हमारी सरकार पूरी दुनिया के लोगों के लिए पहचान पत्र बनाने का सिरदर्द क्यों मोल लेना चाहती है, क्या उसके पास और कोई काम नहीं है या उसके पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उन पैसों को कहां ख़र्च किया जाए. यह सवाल पैदा होना लाजिमी इसलिए है, क्योंकि सरकार यूआईडी योजना पर एक लाख 50 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च करने का मन बना चुकी है. सरकार को यह अधिकार भला किसने दिया कि वह इतनी बड़ी धनराशि एक ऐसे काम में ख़र्च कर दे, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका मक़सद साफ़ नहीं है.

भारत में करोड़ों लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, पर्याप्त संख्या में स्कूल-कॉलेज नहीं हैं, जहां देश के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें. सरकार को अगर पैसा ख़र्च करना है, तो उसे इन मूलभूत समस्याओं के निराकरण की दिशा में ख़र्च करना चाहिए, लेकिन नहीं, वह केवल कुछ निजी आईटी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है. अगर ग़ौर किया जाए तो यूआईडी कार्ड के नाम पर देश का ख़ज़ाना लूटा जा रहा है, क्योंकि इस कार्ड के बन जाने के बाद इसके प्रयोग के लिए सरकार को करोड़ों कंप्यूटर और स्कैनर ख़रीदने होंगे. ज़ाहिर है, इससे उन्हीं कंपनियों का फ़ायदा होगा, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती हैं. इस तरह देखा जाए तो कॉमनवेल्थ एवं टूजी स्पेक्ट्रम जैसे एक और बड़े घोटाले को अंजाम देने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया के ख़िलाफ़ जांच होनी चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने न केवल संसदीय सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, बल्कि निजी कंपनियों को यहां के नागरिकों की व्यक्तिगत सूचनाएं अवैध तरीके से इकट्ठा करने का अधिकार दे दिया है और यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है.

बड़े आश्चर्य की बात है कि नंदन नीलेकणी के कार्यालय से आरटीआई के तहत जब यह सवाल पूछा जाता है कि यूआईडी कार्ड बनाने का ठेका जिन कंपनियों को दिया गया है, वह किस देश की हैं तो जवाब मिलता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी यूआईडीएआई इन कंपनियों के देशों के बारे में पता करने में नाकाम रही. इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए भी नीलेकणी के ख़िलाफ़ मुक़दमा दायर होना चाहिए. देश के लोग यह जानते हैं कि 19 जुलाई 2011 को यूआईडीएआई ने जिस एल1 आईडेंटिटी सोल्यूशंस को कार्ड बनाने का ठेका दिया था, उसे हाल ही में फ्रांस के सैफरन ग्रुप ने ख़रीद लिया है. इस कंपनी ने नई दिल्ली स्थित हिन्दुस्तान टाइम्स भवन में एक कार्यालय भी शुरू किया है. ऐसे में एक विदेशी कंपनी के साथ भारतीय नागरिकों के बारे में सारी जानकारियां साझा करना क्या देश की सुरक्षा के साथ ख़िलवाड़ नहीं है. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और शिक्षाविदों सहित प्रबुद्ध नागरिकों ने एक बयान में अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए यूआईडी जैसी पहचान प्रक्रियाओं पर रोक लगाने की मांग की थी.

tabrez@chauthiduniya.com

यह कार्ड ख़तरनाक है

चौथी दुनिया ने बहुत पहले जनता को इस कार्ड के बारे में चेता दिया था कि यूआईडी एक ऐसी योजना है, जिस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है. वह इसलिए, क्योंकि इस कार्ड का प्रयोग इतिहास के सबसे ख़तरनाक नरसंहार का कारण बन सकता है, क्योंकि यह कार्ड सरकार में भ्रम पैदा कर रहा है. इस कार्ड को बनाने वाली कंपनियों के तार विदेशी ख़ुफ़िया एजेंसियों से जुड़े हैं. इसे लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी ने देश के साथ-साथ सरकार को भी गुमराह किया. देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए यूआईडीएआई ने कार्ड बनाने के लिए तीन कंपनियों का चयन किया, जिनमें एसेंचर, महिंद्रा-सत्यम-माफो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन शामिल हैं. इन तीनों कंपनियों पर ग़ौर करते हैं तो डर सा लगता है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन का उदाहरण लेते हैं. इस कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं, जिनके रिश्ते अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी सीआईए और दूसरे सैन्य संगठनों से रहे हैं. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियों में से एक है, जो 25 देशों में फेस डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट आदि बेचती है. अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के सभी काम इसी कंपनी के पास हैं. यह पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक बनाकर देती है. इस कंपनी के डायरेक्टरों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है. इसके सीईओ ने 2006 में कहा था कि उन्होंने सीआईए के जॉर्ज टेनेट को कंपनी बोर्ड में शामिल किया है. जॉर्ज टेनेट सीआईए के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही इराक़ के ख़िलाफ झूठे सबूत इकट्ठा किए थे कि उसके पास महाविनाश के हथियार हैं. अब कंपनी की वेबसाइट पर उनका नाम नहीं है, लेकिन जिनका नाम है, उनमें से किसी का रिश्ता अमेरिका के आर्मी टेक्नोलॉजी साइंस बोर्ड, आर्म्ड फोर्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन, आर्मी नेशनल साइंस सेंटर एडवाइज़री बोर्ड और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसे संगठनों से रहा है. इसकी गहराई में जाएं तो पता चलता है कि इन सभी अधिकारियों के संबंध यहूदी संगठनों के साथ भी रहे हैं.

कांग्रेस हाईकमान इस राज्य में किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव मैदान में नहीं उतार रही है.

उत्तराखंड

कांग्रेस में गुटबंदी थम नहीं रही है

राजकुमार शर्मा

विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन पार्टी नेताओं को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है. कांग्रेस हाईकमान की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम सिद्ध हो रही हैं. इस गुटबाज़ी को कांग्रेस के पांच पांडवों में शुमार सांसद विजय बहुगुणा, हरीश रावत, सतपाल महाराज, नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत एवं यशपाल आर्य हवा दे रहे हैं. इन दिग्गजों में अभी से वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है और सभी के निशाने पर है सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी. इस चुनाव में जिस तरह कांग्रेसी दिग्गज शह और मात का खेल खेल रहे हैं, उसके मद्देनज़र राजनीति के जानकार मानते हैं कि इसका सीधा फ़ायदा भाजपा और बसपा को मिलेगा. इस खेल में पार्टी के भीतर नित्य नए समीकरण जन्म ले रहे हैं. केंद्रीय राज्यमंत्री हरीश रावत के विपरीत अब यशपाल आर्य, सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत एक दिखाई पड़ रहे हैं.

यह और बात है कि 2009 में लोकसभा चुनाव में हरिद्वार संसदीय सीट को कांग्रेस की झोली में डालने के बाद हरीश रावत का प्रभाव क्षेत्र कुमाऊं के साथ-साथ हरिद्वार तक बढ़ आया है और चुनाव से पहले पार्टी आलाकमान हरीश रावत को नज़रअंदाज़ करने की स्थिति में नहीं है. चुनाव के नतीज़े जो भी आएं, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज अभी से अपने हिसाब से पार्टी की अंदरूनी सियासी शतरंज में अपने प्यादों को मज़बूती से खड़ा करने की कोशिश में हैं. पार्टी के भीतर गुपचुप समझौते हो रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव समिति की पिछली बैठक में केंद्रीय मंत्री हरीश रावत का उठकर चले जाना पार्टी में वर्चस्व की जंग का संकेत है. सूत्रों की मानें तो मौजूदा वक़्त में कांग्रेस प्रदेश की सियासत को इस तरह देख रही है, जैसे सत्ता का फल उसकी ही झोली में गिरना है, लेकिन यह मात्र उसका दिवास्वप्न सिद्ध होगा. पार्टी के सभी कद्दावर नेता उन दावेदारों को टिकट दिलाना चाहते हैं, जो चुनाव जीतने की सूरत में उनके साथ खम ठोंककर खड़े हो सकें और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका दावा पुख्ता हो सके.

इस गुटबाज़ी को कांग्रेस के पांच पांडवों में शुमार सांसद विजय बहुगुणा, हरीश रावत, सतपाल महाराज, नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत एवं यशपाल आर्य हवा दे रहे हैं. इन दिग्गजों में अभी से वर्चस्व की जंग शुरू हो गई है और सभी के निशाने पर है सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी. इस चुनाव में जिस तरह कांग्रेसी दिग्गज शह और मात का खेल खेल रहे हैं, उसके मद्देनज़र राजनीति के जानकार मानते हैं कि इसका सीधा फ़ायदा भाजपा और बसपा को मिलेगा.

कांग्रेस हाईकमान इस राज्य में किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव मैदान में नहीं उतार रही है. कांग्रेस में जबसे अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर दावा ठोंकने वाले विधायकों को सिटिंग विधायक मानने पर बहस शुरू हुई है और दिग्गजों के पलायन के मामले ने तूल पकड़ा है, सतपाल महाराज और डॉ. हरक सिंह रावत काफी क़रीब आ गए हैं. उनके बीच छत्तीस का आंकड़ा एक और एक ग्यारह का आंकड़ा बन गया है. इस तरह पार्टी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य, सतपाल महाराज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत की एक तिकड़ी बन गई है. वजह यह मानी जा रही है कि यशपाल आर्य, सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत एवं नेता प्रतिपक्ष डॉ. हरक सिंह रावत बाजपुर, रामनगर और डोईवाला से पार्टी टिकट के लिए जोर लगा रहे हैं और पलायन का सवाल एक तरह से उन्हीं पर चला तीर है. वैसे इस तीर ने वंश परंपरा के पोषक हरीश रावत को भी चोटिल किया है, जो अपने पुत्र आनंद रावत को हरिद्वार सीट से लड़ाना चाहते थे.

उत्तराखंड	
कुल सीटें	70
भाजपा	34
कांग्रेस	21
बसपा	08
आईएनडी	03
अन्य	04

दूसरी ओर इस हमले ने तीनों दिग्गजों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है. सूत्रों की मानें तो इन नए समीकरणों के बीच पार्टी सीधे-सीधे हरीश रावत, यशपाल आर्य और विजय बहुगुणा के खेमों में बंटी दिखाई दे रही है. यह बात और है कि पार्टी के कई कार्यक्रमों में ये सभी नेता एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं. राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में इन दिनों वही स्थितियां हैं, जो 2009 में भाजपा में थीं. माना जाता है कि 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा संगठन में हरीश रावत जैसी पकड़ रखने वाले भगत सिंह कोश्यारी लगभग किनारे कर दिए गए थे, जिसका असर चुनाव परिणामों पर पड़ा और भाजपा के हाथों से पांचों लोकसभा सीटें जाती रहीं. सियासी दांव-पेंच के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान इस बात को बख़ूबी समझता है, इसलिए वह टिकट बंटवारे के समय हरीश रावत फैक्टर को नज़रअंदाज़ नहीं कर पाएगा. चुनाव से पहले ही लोग मांग करने लगे हैं कि राज्य में अगर कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो मुख्यमंत्री किसी सांसद को न बनाकर चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों में से ही बनाया जाए. समय से पूर्व उठी इस मांग ने तीनों सांसदों के पर कतर दिए हैं, वहीं इससे यशपाल आर्य और डॉ. हरक सिंह रावत की बांछें खिल उठी हैं.

भाजपा ने पलटी मारकर जिस तरह बी सी खंडूरी के हाथों चुनाव की कमान दे दी है, उससे इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कथित दाग़ी निशंक को हटाते ही भाजपा का ग्राफ बेहतर हो रहा है. बसपा का हाथी पहले से ही हरिद्वार में अपना कौशल दिखा चुका है. भाजपा और कांग्रेस के दिग्गजों की आपसी जंग के चलते अगर बसपा का हाथी पहाड़ पर चढ़ जाए तो किसी को इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए. दिग्गजों की आपसी कलह इस बात का संकेत दे रही है कि भविष्य में इस राज्य की सत्ता के ताले की चाबी बसपा के हाथों में होगी. बसपा के हाथी को पहाड़ पर चढ़ने से रोकने के लिए ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन की कमान दलित नेता यशपाल आर्य को सौंपी थी और इस चुनाव में भी आर्य को ऊंची जाति बाहुल्य वाले प्रदेश में अग्रिम पंक्ति में रखना एक खास संकेत है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया... प्रणव दा को ईनाम

राजधानी दिल्ली के लाखों किराएदारों एवं दुकानदारों पर किराए का बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार जल्द ही नया किराया क़ानून लागू कर सकती है.

किराएदारों में ख़ौफ़

दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर माफ़िया बन गए हैं

महानगरों का मिजाज़ भी अजीब होता है. यहां हर चीज़ किराए की है. कोख, संबंध और मकान भी. छोटे शहरों से आए किसी आदमी से पूछिए कि दिल्ली में एक अदद मकान ढूंढ पाने का दर्द क्या होता है? मकान मालिक सीधा आपको मकान नहीं देगा, क्योंकि उसे भरोसा नहीं है. मज़बूरन प्रॉपर्टी डीलरों की शरण में जाना पड़ता है. प्रॉपर्टी डीलरों का रवैया कुछ ऐसा है, मानों आप किसी लुटेरे से बात कर रहे हों. तुर्रा यह कि ज्यादातर प्रॉपर्टी डीलर रजिस्टर्ड नहीं हैं. लूट के इस खेल में सब शामिल है. सिवाय उस आम आदमी के, जिसे महानगर में रहने की क़ीमत चुकानी पड़ती है.

अभिषेक रंजन सिंह

ज़िंदगी जीने और सिर छुपाने के लिए एक अदद छत की ज़रूरत होती है, लेकिन अमूमन छोटे शहरों की तरह आसानी से मिलने वाली किराए की छत को दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलरों की नज़र लग गई है. तक़रीबन डेढ़ दशक पहले राजधानी दिल्ली में भी निजी पहचान के ज़रिए अथवा ख़ुद सीधे मकान मालिक से संपर्क करके लोग किराए के घर में रहते थे, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है. दिल्ली में किराएदार और गृहस्वामी के बीच प्रॉपर्टी डीलर नामक एक ऐसा तत्व आ गया है, जिसने दोनों के बीच का संबंध ख़त्म कर दिया है. प्रॉपर्टी डीलरों का यह जाल राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में फैल चुका है. अब किसी ज़रूरतमंद को बग़ैर किसी प्रॉपर्टी डीलर की मनुहार किए मकान नहीं मिल सकता. दिल्ली में कुल नौ ज़िले हैं. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की आबादी 1,38,50,507 है. ज़ाहिर है, यहां लाखों लोग किराए के मकान में रहते हैं. पूरी दिल्ली में कई इलाक़े ऐसे हैं, जहां हर वर्ग के लोग रहते हैं. मसलन, दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका, बेर सराय, कटवारिया सराय, हौज़खास और मालवीय नगर जैसी कॉलोनियों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हज़ारों छात्र-छात्राएं रहते हैं. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय जनसंचार संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे शिक्षण संस्थान यहीं स्थित हैं. इसी तरह प्रशासनिक एवं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा उत्तरी दिल्ली स्थित मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, आउट्रम लाइन, हडसन लेन, मॉल रोड, किंग्सवे कैंप, विजय नगर और हक़ीक़त नगर जैसे इलाक़ों में रहते हैं. ये इलाक़े दिल्ली विश्वविद्यालय के नज़दीक हैं, लिहाज़ा बेहतर पढ़ाई की उम्मीद लिए देश के अलग-अलग राज्यों से हर साल हज़ारों छात्र यहां आते हैं. चार्टर्ड एकांउटेंसी एवं बैंकिंग सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा और नौकरीपेशा लोग पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, शकरपुर, पांडव नगर, पटपड़गंज, विनोद नगर और गणेश नगर में रहते हैं. इसी तरह पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर, जनकपुरी, नवादा और विकासपुरी जैसे इलाक़ों में बड़ी संख्या में प्रवासी मज़दूर रहते हैं. यहां हर गली-मोहल्ले में चंद क़दमों की दूरी पर ढेरों प्रॉपर्टी डीलरों के साइन बोर्ड दिखेंगे, जिसमें फ्लैट ही फ्लैट और कमरे ही कमरे जैसे स्लोगन लिखे होते हैं. इन इलाक़ों में प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन की मोटी रक़म दिए बिना किराए का कमरा खोजना भूसे में सुई ढूंढने जैसा है. मुखर्जी नगर, मुनिरका, बेरसराय, पांडव नगर, लक्ष्मी नगर जैसे इलाक़ों में, जहां छात्रों की बहुतायत है, एक रूम सेट का किराया 6 हज़ार से लेकर 7 हज़ार रुपये के बीच है, बिजली और पानी का बिल अलग से. इसके अलावा किराएदार को एक महीने का पूरा कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को देना अनिवार्य है. अगर आपको इन इलाक़ों में किराए का मकान चाहिए तो पहले महीने का पूरा ख़र्च 12-15 हज़ार रुपये के बीच आएगा. मुखर्जी नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे रंजीत का कहना है कि पहले इस इलाक़े में कपड़े पर प्रेस करने वाले और चाय बेचने वाले दुकानदार भी खाली मकानों का ठिकाना बता देते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहां प्रॉपर्टी डीलरों का ख़ौफ़ इतना बढ़ चुका है कि ये ग़रीब लोग चाहते हुए भी छात्रों की मदद नहीं कर पाते. मॉल रोड में रहने वाले छात्र आकाश का कहना है कि यहां काफी छोटे कमरे का भी किराया हज़ारों रुपये है. इसी तरह साउथ दिल्ली के मुनिरका में रहने वाले हिमांशु ने बताया कि पांच साल पहले मुनिरका में प्रॉपर्टी डीलरों का कोई ख़ास दखल नहीं था, लेकिन अब यहां भी दर्जनों प्रॉपर्टी डीलरों ने अपनी दुकानें सज़ा रखी हैं. अमित नामक छात्र ने बताया कि यहां मकान मालिकों का व्यवहार इस क़दर ख़राब है कि अगर कमरे पर किसी का दोस्त रात में आ जाए तो उन्हें बेहद नागवार गुजरता है. कभी-कभी तो मकान मालिक किराएदार के साथ अभद्र बर्ताव भी करते हैं. दरअसल, यह आपबीती दिल्ली में रहने वाले हज़ारों किराएदारों की है, जो अपमान सहकर भी कुछ नहीं कह पाते. ज़रा सोचिए उस परिवार के बारे में, जिसकी आमदनी 10-12 हज़ार रुपये के बीच है, क्या वह कभी अपना घर बना सकता है. यही वजह है कि दिल्ली आने के बाद कई युवा काफी उम्र के बाद शादी करते हैं. कई लोग ऊंची मंजिल की चाहत में अविवाहित जीवन व्यतीत करने लगते हैं, जबकि कई लोग शादी के बाद अपनी पत्नी को गांव में रखते हैं. जो ऐसा नहीं कर पाते, वह अपने ख्वाबों को कुचल कर दिल्ली को अलविदा कह देते हैं.

दरअसल, वर्ष 1990 के बाद राजधानी दिल्ली में शिक्षा और रोज़गार के लिए देश के दूसरे शहरों से काफी तादाद में लोगों का आगमन हुआ. यह सिलसिला आज भी जारी है. सवाल यह है कि दिल्ली के हर गली-कूचे में मौजूद प्रॉपर्टी डीलरों पर क्या सरकार की कोई नज़र है अथवा नहीं. किराएदारों को स्थानीय पुलिस थाने में अपना सत्यापन (वेरीफिकेशन) कराना पड़ता है. क्या दिल्ली सरकार और पुलिस ने कभी किराए का मकान दिलाने के नाम पर चांदी काट रहे किसी प्रॉपर्टी डीलर की कोई जांच की कि उसने जो दुकान खोल रखी है, क्या वह पंजीकृत है. चौथी दुनिया ने जब इन इलाक़ों में जाकर देखा तो कहीं भी किसी प्रॉपर्टी डीलर ने साइन बोर्ड पर अपना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा था. दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट जितेंद्र मेहता का कहना है कि राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में आज हज़ारों की संख्या में प्रॉपर्टी डीलर अपनी दुकानें चला रहे हैं, जो अपंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली सरकार इनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दे तो उसके राजस्व में भी वृद्धि होगी. एडवोकेट मेहता ने कहा कि दिल्ली सरकार किराया क़ानून में संशोधन करके उसे जनसुलभ बनाए. आज राजधानी दिल्ली में मकान का किराया सेंसेक्स की तरह छलांग मार रहा है. फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि इसमें कभी गिरावट नहीं आती, क्योंकि मकान मालिकों और प्रॉपर्टी डीलरों का लालच ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है. वे हर वर्ष किराए में 15 से 18 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी कर रहे हैं. मकान मालिक और किराएदार के बीच 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है. यह अवधि बीतने के बाद मकान मालिक कोई न कोई तरकीब लगाकर मकान खाली करा लेते हैं और उसे ज़्यादा किराए पर चढ़ा देते हैं. प्रवासी किराएदार कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, इससे मकान मालिकों को कोई मतलब नहीं. अपने घर से दूर रहने वाले किराएदार से मकान मालिक और प्रॉपर्टी डीलर का कोई मानवीय रिश्ता नहीं है, उसे तो केवल हर महीने की सात तारीख़ तक एकमुश्त किराया चाहिए. अगर किसी किराएदार की तबियत ख़राब हो जाए या किसी महीने उसका हाथ तंग हो तो भी गृहस्वामी उस पर कोई रहम नहीं करते. किसी कारणवश किराएदार को 2-3 महीने के लिए घर जाना पड़े और इस बीच अगर वह किराया नहीं देता है तो कई मकान मालिक प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर उसका सामान बेचकर किराए की राशि वसूल लेते हैं. ऐसे कई मामले सामने आए हैं. अगर नोएडा एवं आनंद विहार की बात करें तो यहां हालत और भी ज़्यादा ख़राब है. यहां मेट्रो की सुविधा होने के चलते मकान मालिकों ने किराए में अनुचित बढ़ोत्तरी कर दी है.

किराया बढ़ने के मुख्य कारण

राजधानी दिल्ली के लाखों किराएदारों एवं दुकानदारों पर किराए का बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि सरकार जल्द ही नया किराया क़ानून लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह तय है कि प्रवासी लोगों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. ग़ौरतलब है कि वर्तमान में जो किराया नियंत्रण क़ानून लागू है, वह लोगों को कोई राहत नहीं पहुंचा रहा है. जानकारों की मानें तो किराया बढ़ने के पीछे एक अहम वजह यह किराया नियंत्रण क़ानून भी है, जिसे किराए की दरें संतुलित रखने के लिए बनाया गया था. राजधानी दिल्ली में किराया बढ़ने के लिए दूसरा बड़ा कसूरवार है डीडीए यानी देल्ही डेवलपमेंट अथॉरिटी. इसका काम है मकानों का निर्माण और आवंटन, लेकिन यह जिस चाल से फ्लैट-भवन का निर्माण कर रहा है, उसे देखते हुए आम लोगों का अपने घर का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा. तीसरी बड़ी वजह है कॉलोनियों को अवैध बनाए रखने की सरकारी प्रवृत्ति. दिल्ली में जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो राजनीतिक दल दावा करते हैं कि वे सत्ता में आने के बाद दिल्ली की सैकड़ों अनाधिकृत कॉलोनियों को वैधता प्रदान करेंगे, लेकिन चुनाव समाप्ति और सत्ता हासिल होने के बाद नेताओं को अनाधिकृत कॉलोनियों की याद नहीं आती. हैरान करने वाला सवाल यह है कि अगर ये कॉलोनियां आज वैध हो सकती हैं तो कल तक अनाधिकृत क्यों थी? वजह साफ है, सरकार और नौकरशाह कभी चाहते ही नहीं है कि राजधानी में ऐसी बस्तियां नियमित हों, क्योंकि अगर उन्हें वैधता मिल जाएगी तो वहां रहने वाले लाखों लोगों को सभी बुनियादी सुविधाएं देनी होंगी, जिसके वे हक़दार हैं.

arsingh@chauthiduniya.com

प्रॉपर्टी डीलरों को राजनीतिक संरक्षण

दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलरों की संख्या हज़ारों में है. इसकी संभावना बहुत कम है कि दिल्ली सरकार को इनकी वास्तविक संख्या पता हो. साल दर साल इनकी संख्या बढ़ रही है, उसी तरह दिल्ली में रहने वाले किराएदारों की मुसीबतें भी बढ़ रही हैं. गली-मोहल्लों में एक छोटे से कमरे में प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करने वाले ज़्यादातर वे लोग हैं, जो दादागिरी के लिए जाने जाते हैं. धीरे-धीरे इनका संपर्क राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं से हो जाता है. नेताओं का संरक्षण मिलने के बाद ये पूरी तरह निरंकुश होकर किराएदारों के साथ मनमानी करते हैं. इनका ख़ौफ़ इस क़दर है कि कई इलाक़ों में मकान मालिक बग़ैर इनसे पूछे किसी को मकान नहीं देते. ये प्रॉपर्टी डीलर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावों में नेताओं के लिए बहुत कारगार साबित होते हैं. राजनीतिक पार्टियों के लिए इन प्रॉपर्टी डीलरों की कितनी अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप चुनाव के समय लगा सकते हैं, जब इनकी दुकान-घर पर नेताओं का तांता लगा रहता है.

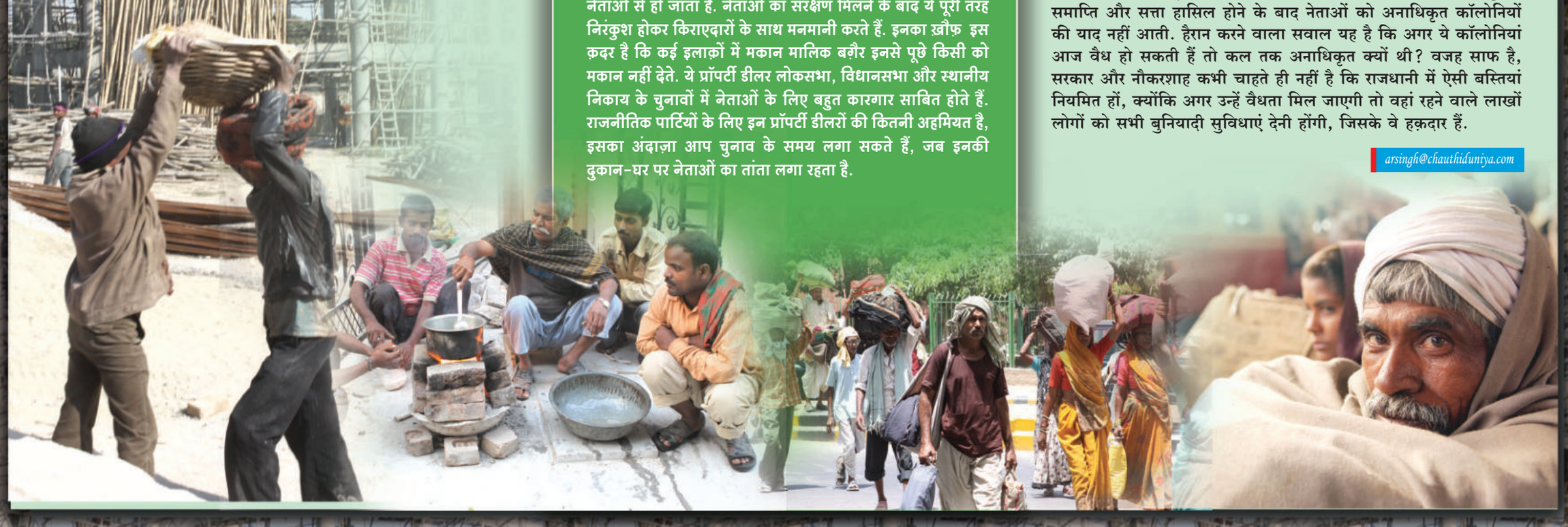

भारतीय नागरिक चुपचाप सहन कर लेगा, उसकी हिम्मत पुलिस विभाग में जाकर पुकारने की सहज में नहीं होगी.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

भ्रष्टाचार बनाम परपीड़न

भारत में सरकारी ऑफिसरों का, नीचे से ऊपर तक सब ही का, नैतिक स्तर काफी गिरा हुआ है. उसको सुधारने में अभी काफी समय लगेगा. पर जब तक यह नहीं होता, समान वित्त वितरण की योजना रुक नहीं सकती. अतएव क़ानून वालों को सोच-समझ कर ऐसे क़ानून बनाने चाहिए, जिनका प्रतिपालन बिना किसी कठिनाई के किया जा सके और शासन के कर्मचारी जिनका पालन कराने में भ्रष्टाचार या परपीड़न का रास्ता न अपना पाएं. ऐसे अनेक क़ानून बन सकते हैं.

आज से 500 वर्ष पूर्व पाश्चात्य विद्वान श्री सर्वांते ने एक उपन्यास डॉन क्वीग्जोट लिखा था. यह पुस्तक हास्यरस के प्रतीक एक महामूर्ख की कहानी है. डॉन क्वीग्जोट अपने सेवक सांको पांजा को उपदेश देता हुआ कहता है कि जिस शासन में कायदे क़ानून इतने ज़्यादा बनाए जाते हों कि यह जानने का अवकाश ही न मिले कि इनका पालन हो रहा है या नहीं, उस राज्य से अराजकता कहीं ज़्यादा अच्छी है. भारत में कई ऐसे क़ानून-पुंज मौजूद हैं, जो सिर्फ़ किताबों में बंद पड़े हैं. उनको प्रजा मानती रहे तो कोई श्रेय नहीं, उल्लंघन करे तो कोई दंड नहीं. ऐसे क़ानून बनाने से लाभ ही क्या?

क़ानून चाहे कम से कम बनें, पर उनका पालन जनता द्वारा बराबर हो, यह देखना शासन का उतना ही कर्तव्य है, जितना क़ानून बनाना. पर लगता है, शासन अभी तक क़ानून बनाने में ही विश्वास करता है, उसके पालन की संभवत: उसे उतनी परवाह नहीं. जनता को क़ानून पालन में प्रवृत्त रखने का जो साधन शासन के पास है, वह है पुलिस विभाग या यदि कहीं मामला ज़्यादा गंभीर बन जाए तो सैनिक विभाग.

क़ानून चाहे कम से कम बनें, पर उनका पालन जनता द्वारा बराबर हो, यह देखना शासन का उतना ही कर्तव्य है, जितना क़ानून बनाना. पर लगता है, शासन अभी तक क़ानून बनाने में ही विश्वास करता है, उसके पालन की संभवत: उसे उतनी परवाह नहीं. जनता को क़ानून पालन में प्रवृत्त रखने का जो साधन शासन के पास है, वह है पुलिस विभाग या यदि कहीं मामला ज़्यादा गंभीर बन जाए तो सैनिक विभाग. पुलिस तो इस तरह से बदनाम है कि कोई भी भला आदमी उसके पास रपट या डायरी लिखाने जाने तक से डरता है, चाहे उसकी बहुमूल्य वस्तु चोरी चली गई हो, चाहे उसकी इज़्ज़त या अस्मत पर गुंडे हाथ डाल रहे हों.

भारतीय नागरिक चुपचाप सहन कर लेगा, उसकी हिम्मत पुलिस विभाग में जाकर पुकारने की सहज में नहीं होगी. ऐसा क्यों? कारण स्पष्ट है, अगर पुलिस के पास वह जाए तो पहले तो वे उसकी रही-सही संपत्ति या आबरू उतारने से बाज नहीं आएंगे और कहीं बच जाए तो फिर वही पूंजीवादी ज़हर इस तरह से फैला हुआ है कि बिना पूंजी के जोर से उसको कुछ भी राहत या न्याय मिले, यह संभव ही नहीं है.

जब ऐसी दशा है तो समान वित्त वितरण कैसे सफल होगा, यह प्रश्न और अधिक गंभीर हो जाता है. अगर क़ानून द्वारा कर्मचारियों के लिए कर्तव्य पालन निश्चित कर दिया जाए और कर्मच्युत होने वाले कर्मचारियों को भारी से भारी सज़ा सहज ही और तत्काल दी जा सके तो शायद स्थिति सुधर सकती है. शासन के कर्मचारियों का नैतिक स्तर सुधारना लाज़िमी है. क़ानून का प्रतिपालन कराना अत्यंत आवश्यक है. क़ानून बनाने से पहले उसमें आने वाली सारी कठिनाइयों का अध्ययन अच्छी तरह होना ही चाहिए और एक बार क़ानून बन जाने पर उसके पालन में भेदभाव की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए. आज स्थिति ऐसी है कि क़ानून एक है, पर उसका प्रवर्तन करोड़पति सेठ के लिए जिस ढंग का है, आम जनता के लिए उससे भिन्न ढंग का है. इस विषम परिस्थिति को मिटाने के लिए अन्य क़ानून अपेक्षित हैं.

feedback@chauthiduniya.com

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

कमल मोरारका का ब्लॉग

www.kamalmorarka.com

नई संसद लोकपाल बिल पास करे

एक बार फिर लोकपाल विधेयक को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. मानों यह एक पहेली बन गया हो. पहले सरकार को खुदरा बाज़ार में एफडीआई पर पीछे लौटना पड़ा और अब लगता है कि उसे पेंशन और कंपनी बिल के मामलों में भी ऐसा ही करना पड़ेगा. ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ख़ुद अपने ही निर्णय में उलझ गई हो, कैद हो गई हो. यह इस देश के लिए अच्छा नहीं है. इसे एक अच्छा शगुन नहीं माना जा सकता है. हर समय यह ज़रूरी है कि देश में एक प्रभावशाली सरकार हो, वह प्रभावी ढंग से काम करे, ताकि देश में अराजकता का माहौल न बने. टीम अन्ना अपनी मांगें रख सकती है, धरना दे सकती है, प्रदर्शन कर सकती है, जेल भरो आंदोलन चला सकती है, रैली कर सकती है. देश में अराजकता न फैले, यह देखने और रोकने की ज़िम्मेदारी टीम अन्ना की नहीं है. सरकार अन्ना को संतुष्ट करने के लिए बहुत कुछ कर चुकी है और बहुत कोशिश भी कर चुकी है. ऐसी स्थिति एक उत्तरदायी और कार्यशील लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है.

कोई आदमी इस स्थिति में काम नहीं कर सकता और न एक ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है, जो यह कहे कि वह एक मज़बूत लोकपाल के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है. टीम अन्ना द्वारा डेडलाइन दिए जाने से सिर्फ़ दबाव बढ़ा है, न कि यह एक अच्छा निर्णय कर पाने में सहायक साबित हुआ. अन्ना ने जब अपना अभियान शुरू किया और उसके बाद इतने महीने बीत गए, तब क्या किया जा सकता है? सच तो यह है कि एक अच्छे लोकतंत्र में इसका सही जवाब है, चुनाव. जनता को अपना नया प्रतिनिधि चुनना चाहिए, जो उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतर सके, बेहतर काम कर सके. यदि अन्ना राजनीति में न भी कूदना चाहें तो ऐसे लोग, जो अन्ना के समर्थक हैं, वे एक अपनी पार्टी बनाकर या व्यक्तिगत रूप से चुनाव मैदान में जा सकते हैं.

यदि 25 युवा भी, जो किसी वर्तमान पार्टी से संबद्ध न हों, चुनाव जीतकर संसद में पहुंच जाएं तो एक बड़ा बदलाव हो सकता है. अभी सारे सांसद एक लिखी हुई पटकथा के मुताबिक़ संसद में बोलते हैं. बहुत कम ही सांसद अपनी व्यक्तिगत भावना को संसद में रख पाते हैं. लगभग सभी सांसद अपनी पार्टी की राय को ही संसद में रखते हैं. ज़ाहिर है, ऐसे में युवा अन्ना के समर्थन से चुनाव लड़ें. नई समस्याओं के लिए नए समाधान की ज़रूरत होती है. ऐसे लोग, जो अन्ना का समर्थन कर रहे हैं, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाकर चुनाव का आह्वान करें, कोई बड़ा वायदा न करें. सरकार पर इस बात का दबाव बनाना चाहिए कि वह संसद भंग करे, नया चुनाव हो और तब तक लोकपाल बिल पर कुछ न हो. नई संसद ही इस बिल को देखे और पास करे.

कोई आदमी इस स्थिति में काम नहीं कर सकता और न एक ऐसा प्रधानमंत्री हो सकता है, जो यह कहे कि वह एक मज़बूत लोकपाल के लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है. टीम अन्ना द्वारा डेडलाइन दिए जाने से सिर्फ़ दबाव बढ़ा है, न कि यह एक अच्छा निर्णय कर पाने में सहायक साबित हुआ. अन्ना ने जब अपना अभियान शुरू किया और उसके बाद इतने महीने बीत गए, तब क्या किया जा सकता है? सच तो यह है कि एक अच्छे लोकतंत्र में इसका सही जवाब है, चुनाव. जनता को अपना नया प्रतिनिधि चुनना चाहिए, जो उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतर सके, बेहतर काम कर सके.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

भ्रष्टाचार मनुष्य की प्रवृत्ति में शामिल है

क्या हम सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो? शायद नहीं. सच तो यह है कि भ्रष्टाचार मनुष्य की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है. अंतर केवल इतना है कि किसी में कम है और किसी में ज़्यादा. भ्रष्टाचार भी दो तरह का होता है. एक वह, जो हमें मजबूरी में करना पड़ता है और दूसरा वह, जो हम अपनी पसंद और ख़ुशी से करते हैं. पहले में हमें किसी काम के लिए मजबूरन सरकारी बाबू को रिश्वत देनी पड़ती है. दूसरे में हमें कोई फ़ैसला अपने पक्ष में कराने के लिए जज या किसी अन्य आला अधिकारी को रिश्वत देनी पड़ती है. यह रिश्वत हम ख़ुद देते हैं. भ्रष्टाचार में हम उस रिश्वत की बात तो करते हैं, जो हमसे जबरन ली जाती है, लेकिन उसकी बात नहीं उठाते, जो हम अपनी ख़ुशी से देते हैं. होना तो यह चाहिए कि भ्रष्टाचार के इन दोनों पहलुओं पर चर्चा हो.

सुनीत गोस्वामी, *आगरा, उत्तर प्रदेश.*

भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म होगा

अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कोई रथयात्रा निकाल रहा है तो कोई भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कर रहा है, लेकिन यह घोषणा कोई नहीं कर रहा है कि भ्रष्टाचारियों और दाग़ी लोगों को अपना उम्मीदवार नहीं बनाएंगे. सवाल उठता है कि जब हमारे प्रतिनिधि ही भ्रष्टाचारी होंगे तो वह भ्रष्टाचार मुक्त शासन कैसे दे सकते हैं. राजनीतिक दलों को ईमानदारी से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रयास करने चाहिए.

अवनीश शुक्ल, *गोंडा, उत्तर प्रदेश.*

सेंसर बोर्ड ध्यान दे

सिनेमा किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति का आईना होता है. भारत में सिनेमा देखने वालों में एक बड़ा वर्ग ग्रामीण लोगों का है, लेकिन आएदिन बन रहीं रागिनी एमएमएस और डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों ने हमारे समाज को नुक़सान ही पहुंचाया है. कहानी के नाम पर फिल्मों में अश्लीलता परोसना कहां तक उचित है. ऐसी फिल्मों से जुड़े कलाकारों के बयान को समझा जा सकता है, क्योंकि उनके लिए उनका करियर और पैसा ही सब कुछ है. सेंसर बोर्ड को यह समझना चाहिए कि पश्चिमी देशों की तर्ज़ पर ऐसा खुलापन हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है. इसलिए ऐसी फिल्मों पर रोक लगाई जानी चाहिए.

विजय कुमार आज़ाद, *बिहार.*

चौथी दुनिया निर्भीकता का प्रतीक

चौथी दुनिया पत्रकारिता के क्षेत्र में एक मिसाल पेश कर रहा है. चमकता रंगीन अख़बार स्तरीय सामग्री से भरपूर है. साथ ही यह निर्भीक और विश्वसनीय पत्रकारिता का प्रतीक है. मां गंगा से आपकी उन्नति की प्रार्थना करता हूं.

-डॉ. रवि रस्तोगी, *देहरादून, उत्तराखंड.*

जाड़ा

जाड़े का रुतबा देखि-देखि
भक्तिन चाची घबराती हैं,
एक लोटा पानी लइके
चम्मच से नहाती हैं,
गर्मी के सीजन मा चाची
तनिकौ न डेरात रहीं
भदइ की गंगा धारा अस
हर-हर-हर नहाति रहीं,
नामी पंडित बांके चाचा
जाड़ा देखि के कांप गए,
पहुड़े-पहुड़े खटिया पै
दर्जन भय पूड़ी चांप गए,
हीलत-डोलत ऐसे जैसे
आय गवा भूकंप,
चिल्लाते हैं जोर-जोर
मचावत हैं हड़कंप.

-आनंद फ़ैज़ाबादी

अख़बार पसंद आया

चौथी दुनिया का नियमित पाठक हूं. आपके अख़बार की जितनी प्रशंसा की जाए, कम है, क्योंकि इसमें निर्भीकता एवं पारदर्शिता के साथ आलेख प्रकाशित किए जाते हैं. अधिकांश अख़बार विज्ञापन पत्र बनते जा रहे हैं और उनमें ऐसे समाचार प्रकाशित होते हैं, जो स्वनिर्मित लगते हैं.

आदित्य कुमार अवस्थी, *उत्तर प्रदेश.*

नएपन का एहसास

चौथी दुनिया के पाठकों की दुनिया स्तंभ में प्रकाशित कविताएं नएपन का एहसास कराती हैं. बहुत कम अख़बारों में कुछ अलग देखने को मिलता है. पुरस्कृत पत्र के लेखक को पुस्तकें देना अच्छा है. इससे जहां पाठकों में अच्छे पत्र लिखने की प्रवृत्ति पैदा होती है, वहीं अच्छे पत्र लिखने वालों को प्रोत्साहन मिलता है.

फ़ौज़िया परवीन, *दरियागंज, दिल्ली.*

राजकमल प्रकाशन समूह

चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.

राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

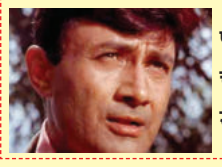

पचास के दशक में भारतीय सिनेमा में तीन नाम सबसे चर्चित रहे, दिलीप कुमार, राजकपूर और देव आनंद. उस समय के युवा इनमें अपनी छवि देखने का प्रयत्न करते थे.

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

वक़्त की नज़ाकत को समझने की ज़रूरत

अक्सर यह माना जाता है कि नियम बनाए जाते हैं और बनाते समय ही उसे तोड़ने के रास्ते भी बन जाते हैं. क़ानून बनाए जाते हैं और उनसे बचने का रास्ता भी उन्हीं में छोड़ दिया जाता है तथा इसी का सहारा लेकर अदालतों में वकील अपने मुल्जिम को छुड़ा ले जाते हैं. शायद इसीलिए बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि अपराधी बाहर घूमते हैं, जबकि बेगुनाह अंदर होते हैं. किसी ने दो सौ रुपये की चोरी की, वह जेल के अंदर और जिसने दो सौ करोड़ रुपये की चोरी की, वह जेल के बाहर, क्योंकि उसके लिए वकील रास्ते निकाल लेते हैं. दो सौ रुपये चोरी करने वाले के पास वकील को देने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए रास्ता नहीं निकल पाता.

लोकपाल बिल जिस तरह संसद में पेश हुआ, उससे ज़्यादा बेहतर था कि यह न पेश होता, क्योंकि उससे मुट्ठी बंद रहती और यह माना जाता कि कांग्रेस पार्टी अभी भ्रष्टाचार से लड़ने के रास्ते नहीं निकाल पाई, लेकिन उसने बिल पेश करके यह साबित कर दिया कि वह रास्ते निकालना ही नहीं चाहती. शायद यह बिल कांग्रेस की लीडरशिप का बिल नहीं है, यह भारत की नौकरशाही का बिल है. पूरी नौकरशाही एकजुट हो गई और उसने कांग्रेस के नेताओं या सरकार चलाने वालों को बता दिया कि वह किसी भी कीमत पर अन्ना हज़ारे द्वारा प्रस्तावित लोकपाल बिल को समर्थन नहीं देगी, क्योंकि इससे देश नहीं चलेगा. नौकरशाही का मानना है कि देश चलाने के लिए कई सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं, जो पहली नज़र में भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं. अगर वे काम न किए जाएं तो जिस तरह दुनिया चल रही है, हमारा उसके साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, विकास का पहिया रुक जाएगा. कांग्रेस लीडरशिप ने इस पर सहमति जता दी, क्योंकि कांग्रेस के लिए भ्रष्टाचार कभी मुद्दा था ही नहीं. उसके लिए छोटा भ्रष्टाचार तो मुद्दा है, लेकिन बड़ा भ्रष्टाचार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता. उसका मानना है कि देश चलाना है तो कुछ हद तक आंखों को बंद करना ज़रूरी है. लेकिन देश के लोग इससे कुछ अलग सोचते हैं. उनका मानना है कि अगर बड़े भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगेगी तो छोटा भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर नहीं रोका जा सकता है.

मुझे अच्छी तरह याद है, 1987–88 में जब बोफोर्स कांड सामने आया और यह खुलासा हुआ कि सात या साढ़े सात प्रतिशत कमीशन बोफोर्स ने हिंदुस्तान में मदद करने वालों को दिया और यह बात सामने आई कि सरकार में बड़े पदों पर बैठने वाले लोग उसमें हिस्सेदार थे तो उन दिनों बस कंडक्टर खुलेआम आम आदमी से टिकट के पैसे लेता था और चेंज वापस नहीं करता था. वह कहता था कि जब सात प्रतिशत ऊपर के लोग ले रहे हैं तो दस प्रतिशत का हमारा हक बनता है. लोग अचंभे से उसका चेहरा देखते थे और पैसे वापस लेने के लिए थोड़ी हील–हुज्जत होती थी, पर परिणाम यह होता था कि बाकी पैसे वापस नहीं मिलते थे. वहीं से हमारे देश में सात से दस प्रतिशत कमीशन लेने का मानों खुला चलन शुरू हो गया. अधिकारी, इंजीनियर और डॉक्टर बेशर्मी के साथ लोगों से पैसे मांगने लगे. जो भ्रष्टाचार पहले सिर्फ बड़े सरकारी महकमों तक सीमित था, छोटे महकमों में बहुत छोटे पैमाने पर होता था, जैसे अगर तारीख बढ़वानी है तो आप बीस रुपये का नोट पेशकार के सामने फेंक दीजिए तो तारीख बढ़ जाती थी, लेकिन अब वही भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि आज जब हम और आप बात कर रहे हैं, शायद कोई भी ऐसी जगह नहीं है, जहां पर बिना कुछ पैसे दिए फाइल आगे बढ़ सके या आपका काम हो सके.

बहुत सारे लोग ड्राइविंग लाइसेंस का उदाहरण देते हैं. कंप्यूटराइजेशन हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस जाने लगीं और कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लेकिन भ्रष्टाचार तो चौराहे पर आकर खड़ा हो गया. अधिकारी पास से गुजरते हैं और चौराहे पर खड़ा सिपाही सामने पैसे लेता है. मुंबई में तो रिश्वत लेने से रोकने पर एक वरिष्ठ अधिकारी को सिपाहियों ने ही पीट–पीटकर मार डाला, आग लगाकर उसे जला दिया. यह घटना बताती है कि हम अगर गंभीर नहीं होंगे, उच्च पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार से लड़ते दिखाई नहीं देंगे तो देश में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा. नतीजे के तौर पर अगर किसी को एप्लीकेशन जमा करानी है और कहीं उसका रिश्ता नौकरी से है तो वह एप्लीकेशन बिना पैसा दिए जमा नहीं हो सकती. जिस देश में यह हाल हो और वहां सरकार इतना कमजोर और लचर बिल लाए तो लोगों को लगता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ना ही नहीं चाहती. कांग्रेस के नेतृत्व में बनी सरकार को बड़े नौकरशाहों का दबाव झेलना पड़ सकता है. पर यहीं तो राजनीतिक इच्छाशक्ति की परीक्षा होती है. अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो तो ये सारे काम हो सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति न हो और आपको काम करना न आए तो फिर नौकरशाह आपके ऊपर हावी हो जाते हैं. जनता की नज़र में कांग्रेस भ्रष्टाचार से लड़ती दिखाई नहीं देती, इसके लिए वह उसे गुनाहगार मान रही है, लेकिन उसकी नज़र में बाकी राजनीतिक दल भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं हैं.

मुंबई में तो रिश्वत लेने से रोकने पर एक वरिष्ठ अधिकारी को सिपाहियों ने ही पीट-पीटकर मार डाला, आग लगाकर उसे जला दिया. यह घटना बताती है कि हम अगर गंभीर नहीं होंगे, उच्च पदों पर बैठे लोग भ्रष्टाचार से लड़ते दिखाई नहीं देंगे तो देश में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार कम नहीं होगा. नतीजे के तौर पर अगर किसी को एप्लीकेशन जमा करानी है और कहीं उसका रिश्ता नौकरी से है तो वह एप्लीकेशन बिना पैसा दिए जमा नहीं हो सकती.

लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे विरोध के स्वर सिर्फ़ रस्मी तौर पर निकल रहे हैं. उनके मन में यह बात घर कर रही है और मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है. इसलिए, क्योंकि हर जगह, जहां भी हम नज़र डालें, लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था से भरोसा उठता दिखाई दे रहा है. उन्हें लगता है कि राजा कोई भी हो, हमारी हालत यही रहने वाली है. हमें पिटना है, भूखों मरना है, बीमार रहना है, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी है. कुल मिलाकर आशा का माहौल ख़त्म हो रहा है. कांग्रेस पार्टी में अगर समझदार लोग हैं तो उन्हें इस स्थिति को आज समझना चाहिए. इसलिए, क्योंकि अगर वे अभी नहीं समझेंगे तो उनके बच्चों को आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी बातों के जवाब देने पड़ेंगे और अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो देश में उन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाएगा. एक अफ़सोस और है. आज देश में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, जो सभी राजनीतिक दलों से कह सके कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं. जो सत्ता में हैं उनसे न कहे, लेकिन जो विपक्ष में हैं उनसे तो कम से कम यह बात कहे. 120 करोड़ लोगों के देश में इस स्थिति पर सिवाय अफ़सोस जताने के और क्या किया जा सकता है. शायद यह इसलिए हो रहा है, क्योंकि राजनेताओं ने देश में माहौल ऐसा बना दिया है कि अच्छे लोग राजनीति में आने के बारे में सोचते ही नहीं हैं.

विडंबना यह है कि अन्ना हजारे और उनके साथी इस स्थिति में जनता को साथ नहीं लेना चाहते. उन्हें लगता है कि वे अनशन करेंगे और देश हमेशा की तरह उनके साथ खड़ा हो जाएगा. हो सकता है, खड़ा भी हो जाए, क्योंकि लोग किसी भी अवसर को अपने हाथ से अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाए बिना जाने नहीं देना चाहते. यह वह *सिटम* है, जिसे राजनीतिक तंत्र चलाने वालों को समझना चाहिए. अगर कहीं ऐसा वक़्त आ जाए कि लोग यही ताक़त लोकतांत्रिक दायरे से बाहर निकल कर दिखाने लगें तो? अन्ना हजारे की आज ज़्यादा ज़िम्मेदारी है. उन्हें सारे देश में घूमकर लोगों को इस स्थिति के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार करना चाहिए. आवाज़ अलोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक. लोगों को समझाना चाहिए कि तुम्हारी ताक़त क्या है, अपनी ताक़त से तुम सरकारें बदल सकते हों, सरकारें बना सकते हों. अगर सरकारें बदलनी हैं तो कैसे बदलनी हैं और सरकारें बनानी हैं तो कैसी बनानी हैं. यह देश गांधी के हिंद स्वराज के आधार पर चलेगा या वॉल स्ट्रीट की फिलॉसफी पर चलेगा. यह देश यहां रहने वालों के सपने पूरा करेगा या आईएमए एवं वर्ल्ड बैंक के सपनों को पूरा करने के लिए सारे देश को मानसिक तौर पर कुंद कर दिया जाएगा. सवाल बड़ा है, इसका जवाब भी बड़ा होगा. पर उस जवाब को अगर राजनीतिक दल नहीं तलाशते हैं और अन्ना हजारे भी इस जवाब को तलाशने नहीं निकलते हैं तो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाएगा, कहीं ऐसा न हो कि देश उसका समर्थन कर दे. ऐसे ही हालात जर्मनी में थे, जब हिटलर सामने आया था. हिटलर की किताब, उसकी आत्मकथा, उसका एक–एक वाक्य हिंदुस्तान में सही साबित होता दिखाई दे रहा है, जिनके सहारे उसने जर्मनी में लोगों को व्यवस्था के ख़िलाफ़ तैयार कर लिया था. आज का राजनीतिक तंत्र अगर इसे नहीं समझता है तो देश के नौजवानों को इस स्थिति को समझना होगा कि लोकतंत्र बहुत मुश्किल से मिलता है और उसे बनाए रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है.

लोकतंत्र या अधूरा लोकतंत्र भी अगर हाथ से जाने वाला हो तो कैसी छटपटाहट होती है, अगर इसे जानना हो तो पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखना चाहिए, जहां पूरी सरकार, उसका प्रधानमंत्री बिलबिला रहा है, तिलमिला रहा है और कह रहा है कि सेना हमारी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश कर रही है यानी लोकतंत्र को समाप्त करने की तैयारी पाकिस्तान में सेना द्वारा हो रही है. हमारे देश में पूरा लोकतंत्र है. यहां के नौजवानों को इसके पक्ष में खड़ा होना होगा, राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव बनाना होगा, अन्ना हजारे के ऊपर भी दबाव बनाना होगा कि इस तरीक़े से जनता नहीं खड़ी होती, सिर्फ़ उसका समर्थन मिलता है. जनता को खड़ा करने के लिए उसके बीच जाना होगा. ठीक उसी तरह, जैसे पानी गर्म करना है तो आपको उसे आंच के ऊपर रखना पड़ेगा, भले ही आंच लकड़ी की आग की हो, कोयले की आग की हो, गैस की आग की हो या सूरज की गर्मी की आग हो. बिना आग पर रखे पानी गर्म नहीं होगा. जनता का आंदोलन, लोकतंत्र को बनाए रखने और लोकतंत्र में रहने वालों के लिए खुशहाली लाने का एक ही तरीका है. वह यह कि जनता, उसका आंदोलन सशक्त हो और लोकतंत्र बना रहे. सभी लोगों को मजबूर करना कि वे जनता के हितों के लिए काम करें, न कि उनके पक्ष में, जो जनता का हित नहीं चाहते. हम एक बड़े संकट के मुहाने पर पहुंच गए हैं. काश कि मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, ए बी वर्धन, प्रकाश करात, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव एवं रामविलास पासवान इस सच्चाई को समझते. इनका न समझना प्रतीकात्मक तौर पर लोकतंत्र के लिए एक घने कोहरे जैसा है, जिसमें एक्सीडेंट हो सकता है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

देव आनंद और मारियो मिरांडा वैश्विक व्यक्तित्व थे

एक सप्ताह के भीतर भारत के दो बड़े कलाकारों देव आनंद और मारियो मिरांडा का निधन हो गया. दोनों अपने–अपने क्षेत्र के महारथी थे. दोनों का अपना रास्ता था, दोनों को लोगों का बहुत प्यार मिला और दोनों अद्वितीय प्रतिभा वाले थे. दोनों ने पचास के दशक में भरपूर नाम कमाया और लोगों का मनोरंजन किया. मुझे याद है, जब मैं बारह साल का था तो मैंने देव आनंद की फिल्म बाजी देखी थी. इसके बाद मैं उनकी हर फिल्म प्रथम दिन के प्रथम शो में देखता था. उस समय पांच आने और साढ़े दस आने का टिकट होता था. देव आनंद की फिल्म देखने के लिए लंबी कतार लगती थी. इसके बाद मैंने जाल, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, नौ दो ग्यारह एवं मिलाप आदि फिल्में देखीं. इसके अलावा मैंने दिलीप कुमार के साथ देव आनंद की एकमात्र बनी फिल्म इंसानियत देखी, जिसे देखने वाले कम लोग थे.

पचास के दशक में भारतीय सिनेमा में तीन नाम सबसे चर्चित रहे, दिलीप कुमार, राजकपूर और देव आनंद. उस समय के युवा इनमें अपनी छवि देखने का प्रयत्न करते थे. वे इनकी नकल करते थे, ताकि लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें. दिलीप कुमार ने कई तरह की भूमिकाएं निभाईं. उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले युवक से लेकर शहरी युवक तक की भूमिका फिल्मों में निभाई. वह ऐतिहासिक और आधुनिक समय की फिल्में भी करते थे. उनकी फिल्में नेहरू के समय की भारतीय राजनीति से संबंधित होती थीं. राजकपूर ने अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं. उनकी फिल्में वाम विचारधारा से संबंधित होती थीं. ख्वाजा अहमद अब्बास ने राजकपूर के लिए ऐसी फिल्में बनाईं. उनकी आवारा जैसी फिल्में सोवियत संघ में बहुत चर्चित रहीं.

इन दोनों से इतर देव आनंद की फिल्में अराजनीतिक होती थीं, लेकिन वह और उनके भाई इप्टा से आए थे, इस कारण उनके पास प्रगतिशील आइडिया होता था. देव आनंद ने हमेशा शहरी युवक की भूमिका निभाई, जो न्याय के लिए ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों से संघर्ष करता था. कृष्ण मेनन के 1957 के चुनाव में प्रचार के अलावा देव आनंद ने कभी किसी पार्टी के साथ काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने आपातकाल के समय विरोध किया था, जैसा कि वह अपनी फिल्मों में किया करते थे. उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिसमें बेबाकी से सारे विषयों पर चर्चा की. कहा जा सकता है कि आजादी के बाद किसी व्यक्ति ने, जिसका जनता के साथ जुड़ाव रहा, इतनी बेबाकी से अपने जीवन के अनुभवों को नहीं लिखा. उनसे मेरी अंतिम मुलाक़ात लंदन में हुई थी. वह उन लोगों में से थे, जो सारे संसार को अपना घर मानते हैं. वह जैसे मुंबई में रहते थे, ठीक उसी तरह लंदन में भी रहते थे. उनकी छवि मनोज कुमार की तरह ब्रिटिश विरोधी नहीं थी. वह लंदन में ब्रिटिश बनकर ही रहते थे. उनका अंतिम संस्कार ईसाई कब्रिस्तान में किया गया, लेकिन हिंदू रीति– रिवाज से. अंतिम समय में भी उन्होंने किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया.

मारियो मिरांडा वैसे दूसरे कलाकार थे, जिनकी मैं पचास के दशक में प्रशंसा करता था, लेकिन उन्हें पिछले दशक से जानने लगा. वह भी देव आनंद की तरह वैश्विक व्यक्ति थे. उनका अधिकांश समय भारत के गोवा में व्यतीत हुआ. वह जितने भारतीय थे, उतने ही पश्चिम के थे. गोवा की सबसे पुरानी पुर्तगीज बस्ती लोटीलुम में उनका घर था. उनके घर की दीवारें देशी–विदेशी पेंटिंग्स से भरी पड़ी रहती थीं. उनकी पत्नी हबीबा हैदराबाद की थीं, जो उन्हें वहां की तहजीब से वाक़िफ़ कराती रहती थीं. दोनों के पास विश्व के कोने–कोने से उनके दोस्त आते थे, जिनका वे स्वागत किया करते थे. पचास के दशक में वैश्विक विचार रखने वाले भारतीय थे, लेकिन धीरे–धीरे वे ख़त्म होते गए. इससे भारत को नुक़सान भी हुआ. उस समय भारत ग़रीब, लेकिन ख़ुश देश था. आज अमीर और वैश्वीकृत हो गया है. आज भी कई सितारे विदेश जाते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वे वहां घर जैसा अनुभव कर रहे हैं. अगर वे ऐसा कहेंगे तो कोई उनके ख़िलाफ़ पीआईएल दर्ज कर देगा.

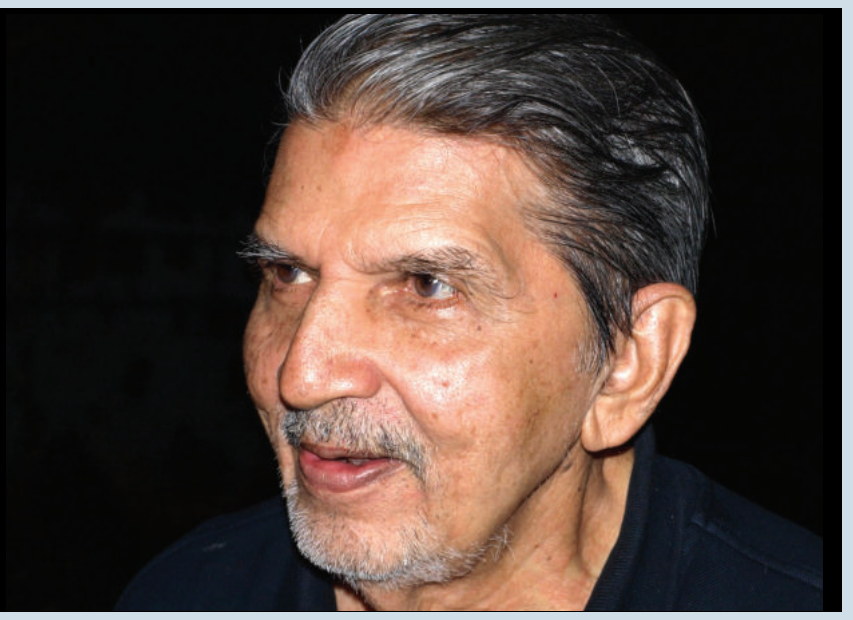

मारियो मिरांडा वैसे दूसरे कलाकार थे, जिनकी मैं पचास के दशक में प्रशंसा करता था, लेकिन उन्हें पिछले दशक से जानने लगा. वह भी देव आनंद की तरह वैश्विक व्यक्ति थे. उनका अधिकांश समय भारत के गोवा में व्यतीत हुआ. वह जितने भारतीय थे, उतने ही पश्चिम के थे. गोवा की सबसे पुरानी पुर्तगीज बस्ती लोटीलुम में उनका घर था.

feedback@chauthiduniya.com

प्रशासन ने सिर्फ़ इतना कहा कि साल के अंत में अच्छी क्वालिटी वाली वाइन बहुत ज़्यादा बिकती है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 02 जनवरी–08 जनवरी 2012

सूचना का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

क्या है सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह सरकार से कोई भी सवाल पूछ सके, कोई भी सूचना ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रति ले सके, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ की जांच कर सके, किसी भी सरकारी काम की जांच कर सके और किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री का प्रमाणित नमूना ले सके. भारत एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी ही देश का असली मालिक होता है. इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का हक़ है कि जो सरकार उसकी सेवा के लिए बनाई गई है, वह क्या, कहां और कैसे कर रही है. हर नागरिक सरकार चलाने के लिए टैक्स देता है, इसलिए भी उसे यह जानने का हक़ है कि उसका पैसा कहां ख़र्च किया जा रहा है. जनता द्वारा यह सब जानने का अधिकार ही सूचना का अधिकार है.

1976 में राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया. अनुच्छेद 19 के अनुसार, हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्त करने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनता जब तक जानेगी नहीं, तब तक अभिव्यक्त नहीं कर सकती. 2005 में देश की संसद ने एक क़ानून पारित किया, जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम में व्यवस्था की गई है कि नागरिक किस प्रकार सरकार से सूचना मांगेंगे और किस प्रकार सरकार जवाबदेह होगी. सभी सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर यूनिट, किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता से चल रहीं ग़ैर सरकारी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थाएं आदि इसमें शामिल हैं. पूर्णत: निजी संस्थाएं इस क़ानून के दायरे में नहीं हैं, लेकिन यदि किसी क़ानून के तहत कोई सरकारी विभाग किसी निजी संस्था से कोई जानकारी मांग सकता है तो उस विभाग के माध्यम से वह सूचना मांगी जा सकती है, धारा–2 (क) और (ज). हर सरकारी विभाग में एक या एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, जो सूचना के अधिकार के तहत आवेदन स्वीकार करते हैं, मांगी गई सूचनाएं एकत्र करते हैं और उन्हें आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराते हैं, धारा–5.

लोक सूचना अधिकारी की ज़िम्मेदारी है कि वह 30 दिनों के अंदर (कुछ मामलों में 45 दिनों तक) सूचना उपलब्ध कराए, धारा–7(1). अगर लोक सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं कराता है अथवा ग़लत या भ्रामक जानकारी देता है तो देरी के लिए 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये तक का जुर्माना उसके वेतन से काटा जा सकता है. साथ ही उसे सूचना भी देनी होगी. लोक सूचना अधिकारी को अधिकार नहीं है कि वह आपसे सूचना मांगने का कारण पूछे, धारा 6 (2). सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क देना होगा. केंद्र सरकार ने आवेदन के साथ 10 रुपये का शुल्क तय किया है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. बीपीएल कार्डधारकों से सूचना मांगने का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, धारा 7(5). दस्तावेज़ों की प्रति लेने के लिए भी शुल्क देना होगा. केंद्र सरकार ने यह शुल्क 2 रुपये प्रति पृष्ठ रखा है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अधिक है. अगर सूचना तय समय सीमा में नहीं उपलब्ध कराई गई है तो सूचना मुफ्त दी जाएगी, धारा 7(6). यदि कोई लोक सूचना अधिकारी यह समझता है कि मांगी गई सूचना उसके विभाग से संबंधित नहीं है तो ऐसे में उसका कर्तव्य है कि वह उस आवेदन को पांच दिनों के अंदर संबंधित विभाग को भेज दे और आवेदक को भी सूचित करे. ऐसी स्थिति में सूचना मिलने की समय सीमा 30 की जगह 35 दिन होगी, धारा 6 (3).

लोक सूचना अधिकारी यदि आवेदन लेने से इंकार करता है अथवा परेशान करता है तो उसकी शिकायत सीधे सूचना आयोग से की जा सकती है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं को अस्वीकार करने, अपूर्ण या भ्रम में डालने वाली या ग़लत सूचना देने अथवा सूचना के लिए अधिक शुल्क मांगने के ख़िलाफ़ केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत की जा सकती है. लोक सूचना अधिकारी कुछ मामलों में सूचना देने से मना कर सकता है. जिन मामलों से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती, उनका विवरण सूचना अधिकार क़ानून की धारा 8 में दिया गया है, लेकिन यदि मांगी गई सूचना जनहित में है तो वह धारा 8 में मनाही के बावजूद दी जा सकती है. जो सूचना संसद या विधानसभा को देने से मना नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को भी देने से मना नहीं किया जा सकता. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देता है या धारा 8 का ग़लत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करता है या दी गई सूचना से संतुष्ट न होने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी यानी प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है, धारा 19 (1). यदि आप प्रथम अपील से भी संतुष्ट नहीं हैं तो दूसरी अपील 60 दिनों के भीतर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग (जिससे संबंधित हो) के पास करनी होती है, धारा 19 (3).

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

द बैड सेंटा

इटली की राजधानी रोम में बीते दो महीनों में छह बड़ी दुकानों में चोरी हुई. एक दुकानदार ने पुलिस को बताया कि विचित्र वेशभूषा में आए एक व्यक्ति ने बंदूक की नोंक पर कैशियर को लूट लिया. कई दिनों तक माथापच्ची करने के बाद पुलिस को सुराग मिला. पुलिस को पता चला कि सेंटा के वेश में आया एक व्यक्ति वारदात करके भाग रहा है. पुलिस शक के आधार पर जब एक घर में घुसी तो फर्जी सेंटा की पोलपट्टी खुल गई. पुलिस को सेंटा की लाल रंग की ड्रेस दिखी और उसके भीतर बंदूक मिली. पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस को शक है कि इनके कुछ और साथी भी हैं. ये लोग सेंटा बनकर बंदूक के साथ घूमते और मौक़ा पाकर लोगों को लूट लेते थे. लूटपाट का यह आइडिया एक फिल्म से चुराया गया. इटली में पिछले साल द बैंड ऑफ फादर क्रिसमस नामक एक फिल्म काफी हिट हुई थी, जिसमें तीन लोगों को ग़लती से लुटेरा समझा गया. पुलिस के मुताबिक़, इन लुटेरों का तरीक़ा फिल्म से प्रेरित लगता है. अब शायद क्रिसमस में लोग सेंटा से डरें.

महंगी बड़ी शराब कि...

शराब जितनी पुरानी हो, उतनी बढ़िया होती है, इस जुमले को अमल में लाने वाले एक शख्स पेरिस से उड़ान भर चुके हैं, लेकिन फ्लाइट पर चढ़ने से पहले उस एशियाई वाइन प्रेमी ने चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट पर ऐसी ख़रीदारी की कि शहर में खुसफुसाहट शुरू हो गई. उसने अथाह पैसे ख़र्च कर पुरानी वाइन (अंगूर की बनी ख़ास शराब) की छह बोतलें ख़रीदीं, जिनमें 1995 की एक रोमाने कोंती, 2003 की एक शातो मारगो और 1982 में तैयार की गई शातो लाफित की दो बोतलें शामिल हैं. उसने 31 साल पुरानी वाइन की भी दो बोतलें ख़रीदीं और बिल बना 49,905 यूरो का. पेरिस एयरपोर्ट के इतिहास में एकमुश्त इतनी बड़ी बिक्री पहले कभी नहीं हुई. एयरपोर्ट प्रशासन और वाइन स्टोर ने ग्राहक का नाम गोपनीय रखा है. पेरिस एयरपोर्ट पर उस एशियाई ग्राहक ने ड्यूटी फ्री सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़े. उसने लगभग 50,000 यूरो यानी 35 लाख रुपये में वाइन की छह बोतलें ख़रीदीं. साल के अंत में हुई इस बंपर सेल से पेरिस वाले दंग हैं. एयरपोर्ट ने यह नहीं बताया कि उस एशियाई धन्ना सेठ ने वाइन पर इतना पैसा कब उड़ाया. प्रशासन ने सिर्फ़ इतना कहा कि साल के अंत में अच्छी क्वालिटी वाली वाइन बहुत ज़्यादा बिकती है. वैसे इतनी ख़रीदारी करके किसी अन्य देश में घुसना बहुत मुश्किल है. तय सीमा से ज़्यादा ख़रीदारी पर कस्टम शुल्क देना अनिवार्य है, लेकिन एशिया से इतनी महंगी वाइन ख़रीदने वाले धन्ना सेठ के बारे में कोई नई ख़बर नहीं आई है. विश्वव्यापी मंदी के दौर में यूरोप समेत कई देशों के नेताओं ने मांग की थी कि बड़े वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, इसमें सभी देशों को सहयोग करना चाहिए और सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए, लेकिन जब वक़्त आया तो एयरपोर्ट अधिकारी नाम बताने की जगह चुप्पी साध गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
जोखिम उठाने की ज़रूरत नहीं है, कार्य सहज ही सिद्ध हो जाएंगे. आपको अपने मन और मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा. किसी साथी या पड़ोसी द्वारा कही गई बात पर आप अचानक भड़क सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि झगड़ा मोल लेने के बाद सुलह-सफाई करने की भी गुंजाइश रखनी चाहिए.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
मौलिक चिंतन एवं तनाव बने रहेंगे. दौड़-भाग के बाद आशाएं बलवती होंगी. यदि आप समय के अनुसार चल रहे हैं और ज़रूरत के मुताबिक़ महसूस कर रहे हैं कि जोखिम लेने के लिए तैयार रहना है तो आप अकेले पड़ सकते हैं.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
शुभ समय का गोचर है, इसका सदुपयोग करना उचित है. आपको व्यक्तिगत जीवन पर सोच-विचार करने की फुर्सत मिलेगी. ऐसा भी मौक़ा आएगा, जब आप दूसरों का सहयोग पाने में सफल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
सप्ताह के मध्य में आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम तैयार पड़े हैं. एक ओर जहां आपको आगामी यात्रा का बंदोबस्त करना है, वहीं अपने काम को बढ़ाने के लिए संपर्क और गठजोड़ भी करने हैं. हो सकता है, आपको किसी निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
सप्ताह के आरंभ में मन में उत्साह रहेगा. निकटस्थजनों का सहयोग मिलेगा. कभी-कभी ज़्यादा परिश्रम और दौड़-भाग करते-करते जब आप बोर हो जाते हैं तो मनोरंजन या मन बहलाव के लिए हल्का-फुल्का कार्यक्रम भी बनाना पड़ता है.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपने जीवन में रचनात्मक कार्य के बजाय प्रेम, रोमांस और सौभाग्य को ज़्यादा महत्व दिया है. यदि इन सबसे पहले रचनात्मक कार्यों में ज़्यादा तल्लीन रहते तो आपको परिवार और बच्चों का समर्थन मिल जाता.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
सप्ताह के आरंभ में बारंबार लाभ होगा और अच्छी ख़बरें मिलेंगी. स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ ज़रूरी क़दम उठाने होंगे. अपने नौकर-चाकर या सहयोगीजनों की भी चिंता करनी पड़ेगी. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप किसी समस्या से घिर जाएंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
आजीविका के जटिल प्रश्न हल होते नज़र आएंगे. आपके जीवन में कई प्रकार के बदलाव और उतार-चढ़ाव इस दौरान आ रहे हैं. आप कहीं पर भी जाएं, वहां आपको कुछ न कुछ करके उदरपूर्ति का साधन तैयार करना होगा.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
सप्ताह के आरंभ में नौकरी में कुछ विलंब हो सकता है, प्रयास जारी रखें. इस राशि के कई जातकों को इस सप्ताह के मध्य में अपना गृहस्थ जीवन संवारने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. कुछ लोग अपने प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने की कोशिश कर सकते हैं.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
स्वास्थ्य विकार के कारण साहस क्षीण हो जाएगा. आप अपने करियर, दांपत्य जीवन, माता-पिता, संतान और परिवार पर अधिक केंद्रित हो सकते हैं. यदि आप नौकरीपेशा हैं तो किसी अच्छे काम का पुरस्कार या प्रोत्साहन मिल सकता है.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
कुछ बौद्धिक उलझनों के कारण मनस्ताप बना रहेगा. अगर गंभीर होकर अपने कार्य में तत्पर हैं तो उन्नति की उच्च सीमा तक जा सकते हैं. अगर समय ने साथ दिया और आपकी इच्छाशक्ति इसी तरह क़ायम रही तो वह दिन दूर नहीं, जब आप औरों के मुकाबले काफी आगे निकल जाएंगे.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
निकट सहयोगियों से बैर-विरोध न हो, इस बात का ध्यान रखें. आप कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं. एक साथ कई काम हाथ में लेने से ऐसा महसूस होना ज़रूरी है. अगर योजनाबद्ध तरीक़े से चलेंगे तो कोई संदेह नहीं कि कारोबार संबंधी समस्या से निजात पा लेंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

अंतरिम सरकार संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाई, जिसके मुताबिक सेना को संवैधानिक वैधता का रक्षक घोषित करना था.

मिस्र मार्शल तांतवी का तांडव

राजीव कुमार

कहा जाता है कि क्रांति अपने पुत्रों को निगल जाती है. क्या मिस्र में कुछ ऐसा ही होने वाला है? जिन लोगों ने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए अपना क़ीमती समय ख़र्च किया, संसाधन लगाए और होस्नी मुबारक को इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर किया, आज उन्हीं के साथ फिर से अन्याय किया जा रहा है. क्या लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रदर्शन करना आज इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि सेना को अपनी मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा. जिन लोगों ने मिस्र में लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिन-रात मेहनत की, उन्हीं को हाशिए पर भेज दिया गया. मिस्र आज भी वहीं खड़ा है, जहां दस महीने पहले खड़ा था. अंतर इतना है कि इस समय लोग बदल गए हैं. शासन का तरीक़ा लोगों को दिखाने के लिए बदल गया है. सत्ता एक हाथ से निकल कर दूसरे हाथ में चली गई है. उस समय होस्नी मुबारक अपनी मर्जी चलाते थे, अब सेना प्रमुख उनकी भूमिका निभा रहे हैं. पिछले दिनों एक लड़की को कुछ सैनिकों ने पीटा और उसे घसीटते हुए कुछ दूर तक ले गए. उस लड़की के कपड़े कुछ इस कदर फट गए कि वह लगभग अर्द्धनग्न स्थिति में आ गई, लेकिन सैनिकों को उस पर दया नहीं आई. उसे उसी अवस्था में घसीटा जाता रहा. जिस इस्लाम धर्म में औरतों को इतनी इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, वहां किसी औरत के साथ होने वाले इस बर्बर व्यवहार को बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है.

इस घटना के बाद प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी है. आख़िरकार उसकी ग़लती क्या थी, उसने कौन सा अपराध किया था? मिस्र की जनता तो केवल इतना चाहती है कि जिस बदलाव के लिए उसने महीनों तक संघर्ष किया, उसकी हत्या न हो. देश में सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना हो, न कि लोकतंत्र के नाम पर सेना की तानाशाही बरक़रार रहे. क्या इसे अपराध कहेंगे? अगर यह अपराध है तो फिर इसकी सज़ा उन सभी लोगों को मिलनी चाहिए, जिन्होंने होस्नी मुबारक के शासन के ख़ात्मे के लिए सड़कों को अपना घर बनाया, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने एवं बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए महीनों तक संघर्ष किया. सेना के उन लोगों को भी अपराधी क़रार दिया जाना चाहिए, जिन्होंने होस्नी मुबारक का साथ नहीं दिया. ग़ौरतलब है कि फरवरी में हुई क्रांति के बाद तीस सालों से काबिज होस्नी मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी. होस्नी मुबारक के बाद शासन की बागडोर सेना के हाथों में सौंप दी गई थी. उस समय आंदोलन करने वाले युवा इससे ख़ुश थे, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने उस समय भी इसे सही नहीं बताया था. उनका कहना था कि सेना को सत्ता सौंपना लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक हो सकता है और उनका अनुमान बिल्कुल सही निकला.

अंतरिम सरकार संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाई, जिसके मुताबिक़ सेना को संवैधानिक वैधता का रक्षक घोषित करना था. साथ ही उसमें यह भी कहा गया कि सेना का बजट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा. इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव को 2012 के अंत या 2013 तक के लिए टाल दिया गया. संविधान संशोधन के इस प्रस्ताव से जनता भड़क गई. उसे लगने लगा कि सेना किसी तरह सत्ता अपने पास रखना चाहती है. मिस्र के युवा जल्द से जल्द लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं. उन्होंने ख़ुद को ठगा महसूस किया, सेना को क्रांति विरोधी क़रार दिया और काहिरा एवं अलक्जेंड्रिया में इकट्ठा होने लगे. पहले सेना ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ने लगी तो उनकी कुछ बातों को स्वीकार कर लिया गया. मिस्र की जनता सोई नहीं है और जागे हुए लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता. सेना ने संसदीय चुनाव कराने का अपना वायदा तो पूरा किया, लेकिन जनता इतने से ख़ुश नहीं हुई. उसका कहना है कि जब तक शासन की बागडोर नागरिक प्रशासकों के हाथों में नहीं सौंपी जाएगी, तब तक उसे इस बात का भरोसा नहीं होगा कि सेना लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम कर रही है. जनता को भरोसा दिलाने के लिए सेना को उसकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन वह इसके विपरीत काम कर रही है. वह प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लगातार हमले कर रही है. सेना के ताजा हमले में दस से अधिक लोग मारे गए और सौ से अधिक घायल हो गए.

प्रदर्शनकारियों ने काहिरा में जमकर तोड़फोड़ मचाई, कुछ इमारतों में आग भी लगा दी. लोग सेना से शासन छोड़ने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि सेना की मंशा साफ होती जा रही है. वह परोक्ष तौर पर शासन करना चाहती है. संसदीय चुनाव कराना तो केवल एक बहाना है, इससे लोकतंत्र बहाल नहीं होगा. सेना जब तक शासन की बागडोर नागरिक प्रशासन के हाथों में नहीं सौंपती, तब तक देश में सही मायनों में लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता. सेना के रवैये से लगता भी यही है कि वास्तव में वह मिस्र की जनता को सही सरकार नहीं देना चाहती, वह किसी तरह इस जनसैलाब को रोकना चाहती है. अगर सेना के मन में कोई छल-कपट न होता तो वह जनता की बात मान लेती और नागरिक प्रशासन को सत्ता सौंप देती, लेकिन वह तो इस प्रदर्शन को कुचलने पर आमादा है. उसने जिस तरह प्रदर्शनकारियों पर हमले किए, उनसे तो यही लगता है कि मार्शल मोहम्मद हुसैन तांतवी होस्नी मुबारक का स्थान लेना चाहते हैं. सेना की इस हिंसात्मक और अमानवीय कार्रवाई की कई देशों ने भर्त्सना की है. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने मिस्र की सेना से अपील की है कि वह देश की जनता को सुरक्षा प्रदान करे और उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करे, जिन्होंने सेना एवं सुरक्षाबल की मर्यादा का उल्लंघन किया. अगर सेना ने अपना रवैया न बदला तो मिस्र में भी लीबिया जैसे हालात पैदा हो सकते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

रूस पुतिन का भविष्य संकट में

सोवियत रूस में संसदीय चुनाव के नतीजे आने के बाद सरकार पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगे हैं. इस चुनाव में रूसी प्रधानमंत्री ब्लादिमिर पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी को जीत तो हासिल हो गई, लेकिन यह कोई बड़ी जीत नहीं है. पुतिन की पार्टी को मात्र 50.2 फ़ीसदी मत मिले हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसे 64 फ़ीसदी मत मिले थे. 450 सीटों के लिए हुए ड्यूमा के चुनाव में यूनाइटेड रसिया पार्टी को 238 सीटें मिली हैं. संसदीय चुनाव में इस बार सात दलों ने हिस्सा लिया, जबकि इससे पहले हुए चुनाव में 11 दलों को हिस्सा लेने का मौक़ा मिला था. कम्युनिस्ट पार्टी (केपीआरएफ) को 19.12 फ़ीसदी मत मिले हैं, जबकि जस्ट रशिया को 13.3 फ़ीसदी. हालांकि इस चुनाव में कामयाबी पुतिन को मिली, लेकिन यह कामयाबी एक साथ कई सवालों को जन्म देती है. पहला सवाल यह है कि क्या वास्तव में पुतिन सफल हुए हैं अथवा यह उनकी घटती लोकप्रियता के बीच का पड़ाव है, जहां से हार तक पहुंचने में ज़्यादा वक़्त की ज़रूरत नहीं है. दूसरा सवाल इस चुनाव के संबंध में उठ रहे विवादों और विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है कि जिस तरह की चुनावी तस्वीर पेश की जा रही है, क्या वह वास्तव में वैसी है या कुछ उलटफेर किया गया है. क्या चुनाव में सचमुच धांधली हुई है, जैसे कि आरोप लगाए जा रहे हैं या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है. पुतिन ने भी आरोप लगाया है कि रूस में विद्रोह फैलाने की कोशिश की जा रही है. अगर यह आरोप ग़लत है तो फिर जनता के बीच आक्रोश का कारण क्या है, जिसके चलते पुतिन विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं.

अगर संसदीय चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें तो यह साफ है कि पहले की अपेक्षा पुतिन की लोकप्रियता में कमी आई है. हालांकि ताजा चुनाव में उनकी पार्टी को पचास फ़ीसदी से अधिक मत मिले, लेकिन ये पिछले चुनाव में मिले मतों से लगभग चौदह फ़ीसदी कम हैं. ग़ौरतलब है कि पुतिन एक बार फिर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिसका चुनाव आगामी मार्च माह में होने वाला है. अगर लोकप्रियता में इज़ाफ़ा हुआ होता तो उनकी पार्टी को पिछले चुनाव से अधिक मत मिलते, लेकिन हुआ इसके विपरीत. ऐसे में पुतिन को राष्ट्रपति बनने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी, जिससे यह पचास फ़ीसदी समर्थन बढ़ाया जा सके, न कि इसे घटने दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा. चुनाव में धांधली का आरोप गोलोस एवं ओएससीई जैसी चुनाव की देखरेख करने वाली संस्थाओं ने लगाया है. गोलोस को अमेरिका और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद मिलती है, जबकि ओएससीई यूरोपीय संस्था है. ऐसे में इन संस्थाओं पर कितना भरोसा किया जा सकता है.

पुतिन के कार्यकाल में रूस की आर्थिक एवं सामरिक ताक़त में वृद्धि हुई है. हालांकि आर्थिक स्थिति मज़बूत करने में देश के तेल और गैस भंडारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को इसका श्रेय देना ही पड़ेगा. चुनाव में धांधली के आरोपों पर शक इसलिए है, क्योंकि अमेरिका इस मामले को जोर-शोर से उठा रहा है. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने भी इस धांधली के संदर्भ में बयान दिया है. अमेरिका ने पुतिन पर चुनाव पर्यवेक्षकों को तंग करने का आरोप लगाया है. ऐसे में इस आरोप पर शक करना अधिक लाजिमी है. पुतिन ने भी अमेरिका पर रूसी जनता को भड़काने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि चुनाव में कैमरों का इस्तेमाल किया गया और किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई. अमेरिका और यूरोप के कुछ देश उनके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं. अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी हस्तक्षेप की वजह से पुतिन विरोधी प्रदर्शन हुए तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं. रूस के पचास शहरों में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा चुनाव कराने की मांग की.

रूस में इस बार सूखा पड़ा, जिससे लगभग 14 अरब डॉलर का नुकसान हुआ. हालांकि तेल की बढ़ती क़ीमतों के कारण बजट घाटे को कम कर लिया गया, लेकिन विनिर्माण और खुदरा बाज़ार के क्षेत्र में कमी आई, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है. मुद्रास्फीति की दर भी लगभग सात फ़ीसदी रही. इसके अलावा भ्रष्टाचार भी रूस में एक अहम मुद्दा रहा है. बड़े-बड़े उद्योगपति रूस के बजाय अन्य देशों में निवेश कर रहे हैं. कई तो रूस में रहते भी नहीं हैं. इन कारणों से जनता में पुतिन के विरुद्ध आक्रोश है. ऐसे में जब चुनाव में धांधली का मामला उठा तो विभिन्न कारणों से परेशान जनता सड़कों पर उतर आई. हालांकि पुतिन के समर्थन में भी प्रदर्शन हुए हैं. बहरहाल, अगर पुतिन राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहते हैं तो उन्हें जनता की समस्याओं को न सिर्फ़ समझना होगा, बल्कि उनका निराकरण भी करना होगा, वरना यह जनाक्रोश उनकी पराजय में तब्दील हो सकता है.

राजीव कुमार
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की एक खास बात अथवा कहें कि कमी है, परिवार में पुत्र को अधिक महत्व देना. यही समस्या चीन में है.

चौथी दुनिया
दिल्ली, 02 जनवरी-08 जनवरी 2012

प्रार्थनाष्टक

गुरुवार दिवस गुरु का मानो, सद्गुरु ध्यान चित्त में ठानो.
स्थोथरा पठन हो अति फलदाई, महाप्रभावी सदा सहाई.
व्रत एकादशी पुण्य सुहाई, पठन सुदिन इसका कर भाई.
निश्चय चमत्कार थम पाओ, शुभ कल्याण कल्पतरु पाओ.
उत्तम गति स्तोत्र प्रदाता, सदगुरु दर्शन पाठक पाता.
इह परलोक सभी हो शुभकर, सुख-संतोष प्राप्त हो सत्वर.
स्तोत्र पारायण सद्य: फल दे, मंद बुद्धि को बुद्धि प्रबल दे.
हो संरक्षक अकाल मरण से. हो शतायु जा स्तोत्र पठन से.
निर्धन धन पाएगा भाई, महा कुबेर सत्य शिव साईं.
प्रभु अनुकंपा स्तोत्र समाई. कवि वाणी शुभ सुगम सहाई.
संततिहीन पाएं संतान, दायक स्तोत्र पठन कल्याण.
मुक्त रोग से होगी काया, सुखकर हो साईं की छाया.
स्तोत्र पाठ नित मंगलमय है, जीवन बनता सुखद प्रखर है.
ब्रह्म विचार गहन तर पाओ, चिंतामुक्त जियो हर्षाओ.
आदर उर का इसे चढ़ाओ, अंत दृढ़ विश्वास बसाओ.
तर्क-वितर्क विलग कर साधो, शुद्ध विवेक बुद्धि अवराधो.
यात्रा करो शिरडी तीर्थ की, लगन लगी को नाथ चरण की.
दीन-दु:खी का आश्रय जो हैं, भक्त-काम-कल्प-द्रुम सोहें.
सुप्रेरणा बाबा की पाऊं, प्रभु आज्ञा पा स्तोत्र रचाऊं.
बाबा का आशीष न होता, क्यों यह गान पतित से होता.
शक संवत अठरह चालीसा, भादों मास शुक्ल गौरीशा.
शशिवार गणेश चौथ शुभ तिथि, पूर्ण हुई साईं की स्तुति.
पुण्य धार रेवा शुभ तट पर, माहेश्वर अति पुण्य सुथल पर.
साईंनाथ स्तवन मंजरी, राज्य अहिल्या भू में उतारी.
मांधाता का क्षेत्र पुरातन, प्रगटा स्तोत्र जहां पर पावन.
हुआ मन पर साईं अधिकार, समझो मंत्र साईं उद्गार.
दासगणु किंकर साईं का, रज कण संत साधु चरणों का.
लेखबद्ध दामोदर करते, भाषा गायन भूपति करते.
साईंनाथ स्तवन मंजरी, तारक भवसागर हृदय तंत्री.
सारे जग में साईं छाए, पांडुरंग गुण किंकर गाए.
श्रीहरिहरापर्णमस्तु शुभं भवतु, पुंडलिक वरदा विट्ठल.
सीताकांत स्मरण जय-जय राम, पार्वतीपते हर-हर महादेव.
श्री सद्गुरु साईंनाथ महाराज की जय.
श्री सद्गुरु साईंनाथपर्णमस्तु.

समाप्त

समाज अपनी खामियों को पहचाने

जो समाज बहुओं को मूक रहने के लिए बाध्य करता है, दहेज के लिए हत्याएं करता है, दहेज को आवश्यक बनाता है, जहां औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और जिसमें अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह करने पर पंचायत द्वारा मौत की सजा दी जाती है, उसे हम श्रेष्ठ समाज कैसे कह सकते हैं. ऐसे समाज को, ऐसे मूल्यों को बदलना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इसे बदलने के लिए किया क्या जा सकता है. सबसे पहले सोच बदलने की आवश्यकता है.

सौमित्र मोहन

हमें अपने भारतीय पारिवारिक मूल्यों पर गर्व होता है. अपने पारिवारिक मूल्यों को हम अन्य संस्कृतियों के पारिवारिक मूल्यों से श्रेष्ठ समझते हैं. अगर किसी से स्वर्ग के बारे में पूछा जाए तो वह कहेगा कि वैसा जीवन, जिसमें ब्रिटिश घर हो, अमेरिकी वेतन हो, चाइनीज खाना हो और भारतीय परिवार हो, स्वर्ग कहा जा सकता है. इसी तरह नरक की परिभाषा यह कहकर दी जाती है कि जिसमें भारतीय वेतन, चीनी घर, ब्रिटिश खाना और अमेरिकी परिवार हो, वह नरक होगा. इस तरह कहा जा सकता है कि भारतीय पारिवारिक मूल्य अन्य सभी संस्कृतियों के पारिवारिक मूल्यों से बेहतर हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह स्थिति बदलती जा रही है. हमारे पारिवारिक मूल्यों में विशेषताओं के साथ-साथ कई खामियां भी हैं, जिनकी ओर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है. इन खामियों की वजह से हमारी पारिवारिक व्यवस्था चरमरा गई है. इन्हीं में से कुछ खामियों पर चर्चा करने की आवश्यकता आजकल महसूस की जा रही है. भारतीय पारिवारिक व्यवस्था की एक खास बात अथवा कहें कि कमी है, परिवार में पुत्र को अधिक महत्व देना. यही समस्या चीन में है. वहां भी एक बच्चे की नीति के बावजूद पुत्र को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण वहां का लिंग अनुपात प्रभावित हो रहा है. पुत्र की चाहत इस कदर भारत के लोगों के ऊपर हावी है कि इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं. यदि आपकी पहली संतान लड़की है तो फिर आपके तथाकथित शुभचिंतक आपको यह सलाह देना शुरू कर देंगे कि कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए. इसके बाद हम में से कई लोग इस दबाव के बाद एक लड़के के लिए तैयार हो जाते हैं. सबसे बड़ी समस्या तो तब होती है, जब लोग लड़के की चाहत में कन्या भ्रूण हत्या शुरू कर देते हैं. वे अनैतिक जांच का इस्तेमाल करते हैं और अगर एक बच्चा होना हो तो फिर लड़के को ही चुनते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति लड़कियों के लिए कम दिखाई पड़ती है. अगर किसी का पहला बच्चा लड़का हो तो वह ऐसा नहीं करता कि दूसरा बच्चा लड़का न हो, बल्कि लड़की हो. हमारे आसपास के सभी शुभचिंतक लोग हमें लड़के के लिए तो कहते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि लड़की की भी उतनी ही आवश्यकता है. इसके चलते हमारे समाज में लिंग अनुपात सही नहीं रह पाता है. लिंग अनुपात का लड़कियों के प्रतिकूल होना भारत में औरतों के प्रति हिंसा और पुरुषों के अविवाहित रहने की एक बड़ी वजह है.

हमारे परिवार में दूसरा मूल्य है, बहू को गाय के समान मानना अर्थात उसका सीधा-सादा होना, जो ससुराल में किसी को कोई जवाब न दे. ऐसी बहुएं परिवार में अपनी सास या किसी और सदस्य की आज्ञा का बिना किसी प्रतिक्रिया के पालन करती हैं. अगर बहू पढ़ी-लिखी हो और परिवार के लोगों के सवालों का जवाब देती है तो उसे अच्छा नहीं कहा जाता है. उसके लिए ग़लत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. परिवार के बुजुर्ग लोगों, खासकर महिलाओं का व्यवहार अपनी बहुओं के प्रति अच्छा नहीं होता. वे हमेशा अपनी बात मनवाने के चक्कर में रहती हैं. कभी-कभी तो वे पारिवारिक व्यवस्था को ही बिगाड़ देती हैं. ऐसा देखा गया है कि कई बार सास अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बेटे और बहू के बीच दरार पैदा कर देती है. ऐसा करके वह अपनी बहू को दबाती है, लेकिन घर में फूट पड़ जाती है. इन्हीं कारणों से संयुक्त परिवार की संस्कृति समाप्त होती जा रही है. भारतीय परिवार के बुजुर्ग लोगों को गाय जैसी बहू चाहिए, लेकिन ऐसी शादियां ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती हैं. इसी तरह की एक समस्या दहेज को लेकर है. यह हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई है. लोग दहेज के लालच में अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह का विरोध करते हैं, वे दहेज को अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का एक साधन मानने लगे हैं. यही नहीं, लोग दहेज को अपने आगे के जीवन को सुरक्षित रखने का आधार भी मानते हैं. इसके कारण शादी-विवाह में जाति की महत्ता को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है. दहेज के इस लालच के कारण महिलाओं का उत्पीड़न दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. आएदिन दहेज के लिए बहुओं को जलाए जाने की ख़बरें मिलती रहती हैं. समाज के इस मूल्य को किसी भी आधार पर सही नहीं कहा जा सकता है. यही नहीं, इससे जाति प्रथा और भेदभाव को बढ़ावा मिलता है, जो समाज के लिए कतई सही नहीं है और यह भारतीय पारिवारिक मूल्यों की एक बड़ी कमज़ोरी भी है. इस प्रकार का संकीर्ण समाज किसी भी तरह सही नहीं कहा जा सकता है. इससे वैश्विक स्तर की विचारधारा का बनना मुश्किल हो जाता है. इसका एक कारण शिक्षा की संकीर्णता है. हमें दूसरी संस्कृतियों की अच्छी बातें स्वीकार करनी चाहिए. इससे किसी भी संस्कृति के नकारात्मक पक्षों को हटाया जा सकता है. इस संकीर्ण सोच को बदलने के बाद ही सैम्युल हटिंगटन के सभ्यता के संघर्ष के सिद्धांत को बदला जा सकता है और उसकी जगह मार्शल मैकलुहान की वैश्विक गांव (ग्लोबल विलेज) की नीति को बढ़ावा दिया जा सकता है. हमें अपनी धारणाएं बदलनी होंगी, ताकि इस संकुचित मानसिकता के दायरे से बाहर निकला जा सके.

पितृसत्तात्मक समाज का मूल्य कभी भी समतावादी नहीं हो सकता है. इस समाज में वही मूल्य सिखाए जाते हैं, जिनसे किसी एक समुदाय को लाभ हो. इस समाज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होती है, जिसमें औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है. ऐसे समाज में पुरुष की प्रधानता होती है और औरतों का शोषण किया जाता है. यह हमारे समाज की एक बहुत बड़ी खामी है. इस मूल्य को भी बदलने की आवश्यकता है, ताकि समाज में समानता आ सके और किसी को भी किसी दूसरे पर अपनी श्रेष्ठता दिखाने का मौक़ा न मिले. परंपरागत मूल्यों में संशोधन की आवश्यकता है. जिन परंपरागत मूल्यों के कारण समाज को परेशानी हो रही है, उन्हें केवल इस आधार पर नहीं बनाए रखा जा सकता है कि वे परंपरागत समाज के हिस्से हैं. जो समाज बहुओं को मूक रहने के लिए बाध्य करता है, दहेज के लिए हत्याएं करता है, दहेज को आवश्यक बनाता है, जहां औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और जिसमें अंतरजातीय या अंतरधर्मीय विवाह करने पर पंचायत द्वारा मौत की सज़ा दी जाती है, उसे हम श्रेष्ठ समाज कैसे कह सकते हैं. ऐसे समाज को, ऐसे मूल्यों को बदलना ही चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि इसे बदलने के लिए किया क्या जा सकता है. सबसे पहले सोच बदलने की आवश्यकता है. परंपरागत सोच से बाहर निकल कर उदार सोच की ओर बढ़ना होगा. जिन परंपरागत विचारों और मूल्यों की वजह से समाज के एक हिस्से का लगातार शोषण होता रहा है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. इस सोच को बदलने के लिए आवश्यकता है एक सही शिक्षा प्रणाली की. जब तक शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इस परंपरागत विचार को बदलना मुश्किल है. इसके लिए संकुचित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना होगा. सांस्कृतिक शिक्षा के अंतर्गत हमें दूसरी सभी संस्कृतियों की अच्छी बातों को शामिल करना पड़ेगा, ताकि हमें यह अनुभव हो सके कि हम जो सोचते हैं, वही सच्चाई नहीं है, बल्कि इससे इतर भी सच्चाई है. हमें आत्ममंथन और आत्मचिंतन करना होगा कि जिन सामाजिक मूल्यों की बात हम बढ़-चढ़कर करते हैं, उनमें कई खामियां भी हैं, जिन्हें अगर जल्दी दूर नहीं किया गया तो ये सामाजिक मूल्य अब ज़्यादा दिनों तक गर्व करने के लायक़ नहीं रह जाएंगे. हमें अब नवीन उदारवादी समाज की स्थापना के लिए काम करना होगा, जिसमें सभी वर्ग को समान अधिकार मिलें, जिसमें किसी एक समुदाय को दूसरे पर शासन करने का अधिकार न हो. हमें ऐसे ही उदारवादी समाज की आवश्यकता है. आधुनिक वैश्विक शिक्षा को आधार बनाकर ही समाज की कमियों को समाप्त किया जा सकता है.

(लेखक आईएएस अधिकारी हैं, इस आलेख में व्यक्त विचार उनके अपने हैं, जिनका सरकार से कोई संबंध नहीं है.)

feedback@chauthiduniya.com

विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस में और भी बातें कही गई हैं, जो बहुत ही मज़बूती से विचारों को अभिव्यक्त करने की इजाज़त देती हैं, लेकिन अपनी ही गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए स्वामी को कोर्स से हटा देना कई सवाल खड़े करता है.

अनंत विजय

संकट में हॉवर्ड की प्रतिष्ठा

दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक हॉवर्ड विश्वविद्यालय इन दिनों विवादों में घिर गया है. विश्वविद्यालय के दो निर्णयों की दुनिया भर में आलोचना हो रही है. पहला निर्णय तो भारतीय राजनेता एवं अर्थशास्त्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को गर्मी के दौरान चलने वाले अर्थशास्त्र के दो पाठ्यक्रमों के शिक्षण से हटा देने का है. ग़ौरतलब है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी पिछले कई सालों से हॉवर्ड के समर स्कूल में अर्थशास्त्र पढ़ा रहे थे. स्वामी को वहां से निकालने के पीछे जो तर्क दिया गया है, वह यह है कि उन्होंने एक लेख लिखा, जिसकी वजह से एक ख़ास समुदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हुई और उस समुदाय के पवित्र स्थलों को लेकर अपमानजनक और हिंसा भड़काने वाली टिप्पणी की गई. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और वहां के कर्ताधर्ताओं की एक लंबी बैठक में गर्मागर्म बहस के बाद यह फ़ैसला लिया गया कि हॉवर्ड विश्वविद्यालय का यह नैतिक दायित्व है कि वह किसी भी ऐसे व्यक्ति या संस्था के साथ न जुड़े, जो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ घृणा फैलाता हो. विश्वविद्यालय के शिक्षकों के बीच चली बहस में कई लोगों को इस बात पर आपत्ति थी कि स्वामी का लेख अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, बल्कि घृणा की राजनीति का हिस्सा है, लिहाज़ा हॉवर्ड से स्वामी को हटा दिया जाना चाहिए.

दरअसल यह पूरा विवाद सुब्रह्मण्यम स्वामी के 16 जुलाई को लिखे एक लेख से शुरू हुआ, जिसका शीर्षक था-हाउ टू वाइप आउट इस्लामिक टेरर. अपने उस लेख में स्वामी ने लिखा कि भारत को एक संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए और वहां उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार मिले, जो यह ऐलान करें कि उनके पूर्वज हिंदू थे. स्वामी ने अपने लेख में यह भी लिखा कि हिंदू धर्म से किसी भी धर्म में धर्मांतरण की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए. स्वामी इतने पर भी नहीं रुके और अपने लेख में उन्होंने मांग कर दी कि काशी विश्वनाथ मंदिर समेत तीन सौ अन्य स्थानों से विवादास्पद मस्जिदों को हटाया जाए. जब यह लेख प्रकाशित हुआ तो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और पक्ष-विपक्ष में तर्क-वितर्क शुरू हो गया. हॉवर्ड ने भी पहले स्वामी के इस लेख को अभिव्यक्ति की आज़ादी माना और वह उनके साथ खड़ा दिखा. शुरुआत में हॉवर्ड प्रशासन को यह लेख फ्रीडम ऑफ स्पीच की कैटेगरी में दिखाई दिया, लेकिन चंद छात्रों ने स्वामी के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय में अभियान छेड़ दिया. उस अभियान में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वामी ने हॉवर्ड की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है, लिहाज़ा विश्वविद्यालय स्वामी के साथ अपने संबंध ख़त्म करे.

चंद छात्रों की इस मुहिम के आगे विश्व के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने अपने सदियों पुराने सिद्धांतों से समझौता कर लिया. पहले जो लेख विश्वविद्यालय को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिख रहा था, वही लेख चंद छात्रों और दो-तीन वामपंथी रुझान वाले शिक्षकों की अगुवाई वाली मुहिम के बाद घृणा फैलाने वाला लगने लगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्वामी के इस लेख को घृणा फैलाने वाला वैसा लेख माना, जो हिंसा के लिए उकसाता है. यह सही है कि हॉवर्ड हमेशा से उस सिद्धांत के तहत काम करता है, जहां विश्व में एक ऐसे समाज की कल्पना की जाती है, जहां पूरी दुनिया की संस्कृतियों के लोग मिलजुल कर रह सकें, लेकिन वहीं हॉवर्ड में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सर्वोपरि भी माना जाता है. विश्वविद्यालय की जो फ्री स्पीच गाइडलाइंस हैं, उनके अनुसार, स्वामी के ख़िलाफ़ लिया गया निर्णय न सिर्फ़ अनुचित है, बल्कि ख़ुद हॉवर्ड द्वारा बनाई गईं गाइडलाइंस का उल्लंघन भी है. 15 मई, 1990 को हॉवर्ड में यूनिवर्सिटी फ्री स्पीच गाइडलाइंस तैयार की गईं, जो यह कहती हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी विश्वविद्यालय के लिए इस वजह से बेहद अहम है, क्योंकि हमारा समूह कारणों और तर्कों पर आधारित डिस्कोर्स की वकालत करता है. अपने विचारों को बग़ैर किसी दबाव के सबके सामने रखना हमारी प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाना या फिर उसमें काट-छांट करने से हमारी बौद्धिक स्वतंत्रता के विचारों को ठेस पहुंच सकती है. यह किसी व्यक्ति के उन विचारों को भी सामने आने से रोकता है, जो बेहद अलोकप्रिय हों और किसी समुदाय को पसंद न आते हों. साथ ही उस ख़ास समुदाय को भी अपनी आलोचना सुनने के अधिकार से वंचित करता है.

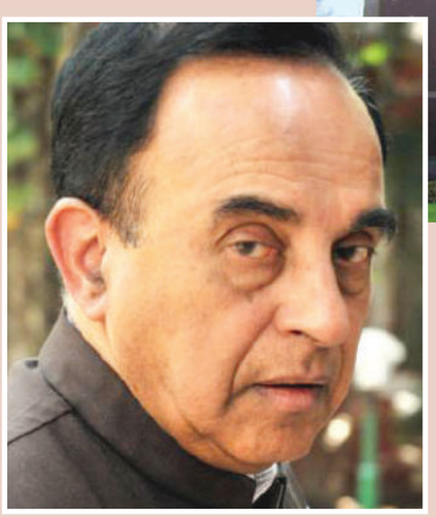

विश्वविद्यालय की गाइडलाइंस में और भी बातें कही गई हैं, जो बहुत ही मज़बूती से विचारों को अभिव्यक्त करने की इजाज़त देती हैं, लेकिन अपनी ही गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए स्वामी को कोर्स से हटा देना कई सवाल खड़े करता है. सवाल तो इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि सुब्रह्मण्यम स्वामी से इस बाबत कोई सफाई नहीं मांगी गई और न उन्हें अपना पक्ष रखने का मौक़ा दिया गया. दशकों से हॉवर्ड का हिस्सा रहे एक भारतीय विद्वान के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद अफसोसजनक है और हॉवर्ड की प्रतिष्ठा के ख़िलाफ़ होने के साथ-साथ न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के ख़िलाफ़ भी है. हॉवर्ड में हर तरह के विचारों को जगह मिलती रही है. वहां के कई शिक्षकों ने एशियाई देशों के ख़िलाफ़ कई आपत्तिजनक लेख लिखे, हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के बारे में टिप्पणियां कीं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई. शोध के नाम पर लिखे गए लेखों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धज्जियां उड़ाई गईं, लेकिन उन सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आईने में देखा गया, कभी किसी लेखक के ख़िलाफ़ विश्वविद्यालय ने कोई कार्रवाई नहीं की. छात्रों और शिक्षकों के किसी समूह ने कोई विरोध नहीं किया.

स्वामी ने भी भारत के एक अख़बार में लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया है. वह भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं तो इसमें ग़लत क्या है. ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और अपने विचार बनाना, उन्हें प्रकट करना हर व्यक्ति का हक़ है. भारत और विदेशों में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे, जो भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हैं. विवादास्पद मस्जिदों को मंदिर परिसरों से हटाने की वकालत तो भारत का प्रमुख विपक्षी दल भी करता है और यह भारत के एक बड़े समुदाय का मत है. तो अगर स्वामी ने अपना मत ज़ाहिर कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया. तीसरी बात स्वामी ने धर्मांतरण के ख़िलाफ़ कही है, वह भी उनका निजी विचार है और उस पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाना जायज़ नहीं कहा जाएगा. आप उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने से नहीं रोक सकते, असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति का दंड लेखक को देना हॉवर्ड विश्वविद्यालय की ख़ुद की गाइडलाइंस और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है. हॉवर्ड ने तो स्वामी से बग़ैर कुछ पूछे, बग़ैर उनका पक्ष जाने उन्हें अपने कोर्स से हटा दिया.

दूसरी अहम बात, जो हॉवर्ड की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, वह यह है कि विश्वविद्यालय ने ऑक्यूपॉय मूवमेंट के मद्देनज़र हॉवर्ड यॉर्ड को बाहरी गतिविधियों के लिए बंद कर दिया. यह एक ऐसी जगह थी, जहां छात्र, पर्यटक एवं सामाजिक समूह आते थे, बैठते थे, बहस-मुबाहिसे करते थे और चले जाते थे. दशकों से वहां ऐसी परंपरा चल रही थी और हॉवर्ड यार्ड कई आंदोलनों का गवाह भी रहा है, लेकिन आरोप है कि अमेरिका में जारी ऑक्यूपॉय मूवमेंट को रोकने के लिए विश्वविद्यालय ने यह क़दम उठाया. इन दो क़दमों से विश्वविद्यालय की अभिव्यक्ति की आज़ादी के समर्थक वाली छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ठेस पहुंची है, जिसके लिए वह जाना जाता है. ज़रूरत इस बात की है कि विश्वविद्यालय अपनी पुरानी परंपरा की ओर लौटे और विचारों को बेख़ौफ़ होकर अभिव्यक्त करने वालों को मंच प्रदान करे. अंतरराष्ट्रीय जगत को इस बात का इंतज़ार भी है कि हॉवर्ड अपनी ग़लतियों को सुधारे, स्वामी से माफी मांगे और हॉवर्ड यॉर्ड पर लगाई गई पाबंदी को हटाए.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

यात्रा साहित्य माला में एक और मोती

मनुष्य-जातियों का इतिहास उनकी यायावरी प्रवृत्ति से संबद्ध है. यात्रा का मुख्य आकर्षण-बिंदु मनुष्य के सौंदर्य बोध के विकास के साथ-साथ चतुर्दिक् व्याप्त जगत का विस्तार भी है. प्रस्तुत कृति के लेखक अनिल सुलभ ने सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास की भावना द्वारा प्रेरित होकर उत्तर और दक्षिण भारत की यात्रा की. सुलभ ने ऐसे यायावर की भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें साहित्यिक मनोवृत्ति दृष्टिगत होती है.

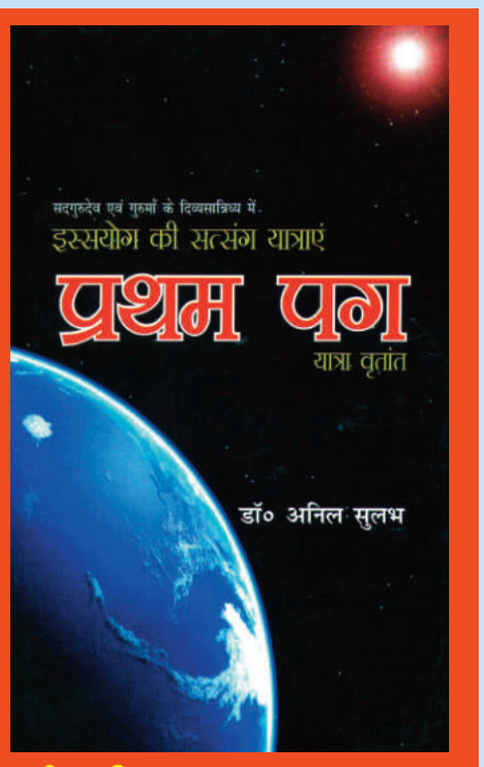

सुलभ एक ऐसे साहित्यिक यायावर हैं, जिन्होंने मुक्त मनोवृत्ति के साथ परिभ्रमण किया और इस कृति की रचना करके यात्रा साहित्य या फिर परम घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में, घुमक्कड़ साहित्य की श्रीवृद्धि की.

समीक्ष्य कृति	:	प्रथम पग
लेखक	:	डॉ. अनिल सुलभ
प्रकाशक	:	अनामिका प्रकाशन
मूल्य	:	175 रुपये

सुलभ एक ऐसे साहित्यिक यायावर हैं, जिन्होंने मुक्त मनोवृत्ति के साथ परिभ्रमण किया और इस कृति की रचना करके यात्रा साहित्य या फिर परम घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में, घुमक्कड़ साहित्य की श्रीवृद्धि की. सुलभ ने यात्रा का केवल विवरण मात्र ही प्रस्तुत नहीं किया, अपितु उनकी यात्रा में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि को अपेक्षित प्रमुखता प्राप्त हुई और हिंदी यात्रा साहित्य समृद्ध हुआ.

सुलभ की इस कृति से यात्रा साहित्य का विस्तार हुआ है, साथ ही हिंदी की निबंध शैली को भी नया आयाम मिला, जिसमें यात्रा करने वाले की व्यक्तिपरकता, स्वच्छंदता और आत्मीयता आदि गुणों का भी समावेश हुआ है. सुलभ ने यात्रा के क्रम में प्राय: उन्हीं क्षणों को अक्षरबद्ध किया है, जिन्हें उन्होंने अनुभूत सत्य के रूप में ग्रहण किया. भ्रमण से संबद्ध देश और काल के वर्णन में निरपेक्ष रूप से सुलभ का अपना व्यक्तित्व भी उभर कर सामने आया. उन्होंने खुद को केंद्र में रखकर भी प्रमुख न बनाकर साहित्यिक यायावर के कर्तव्य का सफल निर्वहन किया. सरल-प्रांजल भाषा में लिखी यह कृति यात्रा साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है.

श्रीरंजन सूरिदेव
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम	तुलसीदास
लेखक	नंदकिशोर नवल
प्रकाशक	राजकमल प्रकाशन
मूल्य	200 रुपये

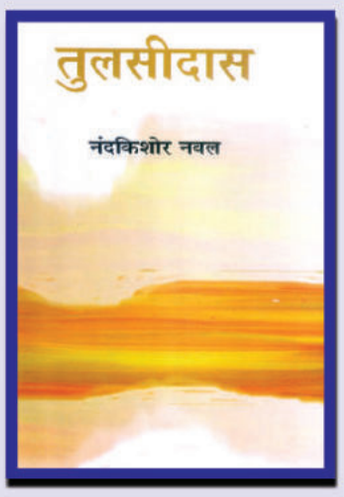

यह किताब गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं पर आधारित है.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

इस कार का इंजन 1.3 लीटर का होगा, जो डीजल सुपर टर्बो इंजन होगा. इसके माइलेज के बारे में ख़ुलासा नहीं किया गया है.

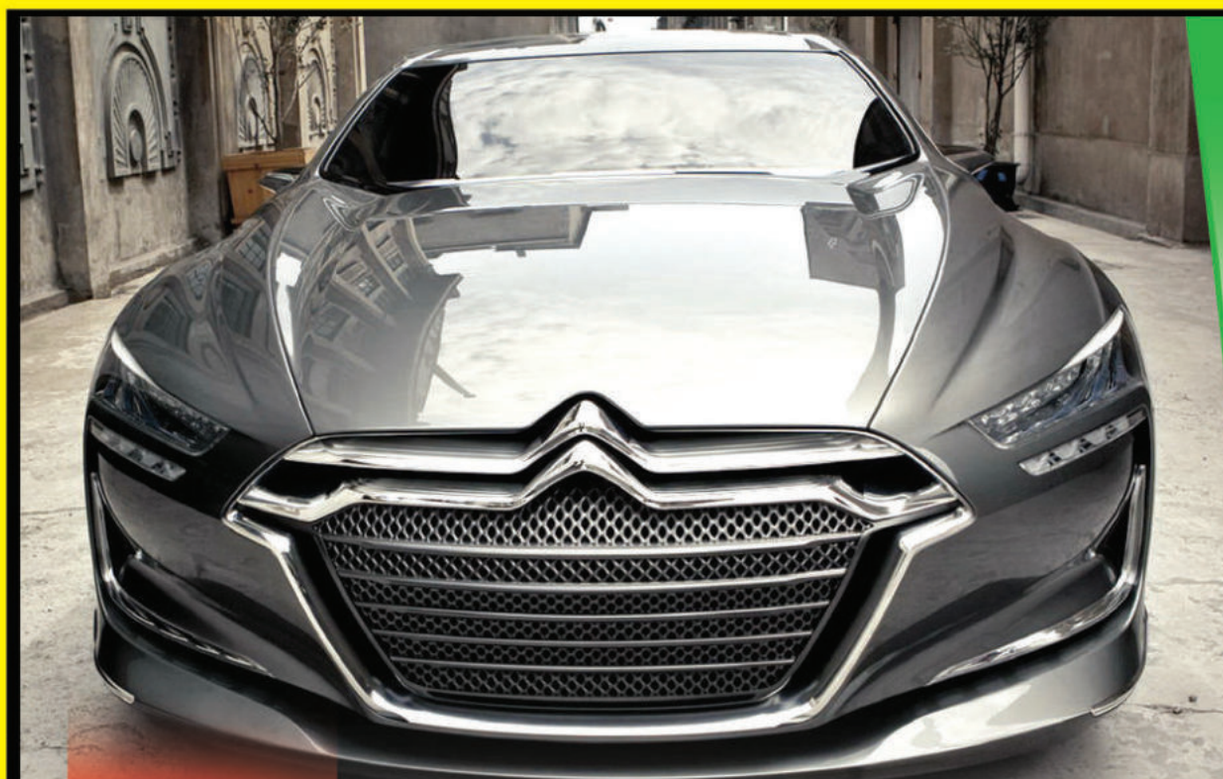

दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम क़ीमत क़रीब 27 लाख रुपये है.

एक लीटर में 98 किलोमीटर!

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती क़ीमतों के इस दौर में कार के शौक़ीनों के लिए यह सबसे बड़ी ख़ुशख़बरी है. एक लीटर में 98 किलोमीटर का माइलेज देने वाली कार जल्द ही सड़कों पर दौड़ती नज़र आएगी. हम बात कर रहे हैं अमेरिका की जानी-मानी कार कंपनी जेनरल मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार शेवरले वोल्ट की. शेवरले वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटर से लैस है और इसके साथ 40 मील यानी 65 किलोमीटर का बैट्री पैक दिया जाता है. खास बात यह है कि इसके बैट्री पैक को आप किसी भी होम आउटलेट से रिचार्ज करा सकते हैं. दुनिया भर में अब तक टोयोटा की प्रायस को सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार के तौर पर जाना जाता है. यह कार एक लीटर में 20 किलोमीटर चलती है. प्रायस गैस इलेक्ट्रिक हाईब्रिड कार है, जो एक छोटे से इंटर्नल कंबशन इंजन पर चलती है, जिसे सपोर्ट करने के लिए एक बैट्री पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है. टोयोटा ने अपनी इस हाईब्रिड कार को इसी साल दिल्ली में हुए ऑटो एक्सपो में लांच किया था. क़रीब तीन महीने पहले भारत में इसकी बिक्री शुरू हुई है. दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम क़ीमत क़रीब 27 लाख रुपये है. यूं तो कार बनाने वाली दुनिया भर की कंपनियां हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक कांसेप्ट पर फ्यूल एफिशिएंट कारें बनाने में जुटी हैं, लेकिन जानकारों की मानें तो वोल्ट की बदौलत जेनरल मोटर्स बाज़ार में मार्केट लीडर बनकर उभर सकता है.

जेब में रखिए टीवी-कंप्यूटर

हम जल्द ही टीवी एवं कंप्यूटर को फोल्ड करके अपनी जेब में रख सकेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कहीं भी यूज कर सकेंगे. यह कमाल होगा क्वांटम डॉट्स यानी क्यूडी टेक्नोलॉजी का. ट्रेन या बस में सफर के दौरान आपके बराबर वाला पैसेंजर अपनी जेब से फोल्ड की हुई स्क्रीन निकाले और उसे सीधा करके उस पर मूवी देखना शुरू कर दे तो आपको लगेगा कि मानो यह कोई सपना है, लेकिन यह सपना जल्द ही हक़ीक़त बनने जा रहा है. हो सकता है कि अभी तक आप क्लियर पिक्चर की चाहत में एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले के फैन हों, लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले, जो न सिर्फ़ इससे बेहतर डिस्प्ले दे, बल्कि क़ीमत के मामले में भी आधा हो तो आप उसे ही पसंद करेंगे. क्यूडी टेक्नोलॉजी की यही ख़ासियत है. सबसे बड़ी ख़ासियत यह कि स्क्रीन इतनी पतली हो जाएगी कि टीवी या कंप्यूटर को आप आसानी से फोल्ड करके अपने साथ कैरी कर सकते हैं. अपने कमरे की दीवार पर आप इसे एक वॉलपेपर की तरह लगाकर बेहतरीन पिक्चर क्वॉलिटी और सफर के दौरान इसे जेब से निकाल कर मूवी का मज़ा ले सकते हैं. इसकी मदद से न सिर्फ़ आपको टीवी, कंप्यूटर एवं मोबाइल में एलसीडी और एलईडी स्क्रीन के मुक़ाबले ज़्यादा ब्राइट पिक्चर देखने को मिलेगी, बल्कि इसमें एनर्जी भी कम ख़र्च होगी. शोधकर्ताओं के मुताबिक़, इस तकनीक से बना पहला टीवी जल्द ही मार्केट में आ जाएगा, जबकि फोल्ड होने वाला टीवी तैयार होने में क़रीब तीन साल का वक़्त लगेगा. दरअसल, क्वांटम डॉट्स सेमीकंडक्टर नैनोक्रिस्टल्स हैं, जो करंट या फिर लाइट के टच में आने पर चमकते हैं. हालांकि इनका चमकना इनके कलर, साइज और मैटीरियल पर डिपेंड करता है. इस शोध से जुड़े जोंग मिन किम के अनुसार, हमने एक साइंटिफिक चैलेंज को रीयल टेक्नोलॉजी अचीवमेंट में चेंज कर दिया है. एक अन्य शोधकर्ता ताय हो किम का कहना है कि क्यूडी तकनीक एलसीडी और एलईडी से पांच गुना कम एनर्जी कंज्यूम करेगी. उन्होंने बताया कि क्यूडी न सिर्फ़ एलसीडी और एलईडी के मुक़ाबले ज़्यादा ब्राइट और लांग लास्टिंग होगी, बल्कि इसे आधे से भी कम लागत में तैयार किया जा सकेगा.

होंडा सिटी का नया मॉडल

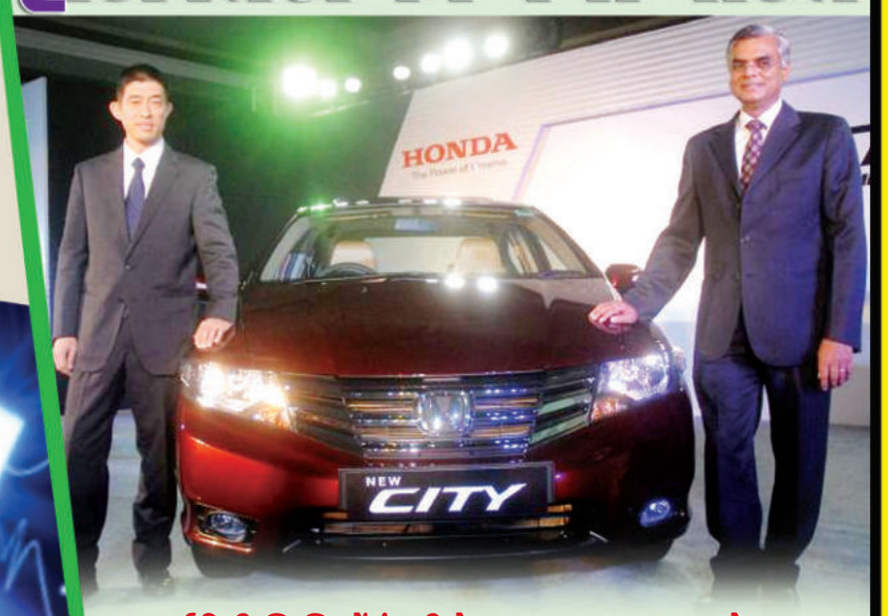

नई सिटी की क़ीमतें कंपनी ने 6.99-10.22 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) तय की हैं. इससे पहले सिटी की क़ीमतें 7.49-9.89 लाख रुपये के बीच थीं.

होंडा सिएल ने अपने फ्लैगशिप मॉडल सिटी का नया वर्जन लांच किया है. नई सिटी का बेस वेरिएंट पुरानी सिटी के मुक़ाबले 50,000 रुपये सस्ता है. नई सिटी की क़ीमतें कंपनी ने 6.99-10.22 लाख रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) तय की हैं. इससे पहले सिटी की क़ीमतें 7.49-9.89 लाख रुपये के बीच थीं. कंपनी ने नई सिटी में कॉरपोरेट एडिशन लांच किया, जिसकी क़ीमत 6.99 लाख रुपये है. कंपनी का कहना है कि इस मॉडल में कई फीचर्स नहीं हैं. इस वजह से यह सस्ता है. होंडा सिटी की डिलीवरी जनवरी 2012 से शुरू हो जाएगी. होंडा सिएल कार्स इंडिया के डायरेक्टर (मार्केटिंग) सेकी इनाबा ने कहा, हमारा लक्ष्य है कि ग्राहकों को किफायती दामों पर कार मॉडल मुहैया कराए जाएं, इसलिए कंपनी ने नई सिटी में कॉरपोरेट एडिशन लांच किया.

अब बॉस की निगाहों से बचना मुश्किल

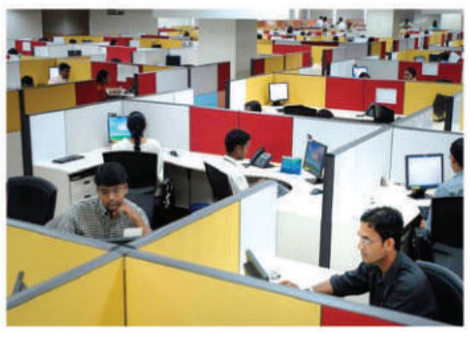

क्या आप ऑफिस में ऑनलाइन गेम खेलते हैं, चैटिंग करते हैं या नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करते हैं? यदि हां, तो इस आदत से छुटकारा पाने की कोशिश करें. माइक्रोसॉफ्ट ऐसी तकनीक ला रहा है, जिससे कर्मचारियों की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकेगा. यह सॉफ्टवेयर न सिर्फ़ ई-मेल, फोन कॉल, बल्कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान आपके हावभाव पर नज़र रखने में भी सक्षम होगा. माइक्रोसॉफ्ट ने इस सॉफ्टवेयर के पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया है. यह सिस्टम कर्मचारियों पर निगाह रखकर उन्हें उनके आचरण के अनुरूप पॉजिटिव व निगेटिव मार्क्स देगा.

यदि किसी कर्मचारी को बीच में टोकने की आदत है या कोई वीडियो कांफ्रेंसिंग में सलीके से कपड़े पहन कर नहीं आता है, तो उसे निगेटिव मार्क्स मिलने तय हैं. डीप सॉफ्टवेयर कंपनी ने एक्टिविटी मॉनीटर विकसित किया है. इसके ज़रिए कोई संस्थान न सिर्फ़ गुप्त जानकारियों को लीक होने से रोकता है, बल्कि ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों और ट्रेड सीक्रेट्स को भी बचाए रखता है. इस सिस्टम से अधिकारियों या सहयोगी कर्मचारियों द्वारा उत्पीड़न को रोकने में मदद मिलती है. साथ ही अवैध तरीक़े से किसी डाटा या सॉफ्टवेयर की डाउनलोडिंग को भी रोका जा सकता है. एक्टिविटी मॉनीटर कर्मचारियों द्वारा विजिट की गई वेबसाइट्स के लॉग पर निगाह रखता है यानी अगर कोई कर्मचारी काम के समय में ऑनलाइन गेम खेलता है, वीडियो देखता है या सोशल नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करता है तो उसकी जानकारी की जा सकती है. इस तकनीक से काम के दौरान समय बर्बाद करने वाले कर्मियों को आसानी से पहचाना जा सकता है. इसमें कुछ ऐसे एप्प की भी मदद ली जाती है, जो व्यक्तिगत आईडी से भेजे गए ई-मेल के टेक्स्ट को इंटरसेप्ट कर सकते हैं. यही बात चैटिंग पर लागू होती है. किसी ने चैटिंग में क्या-क्या बातें कीं, उसका सार जाना जा सकता है. इस तरह ऑफिस में आप हमेशा बॉस की नज़र में रहेंगे. खास बात यह है कि इसके ज़रिए एक ही समय में सभी कंप्यूटरों पर न सिर्फ़ नज़र रखी जा सकती है, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप भी किया जा सकता है. एक्टिविटी मॉनीटर सुपरवाइज़र को यह अधिकार देता है कि वह नियंत्रण कक्ष से किसी भी कंप्यूटर को शट डाउन या सिस्टम को रिबूट कर सकता है. कर्मचारी द्वारा किए जा रहे किसी काम को बीच में भी रोका जा सकता है.

कॉपी की गई फाइल को नष्ट किया जा सकता है और संबंधित शख़्स की ऑनलाइन और पीसी पर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सकता है. माइक्रोसॉफ्ट इस सिस्टम का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ावा देना चाहता है. कंपनी से जुड़े सूत्रों के अनुसार, मॉनीटरिंग सिस्टम से ऑफिस में अनुशासन आएगा, साथ ही कर्मचारियों को ख़ुद में सुधार लाने का मौक़ा भी मिलेगा. माइक्रोसॉफ्ट का मॉनीटरिंग सिस्टम सेल्फ इंप्रूवमेंट टूल की तरह काम करेगा.

सोनी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरू तवागंवा एवं वाइस प्रेसिडेंट हिइकी फ्यूमरी नई दिल्ली में टेबलेट एस एंड पी लांच करते हुए.

फोटो-सुनील मल्होत्रा

मारुति की डीजल इंजन कार

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अब एक कॉम्पैक्ट कार पेश करने जा रही है. यह शानदार कार दिल्ली ऑटो एक्सपो में दिखाई जाएगी. इसे एमपीवी (मल्टी परपज व्हीकल) कहा जाता है. इसका नाम है एर्टिगा और यह एक छोटी कार है. मूल रूप से यह एक कॉन्सेप्ट कार है और इसका व्यवसायिक संस्करण आने में विलंब है. मारुति सुजुकी के पास इस वर्ग की कोई कार नहीं है. इस कार का इंजन 1.3 लीटर का होगा, जो डीजल सुपर टर्बो इंजन होगा. इसके माइलेज के बारे में ख़ुलासा नहीं किया गया है, लेकिन समझा जाता है कि यह 20 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज देगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कर्णम और कुंजुरानी आमने-सामने

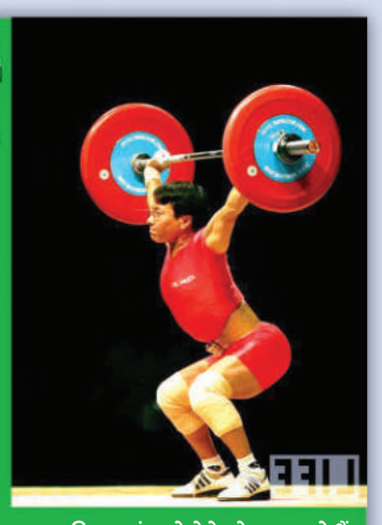

कर्णम मल्लेश्वरी और कुंजुरानी आजकल आमने-सामने हैं. दोनों के बीच वाक्युद्ध शुरू हो चुका है. अभी हाल में कर्णम ने भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का समर्थन करने वाली कुंजुरानी पर पलट वार करते हुए कहा कि मौजूदा पदाधिकारियों के बारे में उनका बयान ग़ैर ज़रूरी और प्रायोजित है. भारत की एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम ने आईडब्ल्यूएफ और कुंजुरानी को भेजे गए प्रत्युत्तर में कहा कि इस मामले में कुंजुरानी का बयान गैर जरूरी और प्रायोजित है, क्योंकि आईडब्ल्यूएफ के संबंधित पदाधिकारी मूक हैं. क़ानूनन चुप्पी को सहमति माना जाता है. उन्होंने कहा कि अभी तक कुंजुरानी महासंघ की कार्यप्रणाली के ख़िलाफ़ थीं. मैं हैरान हूं कि उन्होंने यू टर्न कैसे ले लिया. पिछले दो सालों से वह चुपचाप रहीं. लगता है कि यह बयान उनके लिए तैयार किया गया है. उन्होंने जिस तरह आईडब्ल्यूएफ अध्यक्ष बी पी वैश्य और महासचिव सहदेव यादव की तारीफ़ की है, उससे साफ लगता है कि मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे को खारिज करने के लिए ऐसा किया गया है. कुंजुरानी ने महासंघ के प्रति पूरा समर्थन जताते हुए मल्लेश्वरी के बयान को बेबुनियाद कहा था. कर्णम ने हाल में आईडब्ल्यूएफ के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया था, क्योंकि वह महासंघ की कार्यप्रणाली से नाख़ुश थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि महासंघ को ऐसे लोग चला रहे हैं, जिन्हें खेल के बारे में कुछ नहीं पता. सिडनी ओलंपिक 2000 की कांस्य पदक विजेता इस भारोत्तोलक ने कहा कि उनके इस्तीफ़े का कारण मौजूदा पदाधिकारियों का मनमाना रवैया था. उन्होंने कहा कि पदाधिकारियों ने मेरे दावों का प्रत्यक्ष रूप से जवाब नहीं दिया है. अब उन्होंने मेरी साथी खिलाड़ी को मोहरा बनाया है. कुल मिलाकर दोनों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है.

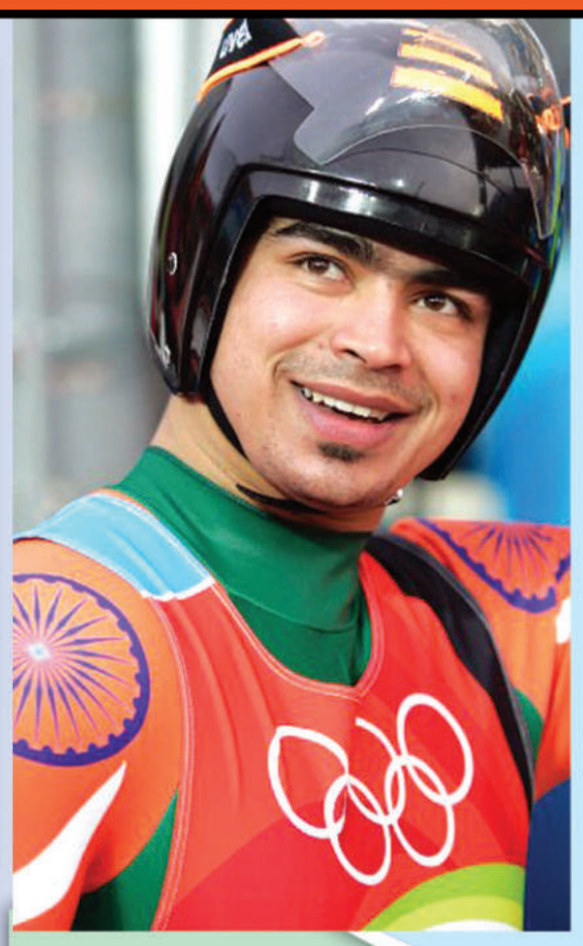

जज़्बे को सलाम

वर्ष 1998 में 16 वर्षीय शिवा जापान के शहर नगोया में विंटर ओलंपिक गेम्स विलेज के दरवाजे पर अंदर जाने के इंतार में खड़े थे. आयोजकों को पता ही नहीं था कि भारत की कोई एंट्री है या नहीं. 13 साल बाद शिवा ने नगोया में ही 134.3 किलोमीटर प्रति घंटे का नया एशियन स्पीड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा. लगातार संकट, दिक्कतों और पैसे की कमी ने हिमाचल के इस युवा को पीछे हटने के बजाय अगली पीढ़ी का आदर्श बना दिया. इस अनजान खेल में शिवा की अकेले दम पर लड़ी गई लड़ाई प्रेरित करने वाली है. हिमाचल में पले-बढ़े शिवा की मां इटालियन हैं और पिता केरल के. इटली ने उन्हें नागरिकता का प्रस्ताव भी दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया. बर्फ के ट्रैक पर तख्ते जैसे स्लेड पर फिसलने वाले इस खेल के लिए भारत में कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा नहीं है. हिमाचल में गर्मियों में सड़क पर पहिए वाले स्लेड और सर्दियों में बर्फ की ढलान पर अभ्यास करके शिवा यहां तक पहुंचे हैं. शिवा 131.9 का पिछला रिकॉर्ड तोड़कर पहली बार ग़ैर जापानी चैंपियन बने. इस पदक के बाद उनका भविष्य में और रिकॉर्ड तोड़ने का भरोसा मज़बूत हुआ है.

विरोध में असलम

ओलंपिक में डाउ केमिकल्स को लेकर काफी पहले से विवाद छिड़ा हुआ है. हॉकी ओलंपियन असलम शेर ख़ान का भी मानना है कि भारत सरकार, आईओए और एथलीटों को लंदन ओलंपिक में डाउ केमिकल्स के प्रायोजक बनने का कड़ा विरोध करते हुए खेलों का बहिष्कार करना चाहिए. 1975 की विश्वकप विजेता भारतीय टीम के सदस्य असलम ने कहा कि भारत यदि लंदन ओलंपिक खेलता है तो यह शर्मनाक होगा. एक ऐसी कंपनी इससे जुड़ी है, जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की कसूरवार है. कई देशों ने अतीत में भी ओलंपिक का बहिष्कार किया है. भारत और भारतीय खिलाड़ियों को एकजुटता दिखानी होगी. भारतीय ओलंपिक संघ के एक समारोह के दौरान असलम ने कहा कि ब्रिटिश संसद के 25 सदस्यों ने भी लंदन ओलंपिक से डाउ के जुड़ने का विरोध किया है. भारत सरकार और आईओए को भी ऐसा ही करना चाहिए. असलम ने उन खिलाड़ियों की निंदा की, जिन्होंने ओलंपिक के बहिष्कार के ख़िलाफ़ बयान दिए हैं. असलम ने कहा कि लंदन ओलंपिक के बहिष्कार का विरोध करने वाले खिलाड़ियों को ख़ुद पर शर्म आनी चाहिए. 15,000 से अधिक लोगों की मौत और हजारों लोगों का प्रभावित होना कोई मज़ाक नहीं है.

ये भी हैं लाइन में

खेलों में पहला भारत रत्न दिए जाने के लिए पूरे देश में ध्यानचंद और सचिन तेंदुलकर के नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन इस दौड़ में आधिकारिक रूप से शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी शूटर अभिनव बिंद्रा बन गए हैं. इस बीजिंग ओलंपिक गोल्ड मेडिलिस्ट के पक्ष में ख़ुद नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) उतर आया है. उसने अभिनव को भारत रत्न दिए जाने के लिए खेल मंत्रालय को पत्र लिखा. इसमें अभिनव की उपलब्धियां गिनाने के साथ उन्हें देश का एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता बताया गया. हालांकि भारत रत्न के लिए आवेदन गृह मंत्रालय के ज़रिए होना है, लेकिन एनआरएआई के एडवाइज़र बी एस सेठी का कहना है कि खेल मंत्रालय की हरी झंडी मिलने पर वह गृह मंत्रालय को भी लिखेंगे. सेठी ने कहा कि अभिनव की उपलब्धियां किसी से कम नहीं हैं. जो उन्होंने किया है, देश के खेलों के इतिहास में किसी दूसरे खिलाड़ी ने नहीं किया. एनआरएआई ने खेल मंत्री अजय माकन से अनुरोध किया है कि भारत रत्न के लिए एकमात्र दावा इस युवा शूटर का बनता है. खेल मंत्री को लिखे पत्र में एनआरएआई ने कहा है कि सब जूनियर, जूनियर स्तर की हर विश्वस्तरीय प्रतियोगिताएं जीतने के साथ शूटिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले अभिनव पहले शूटर हैं. उन्होंने छह वर्ल्ड कप के गोल्ड अपने नाम किए हैं. सबसे बढ़कर बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने देश को गोल्ड दिलाया. सेठी कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि फेडरेशन की इस पहल को स्वीकार किया जाएगा.

हॉकी टीम का कारनामा

काफी दिनों बाद हॉकी से जुड़ी कोई अच्छी ख़बर मिली है. भारतीय महिला हॉकी टीम ने हाल में आयरलैंड को 4-1 से हराकर अर्जेंटीना में चल रहे चार देशों के टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता. यह खेल काफी रोमांचक रहा, क्योंकि शुरुआती दौर में दोनों टीमें एक-दूसरे को बराबर से टक्कर दे रही थीं. हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर था, लेकिन भारत ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए तीन गोल दागे. भारत के लिए जसप्रीत कौर ने 26वें मिनट में, अनुराधा थोकचोम ने 58वें, वंदना कटारिया ने 68वें और रितु रानी ने 70वें मिनट में शानदार गोल दागे. आयरलैंड के लिए एकमात्र गोल एने कोनेरी (सातवें मिनट में) ने दागा. आयरलैंड ने सातवें ही मिनट में बढ़त बना ली थी, जिसे 26वें मिनट में जसप्रीत ने पेनाल्टी कार्नर पर गोल करके उतारा. दूसरे हाफ में भारतीयों ने ज़बरदस्त आक्रामक खेल दिखाते हुए तीन गोल किए. गोलकीपर योगिता बाली, डिफेंडर पिंकी थोकचोम, जसप्रीत कौर एवं प्रीति सुनीला ने आयरिश टीम के सभी हमलों को नाकाम कर दिया. अनुराधा ने 58वें मिनट में भारत को बढ़त दिलाई. वहीं इसके दस मिनट बाद वंदना ने स्कोर 3-1 कर दिया. रितु रानी और असुंता लाकड़ा के मूव पर उसने गोल दागा. अंतिम समय में प्रीति ने पेनाल्टी कार्नर को गोल में तब्दील करके भारत की 4-1 से जीत पर मुहर लगा दी. फाइनल में अर्जेंटीना ने दक्षिण अफ़्रीका को 2-0 से हराकर खिताब जीता.

लड़ाई अभी बाक़ी है

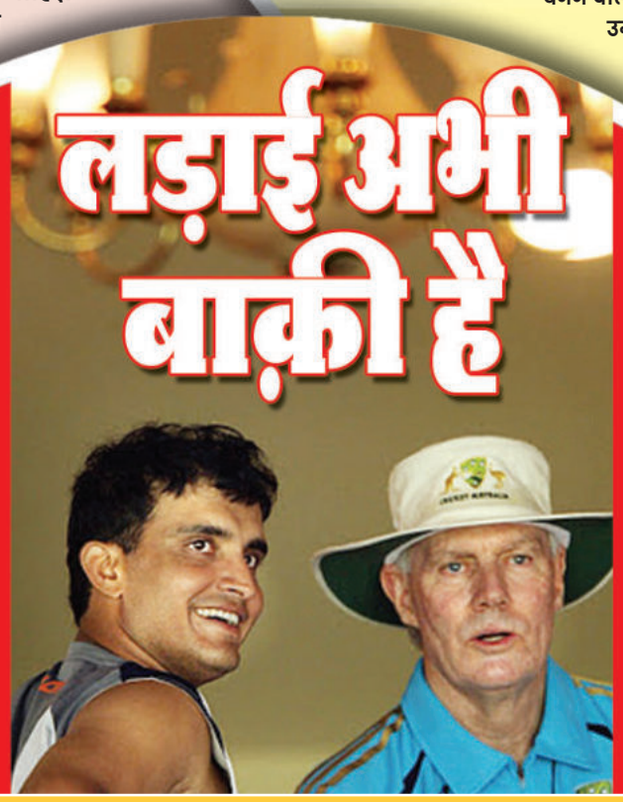

सौरव और चैपल के बीच अब तक की लड़ाई जगज़ाहिर है. अभी हाल में इस कड़ी में आशीष नेहरा ने अपना नाम जोड़ लिया है. उनके मुताबिक़, उनका अनुभव भी चैपल के साथ कुछ अच्छा नहीं था. ग़ौरतलब है कि अभी हाल में सौरव ने चैपल को पागल कहा था. सचिन तेंदुलकर और अन्य भारतीय बल्लेबाज़ों का तिलिस्म तोड़ने में आस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ों की मदद करने की रपटों पर गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम के लिए यह अच्छी ख़बर है. गांगुली के मुताबिक़, चैपल चयनकर्ता और ब्रिसबेन स्थित आस्ट्रेलियन सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रमुख रहे हैं. वहां से भी उन्हें हटा दिया गया. जब वह भारत आए तो कहा गया था कि आस्ट्रेलियाई मानसिकता यहां नहीं चलेगी, लेकिन वह आस्ट्रेलियाई ढांचे में भी काम नहीं कर सके. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि चैपल कोचिंग के हर काम में विफल रहे हैं, जो यह साबित करता है कि ग़लती उन्हीं में है. उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए कि खामी चैपल में ही है. वह ग़लती पर ग़लती करते हैं. कोई व्यक्ति एक बार ग़लत हो सकता है, लेकिन बार-बार वह ग़लती दोहराए और इसकी वजह से नौकरी गंवा दे तो वह पागल ही कहा जाएगा. चैपल को भारतीय टीम के कोच का पद दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले गांगुली की चैपल ने अपनी आत्मकथा में कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वह टीम में बेचैनी फैलाते थे. गांगुली ने कहा कि चैपल के जेहन में कभी भी भारतीय क्रिकेट की भलाई नहीं थी और वह अपनी योजनाएं थोपने में लगे रहे. अब देखना दिलचस्प होगा कि चैपल क्या जवाब देंगे.

गांगुली के मुताबिक़ , चैपल चयनकर्ता और ब्रिसबेन स्थित आस्ट्रेलियन सेंटर आफ एक्सीलेंस के प्रमुख रहे हैं. वहां से भी उन्हें हटा दिया गया. जब वह भारत आए तो कहा गया था कि आस्ट्रेलियाई मानसिकता यहां नहीं चलेगी, लेकिन वह आस्ट्रेलियाई ढांचे में भी काम नहीं कर सके. पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि चैपल कोचिंग के हर काम में विफल रहे हैं, जो यह साबित करता है कि ग़लती उन्हीं में है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं 2012

जनवरी

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

फरवरी

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

मार्च

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

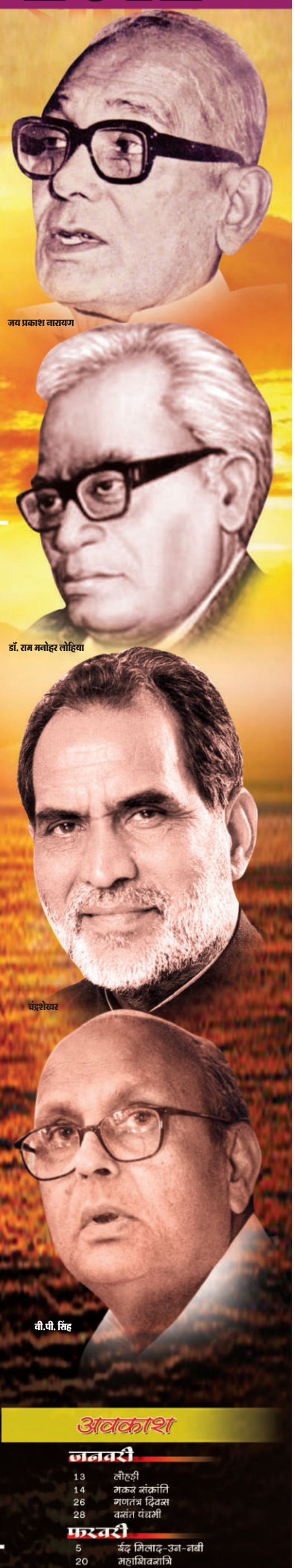

अप्रैल

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

मई

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
	28	29	30	31		

जून

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

जुलाई

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

अगस्त

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

सितंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

अक्टूबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

नवंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

दिसंबर

रवि	सोम	मंगल	बुध	गुरु	शुक्र	शनि
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

अवकाश

जनवरी
- 13 लोहड़ी
- 14 मकर संक्रांति
- 26 गणतंत्र दिवस
- 28 वसंत पंचमी

फरवरी
- 5 ईद मिलाद-उन-नबी
- 20 महाशिवरात्रि

मार्च
- 8 होली
- 23 शहीद दिवस/हिंदी नव वर्ष

अप्रैल
- 1 राम नवमी
- 6 हनुमान जयंती

मई
- 1 मई दिवस
- 6 बुद्ध पूर्णिमा

अगस्त
- 2 रक्षा बंधन
- 10 कृष्ण जन्माष्टमी
- 15 स्वतंत्रता दिवस
- 19 ईद-उल-फितर

सितंबर
- 19 गणेश चतुर्थी

अक्टूबर
- 2 गांधी जयंती
- 16 नवरात्री
- 24 विजयादशमी
- 26 ईद-उल-अजहा

नवंबर
- 13 दीपावली
- 14 बाल दिवस
- 24 गुरुपर्व

दिसंबर
- 25 क्रिसमस

चौथी दुनिया

दिल्ली, 02 जनवरी–08 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

किसानों को भीख नहीं भाव चाहिए

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

प्रवीण महाजन

विदर्भ में किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है. यह बात विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में 2000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित करके सरकार ने साबित कर दिया है. पैकेज भी सरकार ने कुछ इस अंदाज़ में घोषित किया मानो वह विदर्भ के किसानों पर अहसान कर रही हो. इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि राज्य में बैठी सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों में कृषि को प्रोत्साहित करने की न तो दूरदृष्टि है और न ही इच्छाशक्ति. इच्छाशक्ति व दूरदृष्टि के अभाव में ही सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं दिखाई दी, जबकि सत्र शुरू होने के पहले से पूरे राज्य में कपास, धान व सोयाबीन को लेकर आंदोलन की आग भड़क चुकी थी और अधिवेशन के दौरान भी किसान आंदोलनरत रहे. किसान आत्महत्या का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा. जिस दिन पैकेज घोषित किया गया उसी दिन विदर्भ के पांच किसानों द्वारा आत्महत्या करने की ख़बर सदन के अंदर और बाहर चर्चा का विषय बनी रही. इस पर भी सरकार को होश नहीं आया और समस्या को चलताऊ तरीके से पैकेज घोषित कर टाल दिया. इस पैकेज से एक बार फिर साफ़ हो गया कि गन्ना उत्पादकों के प्रति सरकार जो अपनापन दिखाती है वैसा अपनापन राज्य के कपास, धान और सोयाबीन उत्पादकों के प्रति नहीं रखती है. इससे उसके दोहरे चरित्र का पता चलता है.

सरकार ने यह पैकेज भी अपनी इच्छा से नहीं घोषित किया है, बल्कि आक्रोशित किसान आंदोलन से उपजे राजनीतिक दबाव के चलते जल्दबाज़ी में घोषित किया है. पैकेज घोषित करने के दौरान मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के भाषण से ऐसा लग रहा था मानो वह किसानों पर अहसान कर रहे हों. मुख्यमंत्री चव्हाण ने अपने भाषण में किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपये का पैकेज घोषित करते हुए कहा कि किसानों की मदद के लिए इतिहास में घोषित किया जाने वाला यह सबसे बड़ा पैकेज है. उन्होंने सदन को यह भी बताया कि बीज, खाद, बिजली में मिलने वाली सब्सिडी का सबसे अधिक लाभ बागायती किसानों को मिलता है. पूरे महाराष्ट्र में 13.53 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है. महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश में 41 लाख हेक्टेयर में कपास, 30 लाख हेक्टर में सोयाबीन और 15 लाख हेक्टेयर धान की बुआई होती है. इस तरह कुल 86 लाख हेक्टेयर में कपास, सोयाबीन और धान की खेती महाराष्ट्र में की जाती है. कपास का पिछले वर्ष की अपेक्षा कम उत्पादन हुआ, लेकिन तीन वर्ष के औसत के बराबर रहा है. सोयाबीन का पिछले वर्ष की अपेक्षा 26 फ़ीसदी उपज कम हुई पर तीन वर्ष के औसत के बराबर है. यही स्थिति धान की भी है. मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि गन्ने के पैकेज को लेकर ग़लतफहमी व्याप्त है. गन्ने को सरकार की तिजोरी से कोई ज़्यादा पैकेज नहीं दिया गया है, लेकिन कारखाना मालिक और गन्ना उत्पादकों को आमने-सामने बिठाकर समर्थन मूल्य सरकार ने तय करवाया है. उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गन्ने पर विविध प्रक्रिया होती है. उससे गुड़, शक्कर, लीकर (शराब), बिजली, एथेनाल बनता है. गन्ने के इन उत्पादों से सरकार को 5000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता हैं, जिसका फ़ायदा गन्ना उत्पादकों को मिलता है. इस अधिवेशन के अंत तक वं ोद्योग नीति की घोषणा कर दी जाएगी. भाषण के अंत में उन्होंने 2000 करोड़ रुपये के पैकेज से सभी कपास उत्पादकों को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मदद मिलने और सोयाबीन व धान के मामले में तहसील स्तर पर सर्वेक्षण होने के पश्चात जिन तहसीलों में 25 फ़ीसदी से कम उत्पादन हुआ होगा, उन्हें प्रति हेक्टर के हिसाब से मदद किए जाने की बात कही. इस भाषण के दौरान विशेष बात यह रही कि जब मुख्यमंत्री चव्हाण गन्ना और उसके अन्य प्रक्रियागत उत्पादों का लिखित भाषण पढ़कर गुणगान कर रहे थे तो उनकी बगल में बैठे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार बड़ी ही शिद्दत से व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेर रहे थे. सदन के बाहर यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री ने जो लिखित भाषण सदन में पढ़ा वह उप मुख्यमंत्री पवार का लिखा हुआ था. अब उनकी इस मुस्कान का रहस्य नगर परिषद के चुनाव परिणाम थे या कुछ और यह वही जानें पर इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री की बातों से राज्य का किसान निराश है.

मुख्यमंत्री चव्हाण के पैकेज की घोषणा पर किसानों के साथ ही सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों ने भी निराशा व्यक्त की. अब सवाल यह उठता है कि आनन-फानन में घोषित 2000 करोड़ रुपये के पैकेज से किसानों को कितनी राहत, कितनी मदद मिलेगी? उनको राहत देने के लिए सरकार ने यह पैकेज घोषित किया या पिछले पैकेजों की तरह यह भी छलावा ही साबित होगा? सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पैकेज से किसानों को किसी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है. दोनों पक्षों के विधायकों ने किसानों को प्रति हेक्टेयर 5000 रुपये के हिसाब से मदद देने की मांग की है, लेकिन मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि पैकेज में किसी तरह की बढ़ोतरी करने की कोई गुंजाइश नहीं है. इस पैकेज को पूरा करने के लिए अन्य विकास योजनाओं को आवंटित निधि में कटौती करनी पड़ेगी. वहीं खुद मुख्यमंत्री चव्हाण की पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पैकेज के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि सभी किसानों को प्रति हेक्टेयर कम से कम 5000 रुपये की मदद मिलनी चाहिए. ऐसी मांग कांग्रेस के सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री से की है. मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पैकेज से किसानों को केवल 700 से 800 प्रति हेक्टयेर ही मदद मिलेगी. इस रक़म को बढ़ाने की ज़रूरत है. मुख्यमंत्री को मदद की रक़म बढ़ाना पड़ेगा. चूंकि राज्य सरकार के पास कपास खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए वह समर्थन मूल्य नहीं दे सकती है. इसका मतलब साफ़ है कि मुख्यमंत्री के जल्दी में घोषित पैकेज को लेकर सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों का नज़रिया एक सा था और यह पैकेज किसानों के साथ पिछले पैकेजों की तरह मात्र छलावा साबित होने वाला है. सरकार की हमदर्दी कपास, धान व सोयाबीन उत्पादकों के साथ बिल्कुल भी नहीं है. उसकी हमदर्दी हमेशा शक्कर लॉबी के साथ रहती है और उन्हीं के दबाव में वह गन्ने के साथ अपनापन और कपास, धान, सोयाबीन के प्रति सौतेलापन जताती है.

अब उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कह रहे हैं कि विदर्भ के किसान पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों से सीख लें. मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर और बाहर जो भाषण व बयान दिया है वह पीड़ित किसानों के ज़ख्मों में मरहम लगाने की जगह नमक छिड़कने वाला है. वे विदर्भ के किसानों को सीख, सुझाव व सलाह देते समय भूल जाते हैं कि राज्य में खेतों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाले पानी की व्यवस्था ही नहीं है. वे यह भी भूल जाते हैं कि जितनी सुविधा पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के किसानों को दी जाती है उसका आधा भी विदर्भ के किसानों को नसीब नहीं है. यदि कृषि के लिए लगने वाले सारे संसाधन विदर्भ के किसानों को उपलब्ध कराने के प्रति शासन-प्रशासन ईमानदार होता तो वे आत्महत्या के लिए मज़बूर क्यों होते? मुख्यमंत्री ने गन्ने के बहुत गुणगान किए पर यदि राज्य में सारे किसान गन्ना ही उगाने लगें और अनाज की खेती बंद हो जाए तो राज्य का क्या हाल होगा? राज्य सरकार के रवैये को देख कर तो यही लगता है कि उसकी नज़र में गन्ने के आगे अन्य फ़सलों का कोई महत्व नहीं है. इसलिए कपास, धान, सोयाबीन उत्पादक मरते हैं तो उसे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है, लेकिन गन्ना उत्पादक दो दिन अनशन-आंदोलन करने लगे तो नत मस्तक हो जाती है. एक तरह से गन्ना उत्पादकों को जहां सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, वहीं कपास, धान उत्पादक पूरी तरह उपेक्षित हैं. इससे सरकार का कृषि के प्रति नज़रिया भी स्पष्ट हो जाता है. इसलिए सरकार अब तक राज्य के किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सुदृढ़ कृषि नीति बनाने के प्रति गंभीर नज़र नहीं आती है. समस्याओं को राजनीतिक नफ़े-नुक़सान का जोड़तोड़ कर पैकेज-पैकेज का खेल खेल रही है. पिछले प्रधानमंत्री व राज्य सरकार के घोषित पैकेजों का क्या हश्र हुआ और उससे किसको फ़ायदा हुआ, यह सर्वविदित है. राहुल गांधी एक ओर उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान के दरम्यान बार-बार कहते हैं कि पैकेजों से मंत्रियों ने फ़ायदा उठाया है तो महाराष्ट्र में कृषि-कृषक के उद्धार के लिए घोषित पैकेजों से किसका घर भरा है, क्या यह बात कांग्रेस का कोई नेता बताने का कष्ट करेगा?

एक तरह से यदि यह कहा जाय कि सरकार ने जो पैकेज घोषित किया है वह राजनीतिक अधिक है तो अतिश्योक्ति नहीं होगी, लेकिन इस पैकेज से सरकार को क्या लाभ होगा? लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ गठबंधन के दो बड़े घटक दलों में खींचतान जारी है यह ग़ौर करने वाली बात है. उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने नागपुर निवास स्थान में कुछ संपादकों से चर्चा करते हुए विदर्भ के नेताओं से लेकर जनता तक की खिंचाई की और साफ़ शब्दों में कहा कि विदर्भ के नेताओं एवं उनके नेतृत्व में स्थापित ट्रेड यूनियनों के अड़ियल रवैये से नागपुर व चंद्रपुर के कई उद्योग प्रभावित हुए हैं. इन उद्योगों का हाल देखकर कोई नया उद्योगपति यहां आना नहीं चाहता है. विदर्भ की बदहाली के लिए यहां की जनता की खिंचाई करते हुए आश्चर्य जताया कि उन्हें समझ नहीं आता है कि वह आपसी खींचतान करने वाले नेताओं को ही बार-बार निर्वाचित क्यों करते है? उनकी इन बातों से तो यही लगता है कि वे विदर्भ की जनता को जो राजनैतिक इशारा कर रहे हैं, उसका मक़सद यही हो सकता है कि उनकी पार्टी को विदर्भ की जनता सहारा दे, लेकिन अजीत पवार शायद यह भूल रहे हैं कि वे राज्य के वित्तमंत्री हैं और उनसे जनता यह अपेक्षा करती है कि वे जनहित के मामले में राजनीतिक अखाड़े के बाहर आकर पूरे राज्य के किसानों व जनता के साथ एक-सा न्याय करें. वित्त का विभाजन सामान स्तर पर हो, लेकिन उनका दृष्टिकोण राजनीति से प्रभावित व संकुचित है. इसलिए वे जहां गन्ना उत्पादकों के लिए सरकार की तिजोरी का मुंह पूरा खोलने का तैयार हो जाते हैं, वहीं विदर्भ के किसानों के लिए उनकी तिजोरी का मुंह संकुचित हो जाता है. सरकार इस बार भी पैकेज की भूलभुलैया में भटकने को किसानों को छोड़ दिया है.

feedback@chauthiduniya.com

सदन के बाहर यह चर्चा थी कि मुख्यमंत्री ने जो लिखित भाषण सदन में पढ़ा वह उप मुख्यमंत्री पवार का लिखा हुआ था. अब उनकी इस मुस्कान का रहस्य नगर परिषद के चुनाव परिणाम थे या कुछ और यह वही जानें पर इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री की बातों से राज्य का किसान निराश है. मुख्यमंत्री चव्हाण के पैकेज की घोषणा पर किसानों के साथ ही सत्तापक्ष व विपक्ष के विधायकों ने भी निराशा व्यक्त की.

हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई. जाओ,.... खूब जाओ.... डर्टी–फर्टी देखने. विद्या बालन को घर में बुलवा कर डांस कराओ, नो प्राब्लम.

महाराष्ट्र में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है. यहां पिछले दिनों चंद्रपुर ज़िले में एक दुर्घटना में बाघ के शावक की मौत होने का पता चला था.

महाराष्ट्र हलचल

अमरावती के मोझर स्थित गुरुकुंज आराखड़ा आश्रम में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, विधायक यशोमति ठाकुर आश्रम के अधिकारियों से चर्चा करते हुए.

महाराज्य आंगनवाड़ी–बालवाड़ी में कार्यरत हज़ारों महिला कर्मचारियों ने शीतसत्र के दौरान अपनी मांगों व समस्याओं के समाधान के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए.

नागपुर विधानभवन के विधानसभा कक्ष में विधानसभाध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की मौजूदगी में विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते उपमुख्यमंत्री अजीत पवार.

नागपुर विधानभवन में आयोजित 41वें राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्ग में उपस्थितों का मार्गदर्शन करते विधानसभा उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके.

राज्य में पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों और उनकी सुरक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से उनके नागपुर कार्यालय में चर्चा करते हुए पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल.

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को मुबई स्थित इंदू मिल की ज़मीन चैत्यभूमि को देने के संदर्भ में निवेदन देकर चर्चा करते रिपाई नेता राजेन्द्र गवई, विधायक नीलेश पारवेकर व अन्य.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के आयुक्तालय के उद्घाटन अवसर पर प्रकाशित रोहयोच्या ग्राम परिवर्तनाचे नवे पाऊल पुस्तिका का विमोचन करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, रोगायो मंत्री डॉ. नितिन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजी राव मोघे, ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, गुलाबराव देवकर, सतेज पाटिल, प्रधान सचिव वी. गिरीराज व अन्य.

दलित राजनीति

श्रेय लेने की मची होड़

राजेश नामदेव

राज्य में किसान आंदोलन के मध्य में नगर पालिका चुनाव संपन्न हो गए. राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी राजनीतिक गर्मी के बीच उपलब्धियों के मामले में ठंडा ही कहा जाएगा, लेकिन विधानसभा का पिकनिक सत्र (विदर्भवासियों के लिहाज़ से राज्य विधानसभा का शीतसत्र को पिकनिक सत्र ही कहा जाता है) के पहले ही दलित समाज के बीच अपना–अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाने के लिए राजनीतिक बिसात पर इंदू मिल को नया मोहरा बना लिया गया. अब राज्य की दलित राजनीति इंदू के बिन्दु के चहुंओर घूमती नज़र आ रही है. चूंकि मामला दलित–पिछड़े समाज के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का है तो कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है. अब यह अलग बात है कि इंदू मिल की ज़मीन पर डॉ. बाबासाहब आंबेडकर स्मारक जब बनेगा तब, लेकिन उसका श्रेय हासिल करने के लिए राजनीति सभी रिपब्लिकन गुटों व अन्य राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही है.

अब सवाल यह उठता है कि राजनीतिक बिसात पर इंदू मिल को नया मोहरा बनाने को बढ़ावा किसने दिया? इसके लिए हमें सात माह पीछे जाकर राजनीतिक घटनाओं और नेताओं की बयानबाजी को देखना होगा. इंदू मिल को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का स्मारक बनाने की बात पहले भी कभी–कभार उठती रही है. वर्तमान पृष्ठभूमि में इस मुद्दे को सबसे पहले हवा दी राष्ट्रवादी कांग्रेस ने. दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राकांपा नेतृत्व ने वर्ष 2011 के प्रारंभ से प्रयास तेज़ कर दिए थे. राकांपा के नेताओं को यह अच्छी तरह पता है कि राज्य में अपनी सहयोगी कांग्रेस से आगे निकलना है तो उसके जनाधार में सेंध लगानी होगी. इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जून माह में राकांपा के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में पार्टी नेता व राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने भाषण में दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर चैत्यभूमि रखने की बात कही थी. उन्होंने इस भावनात्मक मुद्दे को राजनीतिक फ़ायदे के लिहाज़ से ही छेड़ा था. इसके बाद ही कुछ आंबेडकरवादी संगठनों ने इंदू मिल की ज़मीन डॉ. बाबासाहब आंबेडकर स्मारक को देने की बात कही थी. तब कांग्रेस को लगा था कि कहीं राकांपा दलित राजनीति में आगे न निकल जाए इसलिए पार्टी प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे ने अपने दलित सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण से मिलकर 60 सूत्रीय मांग उनके समक्ष रख कर दलित, पिछड़ों और अल्पसंखयकों को न्याय दिलाने की मांग की थी. मांग में डॉ. बाबासाहब आंबेडकर प्राधिकरण गठित करने, पिछड़े–दलित समाज के छात्र–छात्राओं की स्कारलशिप बढ़ाने सहित कई मांगे शामिल थीं. उसके बाद रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले ने भी इंदू मिल की ज़मीन को डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के स्मारक बनाने को देने की मांग की थी, जिसका शिवसेना व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं ने विरोध भी किया था. इंदू मिल की ज़मीन के मामले में रामदास अठावले और शिवसेना के बीच मतभेद आज भी बरकरार है.

डॉ. आंबेडकर की 6 दिसंबर को पुण्यतिथि के दिन इंदू मिल में जो घटना घटी उसके पीछे भी रामदास अठावले की भूमिका महत्वपूर्ण है. यह तो सर्वविदित है कि दादर स्थित चैत्यभूमि से लगी इंदू मिल की ज़मीन डॉ. आंबेडकर स्मारक को दिए जाने की मांग रिपब्लिकन पार्टी के विविध गुट व अन्य दलित संगठन लंबे समय से करते रहे हैं. इसके लिए सभी अब तक अलग–अलग ही आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन जब से राज्य में सत्तारूढ़ दलों के आपसी संघर्ष में यह मुद्दा उठा है, तब से इसके लिए राजनीतिक दलों में श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है. इसलिए तो राकांपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व समता समाज मंच के अध्यक्ष विजय कांबले ने जहां 3 दिसंबर से इंदू मिल के नज़दीक अनशन पर बैठे. वहीं रामदास अठावले ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि इंदू मिल का सवाल 6 दिसंबर तक डॉ. आंबेडकर स्मारक को देने का निर्णय नहीं लिया गया तो उसके बाद कभी भी हमारे कार्यकर्ता धावा बोलकर उस पर कब्ज़ा कर लेंगे. उसके बाद रिपब्लिकन सेना के प्रमुख आनंदराज आंबेडकर ने भी इंदू मिल पर 6 दिसंबर को कब्ज़ा करने की घोषणा कर दी. आनंदराज ने न केवल घोषणा की, बल्कि 6 दिसंबर को इंदू मिल की सुरक्षा में तैनात पुलिस चक्रव्यूह को तोड़कर उस पर अमल भी कर दिया. अब यह भी कहा जा रहा है कि इस वाकये में रामदास अठावले के समर्थक भी शामिल थे. अठावले ने भी पहले ही कह दिया था कि यदि आनंदराज इंदू मिल पर कब्ज़ा करने का प्रयास करेंगे तो उनके समर्थक उस कार्रवाई का समर्थन करेंगे. विशेष बात यह है कि वहां तैनात पुलिस 600–700 लोगों की भीड़ के सामने कमजोर साबित हुआ. शासन–प्रशासन इस मामले में तमाशबीन बना रहा

ग़ौरतलब है कि राज्य सरकार ने इंदू मिल पर रिपब्लिकन सेना द्वारा क़ानून हाथ में लेते हुए जबरन कब्ज़े की कार्रवाई करने का किसी तरह विरोध नहीं किया. ना ही किसी नेता ने उक्त घटना की आलोचना की. इसके कारण राजनीतिक थे. राज्य में नगरपरिषद चुनाव के लिए कुछ ही दिन बाद मतदान होने थे. उसके बाद महानगर पालिका और ज़िला परिषद के चुनाव हैं. इन स्थितियों में कोई राजनेता या राजनीतिक दल यह नहीं चाहता कि उससे दलित–पिछड़े वर्ग के मतदाता नाराज़ हों. इसकी बजाय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 6 दिसंबर को इस घटना के बाद कहा कि डॉ. बाबासाहब आंबेडकर के स्मारक के लिए इंदू मिल की संपूर्ण ज़मीन देने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र को भेजा है. साथ ही यह अनुरोध किया है कि प्रस्ताव को शीघ्र मंजूर किया जाए. इसके लिए राज्य सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. दूसरी ओर केंद्र सरकार ने डॉ. आंबेडकर के स्मारक के लिए इंदू मिल की चार एकड़ ज़मीन देने को तैयार हो गई, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के रामदास अठावले सहित अन्य दलित समाज के संगठनों ने पूरी ज़मीन की मांग की है. रामदास अठावले ने तो राज्य के विधानमंडल के शीत सत्र के दौरान नागपुर आकर मोर्चा भी निकाला और कई मंत्रियों से भी मुलाकात की. दलित पिछड़े समाज के विविध संगठनों ने 15 दिसंबर को राज्य के कई ज़िलों में पुनः आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए और अंतिम समय तक लड़ने की घोषणा तक कर दी है. रामदास अठावले ने यह भी कहा कि ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली में भी इंदू मिल की ज़मीन हासिल करने के लिए आंदोलन करेंगे. इससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि सत्तारूढ़ दलों की राजनीतिक चाल से उपजी यह आग भविष्य में और भड़क सकती है. यदि इसका समाधान शीघ्र नहीं निकाला जाता है तो सत्तारूढ़ दलों की यह चाल उन्हीं के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है जिसका असर आगामी मनपा व ज़िला परिषद के चुनाव में पड़ना तय माना जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

शिवशक्ति–भीमशक्ति में मनभेद

इंदू मिल की ज़मीन डॉ. बाबासाहब आंबेडकर स्मारक को दिए जाने को लेकर रिपब्लिकन नेता रामदास अठावले और शिवसेना नेता बालसाहब ठाकरे के बीच मतभेद हैं. इस मतभेद–मनभेद के चलते शिवशक्ति व भीमशक्ति के गठबंधन के मध्य दरार गहरा सकती है. ग़ौरतलब है कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले मराठवाड़ा विश्वविद्यालय सहित अन्य सभी पिछली घटनाओं को भुलाकर शिवसेना से हाथ मिलाने का फैसला लिया था. उनके इस फ़ैसले को उनके समर्थकों ने बड़े ही संकोच के साथ स्वीकार किया था और नई शुरुआत का आगाज़ किया था, लेकिन दशहरा को मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित शिवसेना की रैली में बालासाहब ठाकरे ने साफ–साफ शब्दों में इंदू मिल की ज़मीन डॉ. आंबेडकर को देने की बजाय समाज सुधारक नाना शंकर सेठ स्मारक को देने को कहा था. इस पर रिपब्लिकन पार्टी के विविध गुट के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. अब एक बार फिर इंदू मिल का मामला गरम हो गया है. रामदास अठावले ज़मीन को जहां डॉ. आंबेडकर स्मारक को दिलाने के लिए खुलकर संघर्ष करने का ऐलान कर दिया है. वहीं शिवसेना ने अब तक 6 दिसंबर को इंदू मिल पर रिपब्लिकन सेना द्वारा कब्ज़ा किए जाने की घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है. उसकी यह चुप्पी रहस्य बनी हुई है. कहा जा रहा है कि इंदू मिल प्रकरण पर शिवसेना ने कूटनीतिक चुप्पी साध रखी है. वह रामदास अठावले के इस कदम से खुश नहीं है.

कांग्रेस की मुश्किल बढ़ी

कांग्रेस के रणनीतिकारों ने सोचा था कि इंदू मिल ज़मीन डॉ. आंबेडकर स्मारक को देने का प्रकरण को अटका कर शिवशक्ति–भीमशक्ति के बीच तनाव बढ़ाने पर उसे सफलता मिलेगी. रामदास अठावले की दलित समाज में पकड़ को कमजोर कर सकेगी, लेकिन कांग्रेस की यह चाल अब उसे के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है. इंदू मिल पर जैसे–जैसे दलित संगठनों का आंदोलन तेज़ हो रहा है उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. राज्य सरकार इंदू मिल की ज़मीन को डॉ. आंबेडकर स्मारक को देने में जितना देर करेगी, उतना ही आक्रोश दलित समाज का कांग्रेस के प्रति बढ़ता जाएगा. 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री चव्हाण ने इंदू मिल ज़मीन डॉ. आंबेडकर को दिए जाने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजे जाने की बात कहकर दलित समाज के लोगों को शांत करने का प्रयास जरूर किया है पर देरी होने का खामियाजा कांग्रेस को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है, लेकिन राकांपा नेता शरद पवार ने इंदू मिल डॉ. आंबेडकर स्मारक को यथाशीघ्र देने की बात कह कर दलितों को लुभाने की एक और चाल चल दी है.

राकांपा की लुटिया डुबोने पर तुले देशमुख

विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस का तेज़ी से विस्तार तब हुआ, जब अजीत पवार ने पार्टी को संचालित करना शुरू किया. उसके पहले उसके विस्तार की गति थम सी गई थी. जिस नेता को विदर्भ में राकांपा को बढ़ाने की ज़िम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने सौंपी थी, वह सिर्फ उनके निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित रह गया है. वह अपनी स्वार्थ नीति के कारण न कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर सके और न पार्टी के हित में कोई निर्णय ले सके. इसके बावजूद अनिल बाबू देशमुख विदर्भ में खुद को राकांपा का एकमेव नेता मानते हैं और पार्टी का संचालन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह करते नज़र आते हैं. यही वजह है कि नगर परिषद चुनाव में नागपुर ज़िले में खुद अनिल बाबू देशमुख अपने गृहनगर काटोल की नगर परिषद में अपनी लाज नहीं बचा सके. ज़िले की बाकी नगर परिषदों में उनकी स्वार्थी नीतियों के कारण राकांपा को अपेक्षित सफलता नहीं मिली.

महाराष्ट्र में अनिल देशमुख को सदाबहार नेता के रूप में जाना जाता है. उनकी विशेषता यह है कि वे हमेशा सत्ता में बने रहते हैं. सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल करने में हमेशा कामयाब रहे हैं. इसके लिए उन्हें दलबदल का सहारा लेना पड़े तो भी वे किसी तरह का संकोच नहीं करते हैं. वर्ष 1995 में जब राज्य में शिवसेना–भाजपा की सरकार थी तब भी वे उसमें मंत्री थे. युति सरकार का पतन हुआ तो शिवसेना–भाजपा को त्यागकर कांग्रेस में शामिल हो गए. उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी तब भी मंत्री बने. कांग्रेस का विभाजन करने बाद जब शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई तो उसमें शामिल हो गए. कहने का मतलब यह है कि विदर्भ की राजनीति का चाकलेटी चेहरा यानी अनिल देशमुख जब से विधान मंडल के गलियारों में गए तब से वह सत्तापक्ष में ही चमकते नज़र आए. वे काटोल से सतत अपनी विजय पताका फहरा कर सत्ता का सुख भोगते रहे. यदि किसी को राजनीतिक अवसरवादिता का पाठ पढ़ना हो तो वह अनिल देशमुख से सीखे. आखिर वे पिछले 16–17 सालों से सतत कैसे राज्य मंत्रिमडल का सदाबहार चेहरा बने हुए हैं. ऐसे नेता को विदर्भ में राकांपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व ने सौंपी थी, लेकिन वे अपने ही हित साधने में ज्यादा मगन रहे हैं. पिछले दिनों संपन्न नगर परिषद चुनाव में राकांपा को विदर्भ में जो सफलता मिली है वह उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत पवार द्वारा खड़ी की गई टीम के कारण मिली है. गोंदिया में राजेंद्र जैन, तिरोड़ा में पूर्व विधायक. दिलीप बंसोड, भंडारा में सुनील फुंडे व धनंजय दलाल, बुलढाणा ज़िले में राजेंद्र शिंगणे, यवतमाल में नगर परिषद चुनाव के लिए विधायक संदीप बाजोरिया की मेहनत को श्रेय जाता है. नागपुर में राकांपा विफल साबित हुई, क्योंकि यहां की जिम्मेदारी जिस नेता को सौंपी गई थी वह पार्टी को बढ़ाने की बजाय अपना कद बढ़ाने के लिए प्रयास करता नज़र आया, लेकिन अनिल बाबू को अपने प्रयास में भी कोई सफलता नहीं मिली. काटोल में अनिल बाबू ने राकांपा को बढ़ावा देने की बजाय कांग्रेस के चरण सिंह ठाकुर के साथ जनसेवा गठबंधन बना अपने उम्मीदवार उतारे. अलिन बाबू के जनसेवा गठबंधन को राहुल देशमुख के नेतृत्व वाले शेकाप ने 21 में से 13 सीट जीत कर पटकनी दे दी. आखिर जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह अपने ही बनाये गढ़ढे में गिरता है. ऐसा ही अनिल देशमुख के साथ हुआ है. मज़ेदार बात यह है कि चरण सिंह और किरण पांडव का सहारा लेने के बाद भी काटोल नगर परिषद अनिल बाबू बचा नहीं सके.

जिस नेता को अपने निर्वाचन क्षेत्र की नगर परिषद चुनाव की नैया पार करने के लिए किसी और स्थानीय नेता के नेतृत्व वाली ग्रामीण विकास आघाड़ी से गठबंधन करना पड़ा. उससे सवाल यह उठता है कि जिस नेता ने राकांपा का मंत्री रहने के बावजूद अपने निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी को मजबूत नहीं कर सका, वह भला पार्टी का क्या हित कर सकेगा और विदर्भ का क्या नेतृत्व कर सकेगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है, क्योंकि अनिल देशमुख जैसे अवसरवादी नेता ने राकांपा को बढ़ाने की बजाय अपना कद बढ़ाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही किनारे लगाने का पहला काम किया है. अनिल देशमुख ने राकांपा में आने के बाद सबसे पहला काम किया पार्टी नेतृत्व का विश्वास हासिल करने का. जब अनिल देशमुख ने शरद पवार का विश्वास हासिल कर लिया तो दूसरा काम किया दता मेघे जैसे वरिष्ठ नेता के पर काटने का. यह ध्यान रखना चाहिए कि दत्ता मेघे उन नेताओं में हैं जिन्होंने कांग्रेस से अलग होने पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस की स्थापना में न केवल महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, बल्कि विदर्भ में पार्टी को सम्मानजनक स्थिति में खड़ा किया. ऐसे नेता को अनिल देशमुख की कुटिल राजनीति के कारण ही राकांपा से अलग होना पड़ा. इसी के साथ राकांपा को वाट लगाने का अनिल देशमुख मिशन शुरू हो गया. अनिल देशमुख का दत्ता मेघे के बाद अगला निशाना बने गिरीश गांधी, सुनील शिंदे और रमेश बंग. गिरीश गांधी को राकांपा का नागपुर शहराध्यक्ष पद भी अनिल देशमुख के कारण ही गंवाना पड़ा. सुनील शिंदे को तो राजनीति से ही बाहर होना पड़ा. रमेश बंग की विधायकी छीन ली. इसी तरह जब अनंतराव घारड विधान परिषद चुनाव के लिए खड़े हुए तो उनके लिए भी अनिल देशमुख ने गड्ढा खोदने का काम किया. धर्म की राजनीति करने वाली पार्टी का साथ दिया और काटोल–मोवाड़– नरखेड़ में अनंतराव घारड को हराने के लिए मतदाताओं को उनके ख़िलाफ़ वोट डालने को उकसाया. देशमुख ने अपने स्वार्थ की ख़ातिर पार्टी से दगा किया.

इतना ही नहीं अनिल देशमुख और उनके निजी सेक्रेटरी पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए. अख़बारों में समाचार भी प्रकाशित हुए. विधानसभा में विपक्षी दल के नेताओं ने बार–बार गंभीर आरोप लगाए. बीपीए घोटाला, डिप्टी कलेक्टर साठवणे को जिंदा जलाए जाने के मामले में भी अनिल देशमुख के निजी सेक्रेटरी का नाम चर्चाओं में रहा है, लेकिन अनिल देशमुख व उनके सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ शासन–प्रशासन ने कभी जांच करने की जहमत नहीं उठाई. देशमुख के नज़दीकी लोगों की मानें तो सब कुछ सेटिंग कर लिया जाता है. नागपुर के कुछ स्थानीय नेता अक्सर बातचीत में यह कहते सुने जाते है कि नागपुर के हर राशन दुकानदार से हज़ारों रुपये हफ्ते के रूप में वसूल किए जाते हैं, जो निज़ी सचिव के मार्फत उनके ख़जाने में पहुंचता है, लेकिन सत्ता के पावर का इस्तेमाल करके अनिल देशमुख अपने ख़िलाफ़ उठने वाले हर मामले को दबा देते हैं. यह भी कहा जाता है कि अनिल देशमुख अपने निजी सेक्रेटरी को किसी भी हालत में अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि उसको अलग किया तो वह उनका पूरा काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख देगा. इसी के चलते विपक्षी दलों के बार–बार आरोप करने के बाद भी अनिल बाबू अपने सेक्रेटरी की हर जायज़–नाजायज़ हरकतों को नज़रअंदाज़ करने में ही अपनी भलाई समझते हैं. उनके कई समर्थक कहते हैं कि जब तक सत्ता के साथ अनिल देशमुख चिपके हैं तब तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.

महाराष्ट्र में अनिल देशमुख को सदाबहार नेता के रूप में जाना जाता है. उनकी विशेषता यह है कि वे हमेशा सत्ता मे बने रहते हैं. सत्ता में अपनी भागीदारी हासिल करने में हमेशा कामयाब रहे हैं. इसके लिए उन्हें दलबदल का सहारा लेना पड़े तो भी वे किसी तरह का संकोच नहीं करते हैं. वर्ष 1995 में जब राज्य में शिवसेना-भाजपा की सरकार थी तब भी वे उसमें मंत्री थे. युति सरकार का पतन हुआ तो शिवसेना-भाजपा को त्यागकर कांग्रेस में शामिल हो गए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ये क्या हो रहा है...

आवाज़ बंद करना लोकतांत्रिक नहीं

राज्य में लोकतंत्र है या नहीं. यहां जनता के हित में जो बोलता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है. यह भला कहां का न्याय है? इसे लोकतांत्रिक पद्धति तो नहीं कहा जा सकता है. यह तो सरासर तानाशाही है. राज्य का किसान अपनी उपज की सही क़ीमत पाने के लिए आंदोलनरत हैं. हमारे विधानसभा में बैठने वाले माननीय सत्तापक्ष–विपक्ष के नेता मदमस्त विद्या बालन का दर्शन करने के लिए मुंह छुपा कर डर्टी पिक्चर देखने जाते हैं. हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई. जाओ,.... खूब जाओ.... डर्टी –फर्टी देखने. विद्या बालन को घर में बुलवा कर डांस कराओ, नो प्राब्लम. पहले भी अपनी पार्टियों में मदहोश अदाओं वाली नचनियों को बुलाकर नेता पार्टियों में नचाते रहे हैं, तब भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की और आज भी नहीं कर रहा है फिर मुंह छुपाकर जाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा हुआ जो हमारे माननीयों ने डर्टी पिक्चर देख ली. इससे जनता को भी फिल्म देखने को प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन माननीयों को यह क्या हो रहा है? आप लोग डर्टी पिक्चर देख कर आए तो आपसे यह अपेक्षा थी कि आप ने उससे कुछ सबक लिया होगा. उसको देखने के बाद आप कोई डर्टी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि डर्टी पिक्चर देखने के बाद आप लोगों ने कोई सबक नहीं लिया. सदन के अंदर आते ही आप ने अपनी डर्टी हरकतें करनी शुरू कर दीं. किसानों के हित में आवाज़ बुलंद करने वाले विधायकों के सदन के अंदर बोलने की आज़ादी छीन ली. विपक्ष के उन तीन विधायकों को निलंबित कर दिया जिनके द्वारा किसानों के प्रति असंवेदनशील सरकार का विरोध किया जा रहा था. यानी सदन के सिंहासन में बैठकर हमारे माननीय पूरी तरह सरकार के होकर रह गए हैं. अरे भाई, धान की क़ीमत मिलेगी नहीं तो किसान धान को जलाएगा नहीं तो क्या करेगा? वैसे भी आपकी की सरकार किसानों की समस्या को गंभीरता से लेने की बजाय पैकेज...पैकेज का खेल खेल रही है. आप भी किसानों के दुख–दर्द के मर्म को समझना नहीं चाहते हैं. इसलिए तानाशाह हेडमास्टर की तरह अपनी क्लास से उन विपक्षी विधायकों को बाहर निकाल दिया जो किसानों की गुहार सरकार के मदहोश कानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे. आपको जनता के हित से अधिक सरकार की हित की चिंता लगती है. इसलिए पहले विधायक नाना पटोले और उसके बाद पाशा पटेल और केशव मानकर को सदन की सदस्यता से निलंबित कर दिया. सदन के सदस्यों ने इसका विरोध भी किया, पर आप पर कोई असर नहीं हुआ. अनुशासन का पाठ कभी–कभी सरकार को भी पढ़ाना चाहिए. सरकार अक्सर जनता के प्रति अपने कर्तव्य को भूल जाती है. मंत्री तो आश्वासन और वायदे करते ही भूलने के लिए हैं. उनकों कभी हमारे माननीयों ने अनुशासन का पाठ पढ़ाने या उनके कर्तव्यों की याद नहीं दिलाई. विरोध की आवाज़ को कुचलना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. यदि सरकार ने किसानों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करती तो विपक्षी दलों को आंदोलन करने या विधान भवन परिसर में धान जला कर विरोध जताने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संकट में हैं वनराज

महाराष्ट्र सहित देश में बाघ फिर ख़तरे में है. वर्ष 2008 में 1411 तक पहुंची बाघों की संख्या वर्ष 2011 में भले ही 1706 तक पहुंच गई हो, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर आज भी सवाल उठाए जा रहे हैं. हालत यह है कि पिछले एक वर्ष में अलग–अलग कारणों से देश में 51 बाघों की मौत हो चुकी है. बाघों की संख्या बढ़ने पर अपने ही हाथों से अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार और प्रशासन वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इस रिपोर्ट से सकते में आ गया है. इस रिपोर्ट के मद्देनज़र महाराष्ट्र में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों के संरक्षण की स्थिति भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती है. यहां पिछले दिनों चंद्रपुर ज़िले में एक दुर्घटना में बाघ के शावक की मौत होने का पता चला था. एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया था. दिसंबर माह में एक बाघ का शव कुंए में मिला. एक प्राणी संग्रहालय में पिछले दो–तीन वर्षों में सही उपचार और भोजन के अभाव में वन्यजीवों के मरने की ख़बरें भी सामने आ चुकी हैं. वर्ष 1997 में देश में लगभग 3508 बाघ थे, लेकिन 11 वर्षों बाद वर्ष 2008 में जब इनकी गिनती हुई, तो यह संख्या 1411 तक पहुंच गई. इससे पूरे देश में हड़कंप मच गया था. सरकार और प्रशासन के स्तर पर कई बैठकें हुईं और केंद्र सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए कड़े उपायों की घोषणा कर दी. देश के अलग–अलग राज्यों में बाघों के लिए सुरक्षित रखे गए वनों में ख़ास नज़र रखने के लिए उपाय किए गए. बाद में जब वर्ष 2011 में बाघों की गिनती की गई तो यह बढ़कर 1508 से 1865 तक यानी औसतन 1706 तक पहुंची. संख्या बढ़ने की रिपोर्ट आते ही सरकार और प्रशासन ने इसका व्यापक तौर पर प्रचार–प्रसार कर वाहवाही लूटी, लेकिन इस रिपोर्ट को आए एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने फिर वन्यजीव प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है.

महाराष्ट्र में सात बाघों की मौत

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में पिछले एक वर्ष में 51 बाघों की मौत हो चुकी है. इसमें प्राकृतिक मृत्यु अज्ञात कारणों से 17, शिकार के कारण 12,

वर्चस्व के लिए संघर्ष में 9, अन्य प्राणियों से हुए संघर्ष में 4, वन विभाग, पुलिस व ग्रामीणों के हमले में 4, दुर्घटना में 2, उपचार के दौरान 2 और करंट लगने से 1 बाघ की मौत हुई. इनमें से 7 बाघों की मौत महाराष्ट्र में हुई. वहीं उत्तराखंड में सबसे अधिक 14 बाघों की मौत हुई है. कर्नाटक में 6 और मध्य प्रदेश में 5 बाघ मारे गए. शिकार और वन विभाग, पुलिस व ग्रामीणों के हमले में मारे गए बाघों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 16 तक पहुंच जाता है. ग़ौरतलब है कि बाघों की घटती संख्या पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी चिंता ज़ाहिर की थी. बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट पर उनकी ख़ास नज़र है. वन विभाग ने भी समय–समय पर कई बार यह कहा है कि बाघों की सुरक्षा और शिकार को रोकने के लिए उन्होंने व्यापक उपाय किए हैं, लेकिन संस्था की इस रिपोर्ट ने सभी दावों की पोल खोल दी है.

पद रिक्त, हाथ खाली

वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका वन्य सुरक्षा कर्मियों की होती हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार इसके हज़ारों पद खाली है. कहीं–कहीं सैकड़ों एकड़ जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी महज़ कुछ सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर है. वहीं इन सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा के लिए बंदूकें भी नहीं दी गई हैं. शिकारियों के पास घातक हथियार होते हैं. ऐसे में निहत्थे सुरक्षाकर्मी उनसे कैसे मुक़ाबला कर सकते हैं. जहां सुरक्षा कर्मियों को बंदूकें दी गई हैं, वे भी बाबा आदम के जमाने की हैं. ऐसे में वन्य प्राणियों की सुरक्षा का दम सरकार कैसे भर सकती है?

प्राणी संग्रहालय भी सुरक्षित नहीं

व्याघ्र प्रकल्पों के साथ–साथ देश में प्राणी संग्रहालय भी सुरक्षित नहीं है. नागपुर के महाराज बाग प्राणी संग्रहालय में भी अलग–अलग कारणों से कई वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है. सांप के काटने से हिरण की मौत होने का मामला तो ताज़ा है. साथ ही बाघ की भी यहां मौत हो चुकी है. ऐसे में प्राणी संग्रहालयों की सुरक्षा पर भी सवाल उठने लगे हैं. कई प्राणी संग्रहालयों में वन्य प्राणियों के खाने की व्यवस्था काफी ख़राब है. उन्हें उचित खाना नहीं देने की शिकायतें आती रहती हैं. इसके अलावा उनके उपचार के लिए चिकित्सकों की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. साथ ही उनके पिंज़रों में साफ़–सफाई नहीं रखने से बीमारी के कारण भी उनकी मौत होने की घटनाएं देश के प्राणी संग्रहालयों में हुई हैं.

डेढ़ लाख का लैपटॉप

बाघों को बचाने के लिए प्रशासन की गंभीरता के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में मेलघाट और पेंच व्याघ्र प्रकल्प में प्रोजेक्ट टाइगर प्रकल्प चलाया जा रहा है. इस प्रकल्प के क्रियान्वयन के दौरान कई गंभीर ग़लतियां सामने आई है. उदाहरण के तौर पर ग्रामीणों में प्रकल्प और वन्य जीवों के संबंध में जनजागृति करने हेतु प्रशासन ने 1 लाख रुपये ख़र्च का प्रस्ताव किया है. वहीं दूसरी ओर इस प्रकल्प के अधिकारियों को डेढ़–डेढ़ लाख रुपये का लैपटॉप खरीदकर दिया गया है, जबकि बाज़ार में अच्छे से अच्छे लैपटॉप की क़ीमत 20 हज़ार रुपये से 40 हज़ार रुपये के बीच है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

भाजपा नेता वेंकैया नायडू के नागपुर आने पर उनका स्वागत करते पार्टी नेता विनोद तावड़े, प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ खड़से, पांडुरंग फुंडकर, किरीट सोमैया.

महाराष्ट्र विद्युत मंडल के सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विधानभवन के समीप प्रदर्शन करते हुए.

कविवर ग्रेस को विदर्भ भूषण पुरस्कार प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, वरिष्ठ साहित्यकार प्रा. महेश एलकुंचवार, वि.स. उपाध्यक्ष प्रा. वसंत पुरके, विधायक विनायकराव मेटे, अनिल देशमुख.

वर्धा ज़िले के तलेगांव में कपास का भाव बढ़ाने की मांग को लेकर भाजपा नेता पूर्व सांसद विजय मुडे, कृषक नेता इंगले के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता व किसान जलसमाधि प्रदर्शन करते हुए.

कुपोषण मुक्त ग्राम निर्माण के उद्देश्य से मोहाड़ी ग्राम सरपंच सुनीता टेकाम के नेतृत्व में निकाली गई मशाल रैली में शामिल महिलाएं व अन्य पदाधिकारी.

अमरावती ज़िले के भानखेड़ा में महानुभाव पंथ द्वारा आयोजित श्रीमद् महावाक्य प्रवचन महोत्सव के दरम्यान निकाली गई चक्रधर स्वामी की पालकी और उसमें शामिल सैकड़ों श्रद्धालु.

रायगढ़ ज़िले में लोणेरे स्थित डॉ. बाबासाहब आंबेडकर तकनीकी विद्यापीठ को राज्य का तकनीकी विश्वविद्यालय घोषित करने की मांग को लेकर शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे, राजन विचारे, भरत गोनावले, प्रताप सरनाईक, परशुराम उपरकर, विनोद घोसालकर विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करते हुए.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

सबसे अच्छी स्थिति नासिक ज़िले में सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल की रही. उनके नेतृत्व में राकांपा ने येवला, नांदगांव मनमाड़, सटाणा नपा में जीत हासिल की.

नगरपालिका चुनाव

पवार पड़े चव्हाण पर भारी

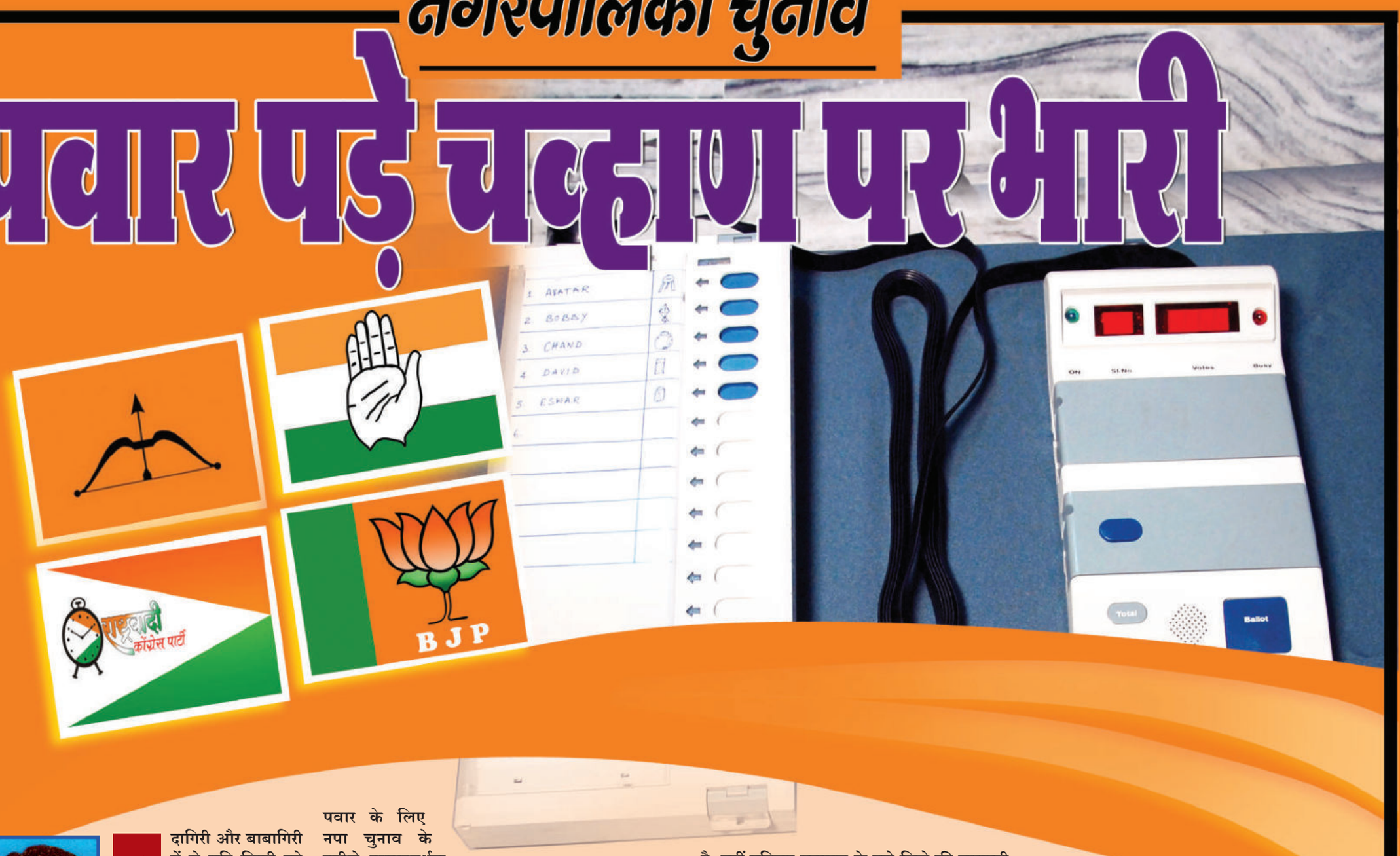

मयूर रंगारी

दादागिरी और बाबागिरी में से यदि किसी को चुनना हो तो निश्चित ही बाबागिरी को चुना जाएगा, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका चुनाव में जनता ने दादागिरी पर मुहर लगाई है. महाराष्ट्र में अजीत पवार को दादा और पृथ्वीराज चव्हाण को बाबा भी कहा जाता है. घर में बाबा का सम्मान दादा से अधिक होता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों उल्टा हो रहा है. राज्य में बदल रहा समीकरण कांग्रेस सहित विरोधी पार्टियों के लिए भी चिंता का कारण बन गया है. हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने नगर पालिका चुनाव के नतीज़ों के बाद कांग्रेस को अब आत्मपरीक्षण करने की सलाह दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन और कब आत्मपरीक्षण करेगा?

महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका चुनाव में अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग पार्टियों का वर्चस्व रहा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राकांपा ने सभी पार्टियों को इसमें काफी पीछे छोड़ दिया है. पश्चिम में तो ख़ैर राकांपा का वर्चस्व रहा ही है, लेकिन कोंकण में भी उसने पूर्व मुख्यमंत्री (शिवसेना में रहते) और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे जैसे दिग्गज को दिन में तारे दिखा दिए हैं. उत्तर महाराष्ट्र में भी राकांपा ने अच्छी जीत हासिल की है. मराठवाड़ा और विदर्भ में कांग्रेस पहले क्रमांक पर रही है, लेकिन यहां भी राकांपा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व पृथ्वीराज चव्हाण और राकांपा का नेतृत्व अजीत पवार ने किया था. ऐसे में साफ है कि छोटे पवार के लिए नपा चुनाव के नतीज़े उत्साहवर्धक है. वहीं कांग्रेस के सभी दिग्गज यानी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख को अपने-अपने गृह क्षेत्रों में हार का मुंह देखना पड़ा है. उधर, शिवसेना-भाजपा से अधिक मनसे के लिए ये नतीज़े अच्छे रहे हैं.

कोंकण में उलटफेर

नपा चुनाव में सबसे अधिक कोंकण क्षेत्र के नतीज़े चर्चा के केंद्र में रहे हैं. यहां नारायण राणे को, जिनका यहां वर्चस्व रहा है, मुंह की खानी पड़ी है. राणे के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मालवण नगरपालिका में 17 में से 8 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, जो पिछली नपा से एक सीट कम है. वहीं राकांपा को 6, शिवसेना को 2 और एक सीट पर निर्दलीय को जीत हासिल हुई है. यहां राकांपा ने शिवसेना और निर्दलीय के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया है. वहीं सावंतवाड़ी की सभी 17 सीटों पर राकांपा ने जीत हासिल की है. वेंगुर्ला में 17 में से 12 सीटें जीत कर राकांपा ने कांग्रेस को कोंकण में बढ़ रहा अपना प्रभाव दिखा दिया है. चिपलून में नारायण राणे और राकांपा नगर विकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव के बीच की वर्चस्व की लड़ाई जारी थी, जिसमें जाधव भारी पड़े राणे पर. रायगढ़ के रोहा, मुरुड-जंजीरा, श्रीवर्धन नपा में राकांपा और पेण व महाड में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. रत्नागिरी ज़िले की खेड नपा मनसे ने शिवसेना को पटखनी देकर अपना खाता खोला. नारायण राणे को शिवसेना से कांग्रेस में आए 6 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उनके आने से कोंकण क्षेत्र में पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज़ किया जाने लगा. कहा जाता है कि उन्हीं से दुखी कार्यकर्ताओं ने राकांपा का साथ दिया. वहीं राणे और जाधव के बीच चली वर्चस्व की लड़ाई ने भी राकांपा को मदद की. कांग्रेस से भी बुरी हालात शेकापा की हुई है. कोंकण को शेकापा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन केवल अलीबाग नपा में ही वह जीत हासिल कर पाई है. क्षेत्र के नतीज़ों ने सबसे अधिक मनसे का उत्साह बढ़ाने का काम किया है. वहीं पश्चिम महाराष्ट्र के पुणे ज़िले की बारामती नपा में 25 में से 24 सीटें राकांपा ने जीती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कराड क्षेत्र में राकांपा समर्थित पैनल ने जीत हासिल की. इंदापुर में सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटिल और राकांपा के बीच का मुक़ाबला दमदार रहा. यहां 17 में से 9 स्थान पर कांग्रेस और 8 स्थान पर राकांपा ने जीत हासिल की. केवल एक सीट से कांग्रेस यह नपा बचा पाई.

मराठवाड़ा में कांग्रेस को लगा झटका

मराठवाड़ा में देखा जाए तो कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें हासिल की. नांदेड़ की उमरी और माहूर नपा में राकांपा ने जीत हासिल की. हालांकि हदगांव में कांग्रेस ने जीत हासिल कर पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही शिवसेना को बाहर कर दिया. लातूर ज़िले की औसा नगरपालिका में भी राकांपा ने अपना झंडा फहराया. औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड में कांग्रेस-राकांपा को जीत हासिल हुई, लेकिन परली नपा अपने पास रखने के लिए भाजपा-शिवसेना ने राकांपा का पसीना छुड़ा दिए. यहां 32 में से 17 सीटें भाजपा-शिवसेना और 14 सीटें राकांपा को मिली. कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां के नतीज़े कांग्रेस के मंत्री राजेंद्र दर्डा के लिए उत्साहवर्धक रहे, लेकिन राकांपा ने यहां भी कांग्रेस के लिए भविष्य के लिहाज़ से मुश्किलें खड़ी कर दी हैं.

भाजपा-शिवसेना की चिंता बढ़ी

उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भ के नतीज़ों को देखें तो भाजपा-शिवसेना की स्थिति और भी ख़राब नज़र आती है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी विदर्भ से है और यहां भाजपा-शिवसेना को कांग्रेस-राकांपा ने काफी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि मनसे ने यवतमाल ज़िले की वणी नगरपालिका में 8 स्थान जीतकर विदर्भ में अपना खाता खोलने में कामयाब रही है, लेकिन यवतमाल ज़िले में भाजपा-शिवसेना एक भी नपा पर कब्ज़ा नहीं कर पाई. चंद्रपुर व गढ़चिरोली ज़िले में मूल व देसाईगंज में भाजपा, राजुरा में कांग्रेस ने जीत हासिल की. वहीं गढ़चिरोली नपा में नए संगठन युवा शक्ति ने कांग्रेस-राकांपा जैसी बड़ी पार्टियों को धूल चटाई है. बुलढाना, वाशिम, वर्धा ज़िलों में कांग्रेस, राकांपा और भाजपा ने जीत हासिल की है. उत्तर महाराष्ट्र में सेना-भाजपा-रिपाइं की महायुति को केवल कुछ स्थानों पर ही सफलता हासिल हुई है. बाकी स्थानों पर यह महायुति बे असर साबित हुई है. इसका सीधा फ़ायदा राकांपा को हुआ है. सबसे अच्छी स्थिति नासिक ज़िले में सार्वजनिक लोक निर्माण मंत्री छगन भुजबल की रही. उनके नेतृत्व में राकांपा ने येवला, नांदगांव मनमाड़, सटाणा नपा में जीत हासिल की. जलगांव में शिवसेना के विधायक सुरेश जैन और भाजपा के एकनाथ खड़से के बीच के विवाद का फ़ायदा राकांपा को हुआ. नंदुरबार ज़िले की शहादा नपा में कांग्रेस ने झंडा फहराया.

नागपुर में कांग्रेस-भाजपा आगे

नागपुर ज़िले में एक बार फिर कांग्रेस ने अपना दबदबा क़ायम रखा. वहीं राकांपा को काफी नुक़सान झेलना पड़ा है, लेकिन भाजपा और शिवसेना के लिए नपा चुनाव के नतीज़े उत्साहवर्धक रहे हैं. कांग्रेस ने कामठी, खापा और उमरेड नपा में सत्ता हासिल की. उमरेड में राज्य के राज्यमंत्री राजेंद्र मुलक के नेतृत्व में कांग्रेस ने 24 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन राकांपा के नेता और वर्तमान मंत्री अनिल देशमुख को इस बार मुंह की खानी पड़ी है. काटोल में पिछले 10 वर्षों से सत्ता में रही राकांपा और चरण सिंह ठाकुर के जनसेवा गठबंधन को इस बार हार का सामना करना पड़ा है. यहां 21 में से 13 सीटों पर राहुल देशमुख गठबंधन के शेकाप पैनल को जीत हासिल हुई है. वहीं जनसेवा गठबंधन को केवल 8 सीटों पर समाधान करना पड़ा है. इसके अलावा रामटेक, नरखेड़ और कलमेश्वर में भी पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई है. सावनेर नपा की सत्ता संगमयुग पैनल के कब्ज़े में चली गई है. यहां कांग्रेस के सुनील केदार का दबदबा रहा है. उधर, शिवसेना ने पहली बार रामटेक नपा में पूर्ण बहुमत हासिल किया है. उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस में अपना दबदबा रखने वाले मुकुल वासनिक का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र रामटेक है. भाजपा ने कलमेश्वर व मोहपा नपा पर कब्ज़ा जमाया. कामठी में भाजपा से कांग्रेस में आए सुरेश भोयर के कारण यहां कांग्रेस ने 31 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की.

feedback@chauthiduniya.com

राकांपा-कांग्रेस में बढ़ेगी वर्चस्व की लड़ाई

स्थानीय निकाय चुनाव राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय राजनीति की पहली सीढ़ी के रूप में देखे जाते हैं. बड़े नेता इन चुनावों में अपने वर्चस्व को दिखाकर राजनीति में अपनी स्थिति को मज़बूत करते हैं. ऐसे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, भाजपा के नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, शिवसेना के उद्धव ठाकरे के लिए नपा चुनावों ने आत्ममंथन की स्थिति पैदा कर दी है. इन बड़े नेताओं को अपने-अपने क्षेत्र में या तो हार का सामना करना पड़ा है या उनके राजनीति कद के अनुसार उन्हें सफलता नहीं मिली है. सबसे अच्छी स्थिति में राकांपा है, लेकिन वह केवल पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और उत्तर महाराष्ट्र में. विदर्भ और मराठवाड़ा में अभी भी कांग्रेस का दबदबा बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस के अमूमन हर बड़े नेता को अपेक्षित सफलता नहीं मिलना उसके लिए ख़तरे की घंटी है. विलासराव देशमुख के लातूर ज़िले की औसा नपा की सत्ता भी राकांपा के हाथ चली गई है. नपा चुनावों के नतीज़ों से साफ़ है कि अब राकांपा और कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई तेज़ होगी. आने वाले दो-तीन महीनों में राज्य में मनपा और ज़िला परिषद के चुनावों में यदि राकांपा-कांग्रेस गठबंधन होता भी है तो राकांपा अपने खाते में सीटें बढ़वाने के लिए ज़रूर दबाव बनाएगी. कहा जाता है कि वर्ष 2014 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में राकांपा अपना पहला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है. ज़ाहिर बात है कि अजीत पवार इसके मुख्य दावेदार है. ऐसे में इन स्थानीय निकाय चुनावों के जरिए वे इसकी ज़मीन तैयार करने में लगे हैं. यदि उनका अनुमान ठीक रहा तो महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बनते नज़र आएंगे.

महाराष्ट्र में हुए नगरपालिका चुनाव में अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग पार्टियों का वर्चस्व रहा, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो राकांपा ने सभी पार्टियों को इसमें काफ़ी पीछे छोड़ दिया है. पश्चिम में तो राकांपा का वर्चस्व रहा ही है, लेकिन कोंकण में भी उसने पूर्व मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री नारायण राणे जैसे दिग्गज को दिन में तारे दिखा दिए हैं. उत्तर महाराष्ट्र में भी राकांपा ने अच्छी जीत हासिल की है. मराठवाड़ा और विदर्भ में कांग्रेस पहले क्रमांक पर रही है, लेकिन यहां भी राकांपा की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 02 जनवरी–08 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड–बिहार में हो सबका मकान

SANJEEVANI BUILDCON

3rd & 4th floor, GEL Church Complex, Main Road, Ranchi, Customer Care No. - 0651-2331429

Our on going projects

Sanjeevani Dynasty-I
PLOT-13 LAC, DUPLEX-25 LAC
Near Ranchi College

Sanjeevani Dynasty-II
PLOT-10 LAC, DUPLEX-22 LAC
Booty More

Future City (BIT)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Namkom)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Future City (Pithoria)
PLOT-4 LAC,
BUNGLOW-10 LAC

Sanjeevani Mega Township
PLOT-3.5 LAC, BUNGLOW-09 LAC
Hazaribagh

बिहार लोकायुक्त बिल

बस दिखाने के दांत

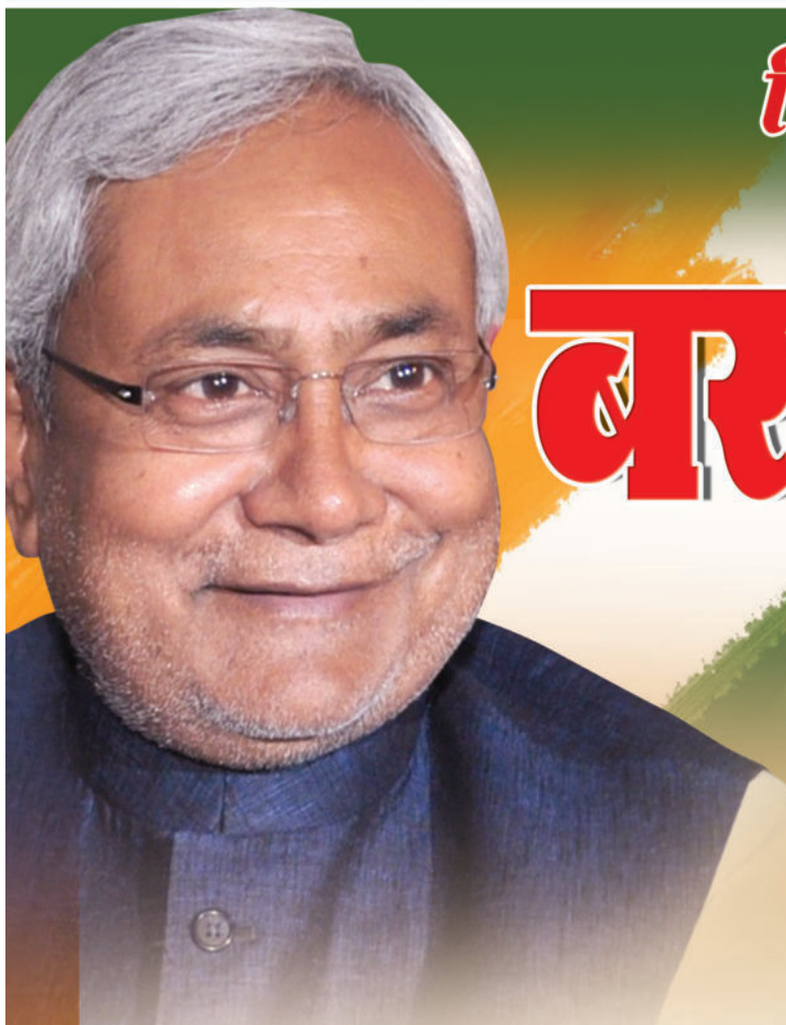

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

देश का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा होगा, जहां भ्रष्टाचार मिटाने और लोकपाल पर चर्चा नहीं हो रही है. नेताओं से लेकर ठेला चलाने वालों तक यह बहस जारी है कि यह देश भ्रष्टाचार से मुक्त कैसे होगा. सबके अपने–अपने तर्क हैं और अपने–अपने समाधान. इन बहसों के बीच बिहार सरकार द्वारा पास किए गए लोकायुक्त बिल के औचित्य और इसकी सार्थकता पर भी बहस जारी है. मुख्यमंत्री कहते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के भीतर बिहार लोकायुक्त बिल काफ़ी कारगर है जबकि पूर्व विधान पार्षद पी के सिन्हा इसे दंतहीन बता रहे हैं. उनकी राय में जल्दबाजी में इसे पारित कराने की ज़रूरत ही नहीं थी. इस पूरे संदर्भ में जदयू अध्यक्ष शरद यादव के भाषणों पर थोड़ा ग़ौर करने की ज़रूरत है.

11 दिसम्बर 2011 को जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के मंच पर जब शरद यादव अपने भाषण में बड़ी मज़बूती के साथ बोल रहे थे कि जल्दी में लोकपाल नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि पूरी तरह बहस एवं विचार करने के पहले यदि लोकपाल विधेयक पारित कर दिया गया तो इससे न तो मज़बूत लोकपाल बन सकेगा और न ऐसा लोकपाल भ्रष्टाचार पर असरदार नियंत्रण का मज़बूत हथियार बन सकेगा और अंतत: इसका ख़ामियाज़ा देश की करोड़ों जनता को भुगतना पड़ेगा. किन्तु इसी मंच से उन्होंने अत्यंत जल्दबाजी में बिना सम्यक विचार किये एवं विधान मंडल में बिना बहस के सम्पूर्ण विपक्ष के बर्हिगमन के बीच बिहार के कमज़ोर बिल की प्रसंशा करते हुए केंद्र सरकार को इसी बिल का अनुसरण करने की सलाह दे डाली थी. एक ही मंच पर एक ही समय में और एक ही विषय पर इस तरह की दोहरी नीति की उद्घोषणा का उदाहरण शायद ही मिले. संभवत: शरद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रभाव में जल्दबाजी में बिना बहस के पारित बिहार लोकायुक्त बिल की प्रशंसा करते हुए इसे अनुकरणीय बताया होगा. यहां यह स्मरण दिलाते चलें कि कुछ माह पहले जब लोकपाल एवं लोकायुक्त के मसले पर दिल्ली में नीतीश कुमार एवं प्रसिद्ध गांधीवादी नेता अन्ना हजारे की मुलाकात हुई थी, तब बिहार के एक पुराने पत्रकार ने इस मुलाकात को भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए अपने आलेख से लिखा था कि *किसी भी सत्ताधारी नेता से मिलकर इतने खुश अन्ना हजारे पहले कभी नहीं दिखे थे जितने ख़ुश वह नीतीश कुमार से मिलकर आज टीवी पर नज़र आए.* जिस मुलाकात का हवाला देकर उक्त टिप्पणी की गई थी उसी आलेख में यह भी बताया गया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीम अन्ना से बिहार में एक सशक्त एवं निष्पक्ष लोकायुक्त के लिए एक प्रारूप बिल की अपेक्षा भी की थी. तदानुसार टीम अन्ना ने मुख्यमंत्री को एक प्रारूप भेजा भी था किन्तु उक्त प्रारूप को कई महीने तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने एक नए लोकायुक्त बिल की मंजूरी मंत्रिपरिषद से करा ली. यह बिल टीम अन्ना द्वारा प्रेषित बिल से बिल्कुल भिन्न था. केजरीवाल ने बिल को कमज़ोर बताते हुए ख़ारिज कर दिया, जिस पर नीतीश कुमार ने अत्यंत रोषपूर्ण प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें टीम अन्ना से कोई प्रमाण–पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है. यहां यह भी बताते चलें कि केंद्रीय स्तर पर जो लोकपाल बिल बन रहा है, उसमें यह भी व्यवस्था है कि एक ही बिल से केंद्रीय स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की स्थापना हो जाए ताकि पूरे देश में समान एवं समरूप लोकायुक्त स्थापित हो जाए. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि क़ानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार निरोध एवं जनहित से जुड़े कई अन्य प्रमुख विषयों से संबंधित कई कानून पूरे देश में समान रूप में लागू हैं. इनमें भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988, सूचना का अधिकार अधिनियम एवं मानवाधिकार अधिनियम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. ऐसी स्थिति में बिहार में आनन–फानन में बिना बहस के विपक्ष के बर्हिगमन के बावजूद एक कमज़ोर एवं लुंजपुंज लोकायुक्त बनाने की क्या आवश्यकता थी. वह भी तब, जबकि बिहार में एक कमज़ोर लोकायुक्त की व्यवस्था पहले से ही चल रही थी. जिसमें पिछले 6 वर्षों में मुख्यमंत्री ने परिवर्तन की आवश्यकता महसूस नहीं की थी. अब यहां बिहार सरकार द्वारा आनन फानन में लोकायुक्त विधेयक, जो अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद बिहार लोकायुक्त अधिनियम 2011 बन चुका है, का इस दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत है कि यह अधिनियम कितना सशक्त, स्वतंत्र और भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में कितना कारगर है. लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित अधिनियम की धारा–3 में कहा गया है कि इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व नियुक्त लोकायुक्त अपना कार्यकाल पूरा होने तक प्रथम अध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे. इसका अर्थ हुआ कि पूर्व के अधिनियम की चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त वर्तमान लोकायुक्त लगभग पांच वर्षों तक लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष अर्थात व्यवहारिक रूप से मुख्य लोकायुक्त के पद पर बने रहेंगे. नया अधिनियम बन जाने के बाद पुराने अधिनियम एवं पुरानी चयन प्रक्रिया से चयनित एवं नियुक्त लोकायुक्त का पद पर बने रहना न सिर्फ़ अनुचित है, बल्कि क़ानून की नज़र में अवैध है. इसी प्रावधान के तहत लोकायुक्त की संस्था में मात्र तीन सदस्यों का प्रावधान किया गया है जबकि इसकी जांच के दायरे में मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक को रखा गया है. क्या इतना बड़ा दायित्व एवं कार्य भार मात्र तीन सदस्यों से संभव हो सकेगा. कहीं इसकी स्थिति वही न हो जाए जो बिहार में सूचना आयोग का हुआ है. मात्र 3 सदस्य रहने के कारण हज़ारों मामले सूचना आयोग के समक्ष वर्षों से लंबित हैं.

टीम अन्ना ने मुख्यमंत्री को एक प्रारूप भेजा भी था किन्तु उक्त प्रारूप को कई महीने तक ठंडे बस्ते में रखने के बाद 9 नवम्बर को मुख्यमंत्री ने एक नए लोकायुक्त बिल की मंजूरी मंत्रि परिषद से करा ली. यह बिल टीम अन्ना द्वारा प्रेषित बिल से बिल्कुल भिन्न था.

अधिनियम की धारा 4 में चयन समिति का प्रावधान है. इसमें विधान परिषद् के सभापति को संयोजक तथा विधान सभा के अध्यक्ष, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत दो कार्यरत न्यायाधीश तथा बर्हिगामी लोकायुक्त को चयन समिति सदस्य बनाया गया है. इस तरह का चयन समिति पूरी तरह ग़लत है. यह उल्लेखनीय है कि जब विधान परिषद् के सभापति एवं विधान सभा के अध्यक्ष को लोकपाल की जांच के दायरे में रखा गया है तब इनमें एक को संयोजक तथा दूसरे को सदस्य बनाना पूरी तरह अनुचित एवं ग़लत है. वैसे भी इस चयन समिति जिसमें विपक्ष ग़ायब है और सरकार पक्ष का बहुमत है, से निष्पक्ष एवं मजबूत लोकपाल सदस्यों के चयन की उम्मीद बेमानी है. अधिनियम की धारा 26 में अभियोजन के पूर्व सरकारी स्तर से स्वीकृति का प्रावधान है. यह पूर्णत: ग़लत है. यदि लोकायुक्त के मामले में भी वही प्रक्रिया लागू होती है जो अभी निगरानी विभाग के मामलों में है, तब तो लोकायुक्त की संस्था भी निगरानी विभाग की तरह एक सरकारी संस्था बन कर रह जाएगी, जिसका दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहेगी.

धारा 29 (5) में कुछ ऐसी स्थितियों का उल्लेख है, जिन्हें लोकायुक्त की जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि लोकायुक्त ऐसे किसी परिवाद की जांच नहीं करेंगे, जहां की गई शिकायत की जानकारी परिवादी को ऐसी शिकायत किए जाने के बारह माह पूर्व आ गयी हो. यदि परिवाद के अन्तर्गत कृत्य के कथित रूप से होने के पांच वर्षों के बाद से संबंधित ही हो. उपर्युक्त दोनों प्रावधान भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में रोड़ा बन सकते हैं. उक्त नियम में इस तरह के निषेधात्मक प्रावधान का कोई कारण अथवा औचित्य भी नहीं बताया गया है. इस तरह देखा जाए तो कहा जा सकता है कि बिहार लोकायुक्त बिल वह हथियार नहीं बन पाया, जिससे भ्रष्टाचार का समूल सफ़ाया हो सके.

feedback@chauthiduniya.com

कई अभियंता वर्षों पूर्व अग्रिम राशि को लेकर अब तक दूसरे ज़िलों में स्थानांतरित हो गए या विभाग में प्रोन्नति के बावजूद हिसाब देने की ज़रूरत नहीं समझते.

अरुण साथी

शेखपुरा में लीज़ ख़त्म होते ही वीरानी छाएगी

शेखपुरा ज़िले की पहचान पहाड़ों और पत्थरों से है. ज़िले की समृद्धि का एक मात्र कारक पहाड़ को ही माना जाता रहा है पर ज़िले के पहाड़ों पर जैसे-जैसे पत्थर माफ़ियाओं का क़ब्ज़ा हुआ वैसे वैसे शेखपुरा ज़िले की यह पहचान खोती जा रही है. पहाड़ों पर माफियाओं का क़ब्ज़ा हुआ और फिर अवैध उत्खन्न का काम ज़ोर-शोर से होने लगा. इतना ही नहीं अवैध रूप से संचालित क्रशरों का कारोबार परवान चढ़ गया और ज़िला खनन पदाधिकारी झकारी राम ने राज्य सरकार को भेजी रिर्पोट में जहां 33 अवैध क्रशरों के ज़िले में संचालन की बात कही, वहीं जब ज़िला पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने सख्ती दिखाते हुए अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने का फरमान दिया तो 74 अवैध क्रशरों को ध्वस्त कर दिया गया और इस एक मात्र आंकड़े से जिला खनन विभाग और अवैध पत्थर उत्खनन माफिया की मिलीभगत का खुलासा हो गया.

शेखुपरा ज़िले में पहाड़ों की वजह से पच्चास हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. शेखपुरा की ओर आने वाली सौ किलोमीटर लंबी सड़कों पर चारों ओर अहले सुबह कड़ाके की ठंड में भी मजदूर कुदाल और बेलचा लेकर ट्रक का इंतजार करते रहते हैं और यह सिलसिला देर रात तक चलता है. पर राज्य सरकार ने 2014 के बाद पहाड़ों की लीज खत्म करने का नियम बना दिया. इसके बाद शेखपुरा जिले में सन्नाटा छा जाएगा. इस आशय पर अपनी टिप्पणी देते हुए सीपीआई के राज्य प्रतिनिधि जितेंद्र नाथ की मानें तो शेखपुरा जिले की जीवन रेखा पहाड़ है और इसको बंद करके राज्य सरकार यहां के पच्चास हज़ार मजदूर और कारोबारियों को बेरोज़गार कर रही है. मामला यहीं नहीं थम रहा है. जिलाधिकारी के सख्त तेवर से जिले के लोग वाकिफ हैं. बावजूद जिले में अवैध पत्थर उत्खनन माफिया हावी हैं और अवैध पत्थर उत्खनन का करोबार जारी है. अवैध पत्थर उत्खन का यह करोबार चांदी, बाजीतपुर इत्यादी पहाड़ों पर किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए छापेमारी तो की जाती है पर पहुंच और पैसे वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है. ज़िले में पत्थर माफियाओं के बढ़े मनोबल का ही परिणाम है कि अवैध क्रशरों को तोड़ने में लगे अनुमंडलाधिकारी मंजूर अली को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दे दी गई. इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंजूर अली ने कहा कि अवैध पत्थर के कारोबारियों की इस करतूत से मैं डरने वाला नहीं और उन पर कार्यवाई का सिलसिला जारी रहेगा. पर वे चाहे जो भी कुछ कहें ज़िले में अरियरी प्रखंड के दो पूर्व के वीडीओ की हत्या किये जाने की वजह से यहां के पदाधिकारियों में अपराधियों का खौफ आज भी देखा जाता है. वहीं इस सारे मसले पर जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव काफी सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहते हैं कि जिले में अवैध उत्खन का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा और इसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं. ज़िलाधिकारी ने बताया कि ज़िले में अवैध रूप से विस्फोटकों का इस्तेमाल पहाड़ों को तोड़ने में किया जाता है, जिसपर अंकुश लगाने के लिए छः बड़ी कंपनियों के विस्फोटक रखने का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. कुछ भी हो पर यदि ज़िले से पहाड़ का उत्खनन बंद होने के बाद ज़िले की रौनक के साथ साथ बड़ी संख्या में यहां के मजदूर बेरोज़गार हो जाएंगे.

क्रशर के ध्वस्त होने का नजारा.

मंजूर अली, एसडीओ

पत्थर तोड़ने वाले मजदूर

वीरेंद्र प्रसाद यादव

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों के लिए मां का दूध अमृत : जनार्दन

जनार्दन प्रसाद सिन्हा — मृदुला पांडे

पटना के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ जनार्दन प्रसाद सिन्हा का मानना है कि ठंड में बच्चों के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है. ज़रा सी लापरवाही निमोनिया को न्योता दे देती है. बच्चों की सांस फूलने लगती है. ऐसे में तुरंत किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. उल्टी और दस्त शुरू हो जाएं तो ओआरएस का घोल काफ़ी कारगर होता है. बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मां का दूध तो अमृत की तरह है. सभी माताओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा जनार्दन जी की सलाह है कि बच्चों को जिन बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, उसकी सफ़ाई ठीक ढंग से होनी चाहिए. इसके साथ ही साथ खाना खिलाने वाले का हाथ भी साफ़ होना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं रखें खाने का ध्यान : मृदुला पांडे

महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत संजीदा नहीं रहती हैं. यह सही तरीका नहीं है. ख़ासकर गर्भवती महिलाओं को तो इस ओर खास ध्यान देना चाहिए. पटना की जानी-मानी स्त्री रोग चिकित्सक मृदुला पांडे मानना है कि कुछ सावधानियां बरत कर महिलाएं बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं. मृदुला पांडे बताती हैं कि गर्भवती महिलाओं में खून की कमी आम शिकायत है. ऐसा ज्यादा इसलिए होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे की खुराक का तो ध्यान रखा जाता है पर उसे पाल रही मां को भुला दिया जाता है. मां को अच्छी खुराक न मिलने से खून की कमी लाजिमी है. बच्चा तो अपनी खुराक मां से ले लेता है पर मां बहुत सारी कमजोरियों का शिकार हो जाती हैं. इनकी राय है कि गर्भ के समय

महिला की नियमित जांच बेहद ज़रूरी है. मृदुला पांडे का मानना है कि सफाई रख कर महिलाएं बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकती हैं. खासकर पीरियड के समय हाईजीन सफ़ाई ज़रूरी है. साथ ही खान-पान व साफ़-सफ़ाई ठीक रहे तो महिलाएं स्वस्थ रहेंगीं.

अनुमेहा झा
feedback@chauthiduniya.com

सारण माल सरकार का और अभियंता खेले होली

शुभम रानी चौहान

सारण में सरकार के चहेते अभियंताओं द्वारा निर्माण योजनाओं में अग्रिम के नाम पर करोड़ों रुपये निजी खाते में रख कर हिसाब न देने का सिलसिला वर्षों से जारी है. विभिन्न निर्माण विभागों के कई अभियंता लाखों रुपए अग्रिम लेकर बिना हिसाब दिए मर गए तो कई वर्षों पूर्व रिटायर हो गए. यही नहीं कई अभियंता वर्षों पूर्व अग्रिम राशि को लेकर अबतक दूसरे ज़िले में स्थानांतरित हो गए या विभाग मे प्रोन्नति के बावजूद हिसाब देने की ज़रूरत नहीं समझते. वरीय पदाधिकारियों की कथित उदासीनता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन पदाधिकारियों ने एक तो नियमों को ताक पर रख कर अग्रिम राशि दी, वही वर्षों बाद वसूलने की ज़रूरत को नहीं समझा.

इस प्रकार यह मामला सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर माल महाराज का और मिर्जा खेले होली की कहावत को चरितार्थ करता है. वहीं ग्रामीण कार्य मंडल के तीन डिविजनों भवन निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, एनआरइपी के विभिन्न सहायक अभियंताओं व कनीय अभियतांओं के यहां करोड़ों का अग्रिम वर्षों से पड़ा हुआ है. किसी भी निर्माण विभाग में एक योजना का अग्रिम देने के बाद जब तक संबंधित अभियंता वाउचर नहीं देते, दूसरी योजना का अग्रिम नहीं दिया जाता. परंतु इन विभागों में नियमों को ताक पर रखकर कम से कम ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता राजबली सिंह, बकाया 8,50,811, ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता राजदेव सिंह अवकाश प्राप्त, बकाया 7,96,128, एनआरइपी के अभियंता सोमारू राम, बकाया 4 करोड़, 7 लाख, 25 हजार 749 रुपये अनिशुर रहमान, बकाया 9 करोड, 24 लाख, 65 हजार, 927 रुपये, कौशल प्रसाद यादव, बकाया, 74 हजार, 866 रुपया, शशिभूषण सिंह, बकाया 8 करोड़ 43 लाख, 45 हजार, 43 रुपये, श्रीनाथ सिंह, रामसेवक महतो, दिनेश प्रसाद सिंह, चंद्रिका ठाकुर, एनआरइपी के पुर्व सहायक अभियता नरेंद्र सिंह, बकाया, 2 लाख , 12 हजार, 933 रुपये, 57 पैसा, कनीय अभियंता विशुनदेव सिंह, बकाया 3 लाख, 29 हजार, 126 रुपये रघुवीर प्रसाद, बकाया एक करोड़, 79 लाख, 62 हजार,314 रुपये, 20 पैसे, सुनील चौधरी, बकाया 51 लाख, 90 हजार, श्रवण कुमार सिंह, 27 लाख, 12 हजार, 623 रूपये, 45 पैसे, नित्यानंद सिंह, बकाया 30 लाख कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बकाया 50 हजार शिवजी सिंह, बकाया 1.58 लाख, सुभाषचंद्र भट, बकाया 21.8 लाख आदि शामिल है. इनमे कई तो लाखों रुपये बकाया रख कर अन्य विभागों को हिसाब दिये बिना प्रोन्नति भी पाते गए. हालांकि इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रामसेवक महतो के ख़िलाफ़ वसूली का मुकदमा दर्ज करने तथा अवकाश प्राप्त राजदेव सिंह के अवकाश ग्रहण से प्राप्त होने वाली बकाया राशि से वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. परंतु इन सभी बकाये में वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं है. एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता रामविलास राम ने कहा कि विभिन्न बकायेदारों के यहां बकाये भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है. बकाया भुगतान न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा की छह माह पूर्व स्थानांतरित होने के बावजूद अग्रिम राशि का भुगतान नहीं देने वालों पर कारवाई शुरू कर दी गयी है.

feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह का स्मृति पर्व

डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह स्मृति संस्थान सारण, जन एकता परिषद छपरा एवं समग्र विकास मंच छपरा सारण के संयुक्त तत्वाधान में प्रखर समाज सेवी स्व. डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह का 25वां स्मृति पर्व मनाया गया. समारोह का उदघाटन नगर परिषद छपरा की पूर्व मुख्य पार्षद शोभा देवी ने दीप प्रज्जवलित कर किया. समारोह का शुभारंभ श्वेता रानी, ज्योति रानी, पुष्पाजंली प्रिया, सुरभि सुधा के हर बात को तुम भुलो मगर मां-बाप को मत भूलना नाम गीत से हुआ. समारोह की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा पदाधिकारी हरिचरण प्रसाद ने की तथा संचालन अशोक कुशवाहा ने किया. समारोह को रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश, डॉ. जगदीश प्रसाद वर्मा, टुनटुन मिश्रा, विजय कुमार सिंह, छट्ठीलाल प्रसाद, नगर पार्षद जनक नंदनी देवी, प्रमीला देवी, जयचन्द प्रसाद, प्राण कुमार चन्द्रवेशी सुजीत कुमार मोर, चन्देश्वर राय चन्दाबाबू सिंह, प्रकाश राज, सुमन मौर्य राधिका देवी आदि ने सम्बोधित किया.

नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ धरना

भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का सारण ज़िला कमेटी ने नगरपालिका चौक पर धरना दिया तथा जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा. संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारे लगाते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की. इस अवसर पर माकपा के युवा नेता डॉ. सत्येन्द्र यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा की सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय ड्रामा कर रही है. संगठन सचिव सुनील राय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है. इसको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. एसएफआई के ज़िला संयोजक राजू भाई ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा अधिकार कानून की मांग की तथा कहा कि इस इस कानून की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की जाए. धरना में सगठन के संयुक्त सचिव शैलेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष गोविन्द पासवान कोषाध्यक्ष दलन यादव, प्रेमचन्द्र पासवान, अयज यादव, संगठन के ज़िलाध्यक्ष दीपक तिवारी ने की.

भिखारी ठाकुर जयंती संपन्न

सारण ज़िला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के नारायण नगर नेवाजी टोला छपरा के तत्वावधान में भोजपुरी साहित्य के सफल लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की जयंती विश्वनाथ शर्मा की अध्यक्षता मे मनाई गई. वक्ताओं में प्रो. चुनचुन पाठक, रामसूरत सिंह, रविशंकर, अमृता कुमारी, ज्योतिष पांडेय, आचार्य सारंगधर, मृत्युजंय कुमार, कमलेश कुमार सिंह, अरुण कुमार दीक्षित, बसंत कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, सुहैल अहमद हाशमी, मोहन कुमार, पंकज कुमार मिश्र आदि वक्ताओं ने लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला. वयोवृद्ध भोजपुरी चिंतक रामसूरत सिंह ने ठाकुर जी के नाम पर गोल्डनगंज स्टेशन का नाम भिखारी ठाकुर स्टेशन की मांग की. प्रो. चुनमुन पाठक ने कुतुबपुर गांव में उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने की मांग की. सभा का संचालन आचार्य सारंगधर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कमलेश कुमार सिंह ने किया.

दक्ष निरंजन सम्मानित किए गए

सारण ज़िला भोजपुरी साहित्य के तत्वाधान में विधि मंडल भवन 2 में भिखारी ठाकुर की 128वीं जयन्ती राजकिशोर गिरि की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाते हुए उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन एवं माल्यार्पण किए गए तथा भोजपुरी कवि गोष्ठी हुई, जिसमें भोजपुरी कवि दक्ष निरंजन को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया. साथ ही एक प्रस्ताव द्वारा छपरा आरा रेल पुल एवं गोल्डनगंज स्टेशन का नाम भिखारी ठाकुर के नाम किए जाने हेतु सरकार से मांग की गई. जयंती में सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार पाडेय, जीतेन्द्र दुबे, चन्द्रभूषण प्रसाद वर्मा, रामकृष्ण राम, गंगोत्री प्रसाद, सुरेन्द्र नाथ चौधरी, नन्दकिशोर गिरी, अजय कृष्ण सिंह, राजेश्वर गिरी, बिन्दा भारती, राजकुमार भारती, परशुराम मिश्र, मधुकान्त गिरी, गौरीशंकर, पिन्टू सिंह आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किये.

जदयू ने बनाए 75 हज़ार सदस्य

सीवान जदयू ज़िलाध्यक्ष मुर्तजा अली कैसर, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव अवधेश कुशवाहा व जदयू प्रभारी मुन्ना सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि ज़िले में जनता दल यूनाइटेड का सदस्यता अभियान काफी रफ्तार पकड़ चुका है और अभी तक निर्धारित लक्ष्य एक लाख के सापेक्ष 75 हज़ार से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाए जा चुके हैं. इस बार ज़िले की सभी 293 पंचायतों में कम से कम 10 सक्रिय सदस्य बनाने की योजना है. उन्होंने बताया कि सीएम की सेवा यात्रा के दौरान 11,12, एवं 13 जनवरी प्रवास की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रेस वार्ता में प्रधान महासचिव सुनील कुमार जीरदेई के प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, मिथिलेश कुमार, रंजीत कुमार, ज़िला महामंत्री नेसार अहमद, मोहम्मद निजामुद्दीन ख़ां भी मौजूद थे.

आर्मी जूनियर एक-शून्य से विजयी

डीपीआर महाविद्यालय के खेल मैदान में दारोगा प्रसाद राय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आरके स्टील बनाम आर्मी जूनियर लखनऊ के बीच खेला गया. टूर्नामेन्ट का यह फाइनल मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा. हालांकि इसमें आरके स्टील क्लब के नाईजीरियाई खिलाड़ी मैथ्यूज का जादू नहीं चला और उनकी टीम एक शून्य से पराजित हो गयी. फुटबाल का यह फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे हज़ारों दर्शकों ने खेल शुरू होने से अंत तक हर बेहतरीन शॉट पर तालियां बजाकर हौसला आफ़जाई करते रहे. मध्यांतर के बाद आर्मी जूनियर लखनऊ ने बेहतरीन गोल दाग एक शून्य से टूर्नामेन्ट पर क़ब्ज़ा जमा लिया. मैच के आयोजक पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी ने विजेता टीम आर्मी जूनियर को विजेता कप व आरके स्टील को रनर कप प्रदान किया. मैच में निर्णायक की भूमिका कैशल प्रसाद, सतीश कुमार, मखदुम ख़ान धर्मनाथ यादव ने निभाई, जबकि मंच संचालन प्राचार्य प्रो. सुभाष चंद राय ने किया.

गोपालगंज में रक्तदान शिविर

गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आयोजित रक्तदान शिविर में पांच सौ से अधिक लोगों ने रक्तदान किया. संत निरंकारी मंडल के तत्वधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मोतिहारी के सिविल जज सह निरंकारी सेवा दल के क्षेत्रीय संचालक विजय किशोर चौधरी ने किया. चौधरी ने कहा कि अप्रैल 1998 में बाबा गुरूचरण दास की हत्या के बाद निरंकारी मंडल पिछले 32 साल से रक्तदान शिविरों का आयोजन करता आ रहा है. इस रक्तदान शिविर में पटना पीएमसीएच के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उपेन्द्र प्रसाद सिंह के साथ चिकित्सकों का एक दल स्थानीय चिकित्सकों के साथ लगा हुआ था. शिविर के दौरान पांच सौ से भी अधिक स्वंयसेवकों ने रक्तदान किया. रक्त को पटना ले जाने का निर्णय लिया गया ताकि पटना में मरीज़ों को मुफ्त रक्त मिल सके. शिविर में मंडल के ज़िलाध्यक्ष मुखी श्याम लाल सोहन लाल तथा मोहन प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे.

गोपालगंज में झोपड़ी से मिलेगी निजात

मार्च माह तक ज़िले के चौदह में से बारह प्रखंडों में रहने वाले हरेक अनुसूचित जाति व जनजाति के ग़रीब व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो जाएगा. इस बात का ख़ुलासा ज़िला प्रशासन के आंकड़ों से हुआ है. विभागीय आंकड़े बताते हैं कि 2011 मई तक आवेदनों की जांच हो जाएगी. ग़रीबी रेखा के नीचे केवल 13728 अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार ऐसे बचे हैं, जिनके पास इंदिरा आवास नहीं है. दूसरे चरण में 12960 इंदिरा आवास अनूसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ही देना है. मार्च माह के बाद ज़िले में इस जाति के केवल 768 परिवार ही ऐसे बचेंगे जो इंदिरा आवास से वंचित रह जाएंगे. दूसरे चरण में भी इंदिरा आवास देने के लिए चयनित परिवार के लोगों को सिर्फ एक शपथ पत्र देने की दरकार है. नियमों के अनुसार लाभुकों के शपथ पत्र के बाद उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद इनका खाता बैंकों में खुलेगा.

लोक अदालत में 50 मामले निपटे

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में आयोजित मेगा लोक अदालत में पचास मामलों का निपटारा किया गया. बनाए गए तीनों पीठ में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों ने आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निबटारा किया गया. इसके पूर्व न्याय सबके लिए अवधारणा के साथ आयोजित इस लोक अदालत का उदघाट्न जिला सत्र न्यायाधीश डीके शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने किया. पहले पीठ में सीजेएम एसजेएम एसडीजेएम तथा न्यायिक दंडाधिकारी एस रंजन के न्यायालयों से संबंधित वादों का निपटारा किया गया. इस मौके पर सब जज पांच एसके मोदी तथा सब जज चतुर्थ एके श्रीवास्तव के अलावा तमाम न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे.

प्रस्तुति- *शुभम् रानी चौहान, मनीष कुमार*

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree In the following Subjects :
• Fire Safety Management • Industrial Safety Management
• Occupational Safety & Health Management • Environmental Safety & Health Management
Only one Institute of Bihar where students of Bihar, Magadh & Several other Universities and Employees of industrial organizations of all over India get theoretical & Practical training in fire & Safety Management.
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-3297011, Mob. : 9334107607, 9234929075
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
NATURE MOULDED FURNITURE
WINNER OF NATIONAL AWARD
1 YEAR GUARANTY
Contact : 9386595926, 9334115955

मिड डे मील योजना

बच्चों का निवाला गटक रहे हैं हाकिम

राजेश सिन्हा

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना लूट योजना बनकर रह गई है. मेन्यू के लिहाज से भी बच्चों को भोजन नसीब नहीं हो पा रहा है. बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के इरादे से सोमवार को दाल, चावल, सब्जी. मंगलवार को चावल और सोयाबीन. बुधवार को चावल, तड़का और छोला. गुरुवार को चावल और राजमा, शुक्रवार को चावल और कढ़ी जबकि शनिवार को खिचड़ी और चोखा उपलब्ध कराने की योजना बनायी गई थी. विद्यालय के प्राचार्य और भोजन उपलब्ध कराने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं के संचालकों ने सभी मापदंडों को ताक पर रखकर सप्ताह के छह दिन खिचड़ी खिलाने की ठान ली. इसमें भी दाल का अता–पता तक नहीं रहता है. अगर बच्चों ने शिक्षकों या प्राचार्य से घटिया भोजन की शिकायत कर दी तो फिर इनकी खैर नहीं. ऐसी बात नहीं है कि अधिकारियों के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में हो रही गड़गड़ी के बावत निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, निरीक्षण तो लगातार किया जा रहा है. लेकिन निरीक्षण के नाम पर महज खानापूर्ति की जा रही है. खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, फारबिसगंज, पुर्णिया, किशनगंज सहित अन्य इलाकों में मध्याह्न भोजन योजना के नाम पर हो रही लूट के बाद अब मध्याह्न भोजन में कीड़े आदि मिलने का मामला भी सुर्खियों में आने लगा है. इस योजना के नाम पर हो रही लूट का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मधुबनी ज़िले में 11 हज़ार 90 क्विंटल चावल डकार लिया गया गया. तुर्रा तो इस बात का है कि लगभग दो करोड़ का चावल डकारने के बाद भी ज़िलाधिकारी संजीव हंस के द्वारा यह कही जा रही है कि उपावंटन और उठाव में अंतर पाए जाने के बाद विभाग को इस संदर्भ में जानकारी दे दी गई है. दायित्व तय होते ही दोषी कर्मियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी. यहां पर हैरत इस बात की है कि लगातार चार वर्षों से उपावंटन के विरुद्ध एसएफसी के विभिन्न एजीएम के द्वारा चावल का उठाव नहीं किया गया और यह दावा किया जाता रहा कि ज़िले में मध्याह्न भोजन योजना सही तरीके से चल रही है. अगर मामले की गहन जांच की जाए तो इतना स्पष्ट हो जायगा कि लगभग दो करोड़ के चावल के गबन मामले में कई गुनाहगार शामिल हैं. मामले की जांच कब होगी और गुनाहगारों को कब तक सजा मिलेगी, यह तो आने वाला वक़्त ही बताएगा, लेकिन अन्य ज़िलों में मध्याह्न भोजन योजना के नाम पर हो रही लूट पर भी शासन प्रशासन को ध्यान तो देना ही होगा. सूबे के अतिपिछड़े ज़िले खगड़िया पर अगर नज़र डाली जाए तो गोगरी, चौथम, बेलदौर और अलौली प्रखंड की कौन कहे, खगड़िया प्रखंड मुख्यालय के भी कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना वर्षों से ठप्प रहने की शिकायत मिल रही है. इतना ही नहीं कई विद्यालयों में भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत भी मिलती रही है. इस तरह की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों की फौज भी विद्यालय तक पहुंच रही है. हालांकि अधिकारियों द्वारा जांच कराए जाने का आश्वासन भी दिया जाता रहा है, लेकिन जांच का आश्वासन अंधे को आइना दिखाने के समान साबित हो रहा है. विभागीय पदाधिकारी द्वारा ज़िले के अधिकांश विद्यालयों में एमडीएम योजना चालू रहने का दावा किया जा रहा है. जबकि अगर सरज़मीं पर इस योजना की जांच की जाए तो यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाएगा कि शहरी इलाकों की कुछ विद्यालयों के साथ–साथ ग्रामीण इलाक़ों के अधिकांश विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना काफी समय से बंद है. इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि मध्याह्न भोजन योजना ठप्प रहने के कारण विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है. नाराज़ बच्चे और उनके अभिभावक अब सड़कों पर भी उतरने लगे हैं. हाल ही में पूर्व खगड़िया प्रखंड अंतर्गत कोठिया गांव के सैकड़ों बच्चे और अभिभावक एमडीएम सहित अन्य स्कूली समस्याओं को लेकर खगड़िया–बखरी मुख्यमार्ग को जाम कर दिया था. बात अलग है कि अनुमंडल पदाधिकारी सुभाष चंद्र मंडल, एसडीपीओ मनोज कुमार तिवारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार ने बच्चों को आश्वासन की चासनी चटाकर जाम हटवा लिया. इसके पूर्व भी कई बार अलग–अलग विद्यालयों के बच्चे घटिया भोजन की शिकायत लेकर डीएम के जनता दरबार में पहुंच चुके हैं. कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई, लेकिन नतीजा सिफ़र ही रहा. यह बात अलग है कि दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी बच्चों को मिला. लेकिन सुलगता सवाल यह है कि आख़िर बच्चों का निवाला कब तक कफन में जेब तलाशने वालों द्वारा गटका जाता रहेगा. कुछ वर्ष पूर्व परबत्ता प्रखंड के एक विद्यालय में एक प्राचार्य को ग्रामीणों द्वारा मध्याह्न भोजन का चावल चोरी करते पकड़ा गया था. उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी. मामला कुछ दिनों तक सुर्खियों में रहा, फिर अन्य मामलों की तरह यह मामला भी दफ़न होकर रह गया. उधर युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी और कांग्रेस नेता मनोहर कुमार यादव का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना के नाम पर जमकर लूट हो रही है. एफसीआई के पदाधिकारी सहित विभागीय पदाधिकारी भी योजना के नाम पर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं. उन्होंने नियम का हवाला देते हुए कहा कि मांग के अनुरूप एफसीआई को विभाग के द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाती है. इसके बाद चावल एसएफसी पहुंचता है फिर गोदामों से एमडीएम के संवेदक द्वारा चावल का उठाव कर विद्यालयों में वितरित किया जाता है. इसी क्रम में चावल के लूट की गुंजाइश खड़ी हो जाती है. शातिर दिमाग़ी लोग बच्चों का चावल हजम कर जाते हैं. अगर इस योजना में हो रही लूट पर सरकार विराम लगाना चाहती है तो एक सर्वदलीय जांच टीम गठित कर मामले की जांच करानी चाहिए. दावा है कि कई पदाधिकारियों के चेहरे दागदार नजर आएंगे. राजद के प्रदेश महासचिव मो. अनामुल हक का कहना है कि इस तरह की योजना को सरकार द्वारा बंद कर देना चाहिए और बीपीएल परिवार की तरह सभी स्कूली बच्चों को उनके घर तक अनाज और ईंधन खर्च पहुंचाना चाहिए. दूसरी तरफ जदयू के प्रवक्ता अरविन्द मोहन का कहना है कि बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने के बावत इस योजना की शुरुआत की गई थी. बात सही है कि कुछ जगहों से इस योजना में गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही है. जदयू कार्यकर्ताओं के साथ–साथ संबंधित विभाग के पदाधिकारियों द्वारा इस योजना पर कड़ी नज़र रखी जा रही है. मध्याह्न भोजन योजना में हो रही गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को न केवल हड़काया गया है बल्कि विद्यालयों का लगातार निरीक्षण कर रिपोर्ट जिला कार्यालय को देने का आदेश भी दिया गया है. इतना ही नहीं प्रखंड के सभी वरीय प्रभारियों को स्कूल का निरीक्षण सप्ताह में एक दिन करने का जिम्मा सौंपा गया है. इस संदर्भ में जब एडीएम आनंद प्रकाश से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. दिशा निर्देश के आलोक में शिकायत मिलते ही फौरन कार्रवाई की जा रही है. बहरहाल, विभागीय प्रधान सचिव के दिशा–निर्देश का कितना असर होगा. मामले की गहन जांच का आदेश मिलने पर जांच अगर होगी तो फिर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कब तक होगी, कहां नहीं जा सकता. लेकिन बच्चों का निवाला गटकने वालों के विरुद्ध बच्चे और अभिभावक गोलबंद होने लगे हैं. बच्चों के द्वारा अगर भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया गया तो आश्चर्य किसी को भी नहीं होना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

शतरंज का खेल दिमाग तेज़ करता है

अन्य खेलों से शरीर का व्यायाम होता है किन्तु शतरंज के खेल से खिलाड़ियों के मस्तिष्क का व्यायाम होता है. इसलिये शतरंज के खिलाड़ी गंभीर और धैर्यवान भी होते हैं. स्कूली छात्र–छात्राओं को इस खेल में आगे लाया जाना चाहिये, उपरोक्त बातें चेस एसोशिएशन ऑफ बिहार के तत्वधान में बेउर स्थित इंडियन इंस्टिच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च में आयोजित हेल्थ इंस्टीच्यूट कप सी एआई ईस्ट जोन ओपेन रेटिंग चेस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने कहीं. डॉ. सुलभ ने कहा कि इस टूर्नामेंट से बिहार के शतरंज खिलाड़ियों को प्रतिभागिता का अधिक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. जो एक अच्छी बात है. इसके पूर्व प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खाद्य मंत्री श्याम रजक और डॉ. सुलभ ने अनिर्णित बाजी खेल कर किया.

शिक्षक प्रशिक्षण शिविर संपन्न

प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक के निर्देश पर हंटरगंज प्रखंड में अंकुर प्रशिक्षण के तत्वाधान में पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षकों द्वारा 14 वर्ष तक के छात्रों को रूचिकर, आनन्ददायी एवं प्रभावकारी तरीके से शिक्षा प्रदान करने की विधा बतायी गयी. प्रशिक्षक के रूप में समाजिक शिक्षक के तौर पर चर्चित रविन्द्र कुमार रवि, सुभाष कुमार एवं सच्चिदानन्द सिंह ने अहम भूमिका निभाई. प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों में शंभु प्रसाद यादव, विजय शंकर सिंह, मुन्ना कुमार, विनोद कुमार, किरण कुमारी, प्रमीला कुमारी, निर्मला कुमारी, अखौरी चंद्रशेखर समेत 40 शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया. मुख्य प्रशिक्षक रविन्द्र कुमार रवि ने बताया कि झारखंड में पहली बार सरकार द्धारा बच्चों की बुनियादी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भाषा एवं गणित के लिए खास तौर पर तैयार की गई है. हंटरगंज प्रखंड में शिक्षक प्रशिक्षण का सांतवा चरण था. प्रशिक्षण कार्यक्रम पन्द्रह चरण में समाप्त होना है.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

बाबू रामनारायण सिंह की जयंती

हंटरगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित रामनारायण सिंह इंटर एवं डिग्री महाविद्यालय में छोटानागपुर केसरी के नाम से चर्चित स्वतंत्रता सेनानी तथा हजारीबाग के पूर्व सांसद बाबू रामनारायण सिंह की जयंती एक सादे सामारोह में मनाई गयी. समारोह का मंच संचालन इंटर महाविद्यालय के प्राचार्य अजय सिंह ने किया. इस अवसर पर आगत अतिथियों ने बाबू रामनारायण सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की. समारोह को संबोधित करते हुए महाविद्यालय के संस्थापक सचिव कमल कुमार केसरी ने बाबू रामनारायण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रामनारायण सिंह की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसके बावजूद उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की. स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हंटरगंज प्रखंड के ऐसे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने कलकत्ता में उच्च शिक्षा की पढ़ाई की. इनका सपना था कि आनेवाली पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन काल में रामनारायण सिंह उच्च विद्यालय की स्थापना की तथा मरणोपरांत यहां के बुद्धिजीवियों ने भिक्षाटन करके महाविद्यालय की स्थापना की. समारोह में मुख्य रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता सूबेदार पासवान, कांग्रेस नेता सहेन्द्र राम, सभाध्यक्ष विरेश नारायण सिंह, प्रधान सहायक कौशलेन्द्र कुमार सिंह इत्यादि ने हिस्सा लिया.

–अमरेन्द्र प्रताप

झारखंडी सिल्क के दीवाने हुए चीनी

दुनियाभर का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन अब झारखंड से सिल्क वस्त्रों का आयात करेगा. झारखंड के सिल्क के दीवाने चीन के व्यवसायी भी हो गये हैं. यही कारण है कि संघाई की एक कंपनी ने झारखंड सरकार की कंपनी झारक्राफ्ट को 15 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है. यह ऑर्डर स्टोल (एक प्रकार का दुपट्टा) की आपूर्ति के लिए दिया गया है. एक कंटेनर का ऑर्डर मिला है जिसमें तीन लाख स्टोल हैं. झारक्राफ्ट के निदेशक धीरेन्द्र कुमार बताते हैं कि 22 से 24 नवम्बर तक मलेशिया में अंतरराष्ट्रीय मेला का आयोजन किया गया था, इसमें झारक्राफ्ट ने भी स्टॉल लगाया था. चीन के 11 व्यापारियों ने ऑर्गेनिक सिल्क से बनी साड़ी और स्टोल ख़रीदने की इच्छा जतायी थी. इसमें फाइनल डील स्टोल के लिए हुई. एक कंटेनर स्टोल की मांग की गयी है. अभी स्टोल के डिजाइन को संघाई भेजा गया है. डिजाइन पसंद करने के बाद स्टोल का उत्पादन किया जाएगा. तीन लाख स्टोल का निर्माण करने में तीन से चार माह का समय लगेगा.

जयनगर की सड़कों का बुरा हाल

जयनगर अनुमंडल से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 पर अधूरा पड़ा पुल जानलेवा है. ज्ञात हो कि स्थानीय वॉटरवेज चौक से महावीर चौक तक पीसीसी सड़क निर्माण लगभग पूरा हो गया है. लेकिन निर्माण कंपनी द्धारा नाला निर्माण के लिए भेलवा चौक एवं कुंवर सिंह चौक पर बनाया जा रहा पुल अधूरे हाल में है. इससे यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है. शहरी क्षेत्र से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय उच्च पथसंख्या 104 पर वाहनों के आवागमन का दबाव हमेशा बना रहता है. जिस कारण भेलवा चौक एवं कुंवरसिंह चौक पर सड़क एवं पुल निर्माण अधूरा रहने से अक्सर किसी न किसी वाहन के पलटने का नजारा देखने को मिलता रहता है. इन दुर्घटनाओं में अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं. वहीं विभाग के द्धारा संवेदक को काली सूची में तो डाल दिया गया मगर अब तक कोई पुल के लिए माकूल व्यवस्था नहीं निकाली गयी है.

अंगिका दिवस पर परमा संगीत

अंगकोकिल डॉ. परमानन्द पाण्डेय फाउंडेशन तथा राष्ट्रीय साहित्य कला परिषद् एवं संदेश की ओर से पमरा दिवस–अंगिका दिवस के अवसर पर परमा संगीत का आयोजन किया गया. दीपराज कॉमप्लेक्स में समारोह का उद्घाटन कर रोहतक की प्रो. दीप्ति ने कहा कि डॉ. परमानन्द पाण्डेय का जन्म दिवस, अंगिका दिवस के रूप में मनाया जाना विश्व–भाषा–विज्ञान के नक्शे पर इस दिशा में भी बिहार की महत्ता सिद्ध करता है. प्रो. एन.के. तिरियार ने राजीव कुमार सिंह के आलेख, डॉ. परमानन्द पाण्डेय का पाठ किया. डॉ. अरविन्द खण्डेवाल ने परमा संगीत को अलौकिक आनन्द की निधि बताते हुए पछिया बनयार के गीतों को अद्धितीय बताया. मुकेश कुमार सिन्हा, पंकज महथा बरूण कुमार सिंह ने परमा संगीत को अमर बताया. परमा संगीत के अंतर्गत उपेन्द्र प्रसाद, विनय राज सोनी के निर्देशन में पछिया बयार के लोकप्रिय गीतों के साथ कचनार की गजलें तथा चिन्ता को प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के नाम हैं–प्रियंका, सुब्रत देवनाथ इर्फ राहुल जी, अंकुर सीमा देवी सुनीता देवी, कामिनी देवी, मोना, ऋषभ राज, शिल्पा मनोज सुधांशु चक्रवर्ती, एजाजल हुसैन अखलाक अहमद जैसे वरिष्ठ कलाकारों ने परमा संगीत की सरस सरिता बहार लोगों को मुग्ध कर दिया. फाउंडेशन की ओर से आगामी 8 अप्रैल को परमा पर्व का भी आयोजन किया जायेगा.

मुंगेर में सपा ने पुतला फूंका

मुंगेर ज़िला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव एक प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रमंडलीय आयुक्त व डीआईजी से मिल, सदर बीडीओ के गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने से आक्रोशित मुंगेर जिला समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं ने जिला प्रशासन का पुतला फूंक कर अपने गुस्से का इजहार किया. इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी विरोध करने के लिए विरोध की राजनीति नहीं करती, जनता के अधिकार और सरकार के भयावह चेहरे को सामने लाने के लिए संघर्ष कर अपने दायित्व का निर्वहन करती है, क्योंकि इस सरकार में जिला प्रशासन का जो चेहरा सामने आया है वह पूरी तरह निरंकुश और तानाशाह है. इसका स्पष्ट प्रमाण प्रखंड कर्मी विवेक सिंह की मौत है. बावजूद पूरा प्रशासनिक तंत्र आरोपित वीडीओ को बचाने का प्रयास कर रहा है, जिसे पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी.

नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

सामर्थ फाउंडेशन, बिहार के तत्वधान में स्थानीय भेलावर राजकीय मध्य विद्यालय काको जहानाबाद में मेगा हैल्थ कैम्प का आयोजन किया गया. इसमें नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण प्रदेश के ख्यातिनाम चिकित्सकों द्धारा किया गया. विशिष्ट अतिथियों में चन्द्रमोहन राय, जीतन राम मांझी, पद्म श्री डॉ. सीपी ठाकुर, जगदीश शर्मा, राहुल कुमार विधायक घोसी उपस्थित रहे. फाउंडेशन की सचिव नूतन कुमारी ने बताया कि संस्था इस प्रकार के नि:शुल्क शिविरों का आयोजन बराबर करती रहेंगी. विशिष्ठ चिकित्सकों में डॉ. सीपी ठाकुर के अलावा डॉ. राजीव रंजन डॉ. अयण कुमार ठाकुर, डॉ.एचएन ठाकुर, डॉ. शांति एसबी सिंह, डॉ. हरिओम साह, डॉ. विनय कुमार, डॉ. राजकिशोर, डॉ. मुन्ना सक्सेना, डॉ. शिवचन्द्र चौधरी आदि लोगों ने भाग लिया. शिविर में भारी भीड़ रही, जिससे संस्था अपने उद्देश्य में सफल होती दिखी.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

चतरा में राष्ट्रीय पुस्तक मेला

चतरा के बालक उच्च विद्यालय में आठ दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला का उद्घाटन चतरा के उपायुक्त मनोज कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अनूप विरथरे ने संयुक्त रूप से किया. यह मेला समय इंडिया व पुस्तक मेला समिति के तात्वाधान में किया गया. इस मेले में राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशकों की पुस्तकें उपलब्ध थी. इस प्रकार का राष्ट्रीय पुस्तक मेला चतरा में पहली बार आयोजित किया गया.

–चंद्रेश शर्मा

गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं : श्याम गुप्ता

संजीवनी बिल्डिकॉन का नाम आज देश भर में लोगों को बेहतरीन, किफायती और आलीशान आशियाएने मुहैय्या कराने में सबसे अव्वल है. आम लोगों के लिए अपने घर का सपना साकार करने के लिए संजीवनी बिल्डिकॉन ने झारखंड व बिहार में ढेर सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. संजीवनी बिल्डिकॉन के डायरेक्टर श्याम गुप्ता ने बताया कि उनका प्रयास कम पैसों में लोगों को अच्छा से अच्छा मकान व प्लॉट देने का है. उन्होंने बताया कि रांची कॉलेज के पास संजीवनी डायनेस्टी–1, बुटी मोड़ के पास डायनेस्टी–2, बीआईटी, नामकुम व पिथौरिया में यूचर सिटी और हजारीबाग में संजीवनी मेगा टाउनशिप पर जोर–शोर से काम चल रहा है. इन प्रोजेक्टों में आम से लेकर खास लोगों का भी ध्यान रखा गया है. श्याम गुप्ता ने बताया कि गुणवत्ता को लेकर मेरी कंपनी कोई समझौता नहीं करती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड

दिल्ली, 02 जनवरी-08 जनवरी 2012

www.chauthiduniya.com

कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड

अजय कुमार

कांग्रेस का चाल-चरित्र चेहरा समझना मुश्किल है. वह कहती कुछ है और करती कुछ. उसने अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ मापदंड तय कर रखे हैं. गुजरात दंगों की ही बात की जाए तो कांग्रेसी मौक़ा पड़ते ही नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा को दंगों के बहाने कटघरे में खड़ा कर से नहीं चूकते. वह मुसलमानों को यह भी बताते रहते हैं कि भाजपा उसके लिए कितनी बड़ी दुश्मन है. भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी का दर्जा देने से भी कांग्रेस कभी पीछे नहीं हटती, लेकिन जो कांग्रेस गुजरात दंगों के लिए भाजपा को कसूरवार मानती है और यहां तक कहती है कि मुसलमान गुजरात दंगों को कभी भूल नहीं सकता. कांग्रेस जब 1984 के सिख दंगों, बाबरी मस्जिद विध्वंस में कांग्रेस की भूमिका आदि की चर्चा छिड़ती है तो अपना दामन बचाने लगती है. कांग्रेस चाहती है कि गुजरात दंगों के लिए ज़िम्मेदार भाजपा से मुसलमान दूर रहे. सिख दंगों और बाबरी मस्जिद विध्वंस मे महत्वमूर्ण भूमिका निभाने वाली कांग्रेस को गले लगा ले. सिख दंगों के बाद कांग्रेस की पंजाब में क्या दुर्गति हुई किसी से छिपा नहीं है. यही हाल बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में हुआ. बीस साल हो गए हैं लेकिन कांग्रेस को मुसलमानों ने माफ नहीं किया है. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और उनकी कंपनी चाहती है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान यह सब भूल कर कांग्रेस के साथ इस लिए खड़ा हो जाए क्योंकि वह मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहा है ?

ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर मुसलमान कैसे कांग्रेस पर भरोसा करे. बात बाबरी मस्जिद के गिरने तक ही सीमित नहीं है. इस विवाद को हवा देने में भी कांग्रेस की भूमिका जगजाहिर है. लोग भूले नहीं है कि 1986 में तत्कालीन केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने विवादित स्थल का ताला खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी. हालांकि ताला ज़िला अदालत के हस्तक्षेप से खोला गया था, लेकिन सरकार चाहती तो वह इस आदेश के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं. जब ताला खुला तो उस समय प्रदेश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी. सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर होता है जो कांग्रेस के युवराज कभी उत्तर प्रदेश वालों को इस लिए धिक्कारते थे कि यहां की जनता जातिवादी मानसिकता से ऊपर नहीं उठ पा रही है, वहीं राहुल अब विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को खुश करने के लिए खुलकर जातिवाद का खेल खेल रहे हैं. वह दलितों के घर जाते हैं तो कभी पिछड़ों को लुभाने के लिए हाथ-पैर मारने लगते हैं, एक रैली में तो उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लोगों को लुभाने के लिए यहां तक लोगों से पूछ लिया कि सैम पित्रोदा कौन हैं? देश में संचार क्रांति के जनक, ज्ञान आयोग के चेयरमैन, प्रधानमंत्री के सलाहाकार या और भी बहुत कुछ? राहुल गांधी ने इस महान व्यक्तित्व की एक और पहचान से जनता को रूबरू कराया तो यह समझते देर नहीं लगी कि विकास की बात करने वाले राहुल गांधी भी जातिवादी तल्ख सियासत से अपने आप को दूर नहीं रख पाए. उन्होंने रमाबाई नगर में एक जनसभा के दौरान विश्वकर्मा समाज को लुभाने के लिय यहां तक कह दिया कि उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी के दोस्त पित्रोदा विश्वकर्मा समाज से आते हैं. ऐसा ही खेल राहुल गांधी मुसलमानों को लुभाने के लिए खेल रहे हैं.

प्रदेश में अभी तक सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर दलित-पिछड़ों का राजनीतिक प्रयोग तो चलता ही रहता है, अब धर्म के नाम पर आरक्षण की वकालत शुरू हो गई है. कांग्रेस इस मामले में काफ़ी उतावली दिख रही हैं. वह बसपा-सपा को मुस्लिम आरक्षण के नाम पर पीछे ढकेल कर नंबर वन बन जाना चाहती है. कांग्रेस के युवराज जो राजनीति में उच्च मापदंडों की बात किया करते थे, बिहार से उत्तर प्रदेश आते-आते वह भी मौक़ापरस्त राजनीति का हिस्सा बन गए. कभी वह बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए दलितों पर चारा डालते हैं तो कभी सपा को चोट देने के लिए मुसलमानों की चौखट पर पहुंच जाते हैं. राहुल जब पूर्वांचल जाते हैं तो वह बुनकरों की बात करते हैं. उन्हें पता है कि इस धंधे में मुसलमानों का वर्चस्व हैं. वाराणसी में बुनकरों का क़र्ज़ माफ़ कर उनको लुभाया जाता हैं. पूर्वांचल के क़रीब एक दर्जन ज़िलों में बुनकर वोटरों का दबदबा है. युवराज मध्य उत्तर प्रदेश के दौरे पर लखनऊ आते हैं तो अचानक नदवा कॉलेज पहुंच जाते हैं. मौलाना राबे हसन नदवी साहब उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं तो मुसलमानों की समस्याएं भी उन्हें गिनाते हैं. यह मुलाकात अहम मानी जा रही थीं क्योंकि नदवी साहब के मुलायम सिंह से भी अच्छे संबंध हैं. पश्चिम में वह सपा के बाग़ी दिग्गज नेता रसीद मसूद को अपने साथ मिला लेते हैं. मुसलामनों की समस्याएं सुनी जाती है तो आरक्षण का झुनझुना बजाया जाता है.

आज स्थिति कुछ ऐसी हो गई है मानो प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण के अलावा किसी दल के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हो. मायावती लखनऊ में मुसलिम-वैश्य-क्षत्रिय सम्मेलन में दहाड़ती हैं कि उनके राज में वाराणसी और मथुरा को दूसरा अयोध्या नहीं बनने दिया गया. वह मुस्लिम आरक्षण का समर्थन करते हुए कहती हैं कि पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए उनकी आबादी के अनुपात में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत कोटे को बढ़ाए जाने और इसके लिए संविधान में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है. ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उसी राह पर चल दिए हैं जिसपर वर्षों तक मुलायम चलते रहे हैं. यही वजह है कि मुलायम को लोग मुल्ला मुलायम कहकर बुलाते थे तो राहुल गांधी को मौलाना राहुल बुलाने लगे हैं. उत्तर प्रदेश में क़रीब 20 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों की है और ये सामूहिक रूप से वोट डालना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए इन्हें लुभाने का मौक़ा कोई नहीं छोड़ता. यह और बात है कि इसका कौम को कुछ फ़ायदा हुआ तो नुक़सान भी कम नहीं उठाना पड़ा. कांग्रेस ने तो मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में खींचने के लिए पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण का रास्ता क़रीब-करीब साफ़ भी कर दिया है. बस घोषणा बाक़ी रह गई है, जिसमें ज़्यादा देर होने की उम्मीद नहीं है. केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफ़ारिशों के आधार पर तैयार रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक की मुस्लिम आरक्षण व्यवस्था का अध्ययन किया था. केंद्रीय अंल्पसंख्यक कार्य मंत्री सलमान खुर्शीद का पिछले दिनों दिया गया बयान, सरकार ने मुस्लिम आरक्षण का जो वादा किया था, अब उसका समय आ गया है. केंद्रीय कैबिनेट इस पर जल्द फ़ैसला करेगा, काफ़ी मायने रखता है. एक तरफ़ कांग्रेस की केंद्र सरकार मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रही है तो दूसरी तरफ़ वह उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार को यह भी बताने से चूक नहीं रही है कि बसपा चाहे तो अन्य राज्यों की तरह अपने यहां भी मुसलमानों को आरक्षण दे सकती है. कांग्रेस को मुस्लिम आरक्षण की राजनीति में दोनों हाथ में लड्डू नज़र आ रहे हैं. पिछड़ों के आरक्षण का सवाल उठाया तो बसपा ने था लेकिन कांग्रेस ने इसके सहारे मुसलमानों और कांग्रेस के बीच जमी बर्फ को पिघलाने के लिए कर लिया. कांग्रेस को पता है कि मुस्लिम वोट बैंक की नाराज़गी से बचने के लिए कोई भी राजनीतिक दल इसका विरोध नहीं कर पाएगा. ख़ासकर सपा और बसपा तो बिल्कुल नहीं. कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का मुसलमानों को लुभाने के लिए मस्जिदों-दरगाहों पर पहुंचना, लखनऊ में नदवा जाकर मुसलमानों को अपना हितैषी बनाना, केंद्र से मदरसों को शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर रखने का आदेश जारी करवाना कुछ ऐसे अहम क़दम रहे जिससे मुसलमानों का विश्वास कांग्रेस के प्रति लौटने लगा है. यह बात कांग्रेसी सोच रहे हैं लेकिन क्या मुसलमान बाबरी मस्जिद की शहादत को भूल कर कांग्रेस को गले लगा लेगा यह देखने वाली बात होगी. युवराज जब बसपा से सवाल पूछते हैं कि उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र सरकारों की तरह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कोई फ़ैसला क्यों नहीं लिया तो मुसलमानों के कान खड़े हो जाते है,लेकिन वह इस बात से भी अंजान नहीं हैं कि क्यों कांग्रेस को चुनाव के समय ही दलित-पिडड़े मुस्लिम आरक्षण की याद आई. कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में राज्य में इसकी सरकार बनने पर पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात कर रही है. मुसलमानों में करीब 80 प्रतिशत आबादी पिछड़ा मुसलमानों की है. इसी पर कांग्रेस की नजर है, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात को मुसलामनों में आपसी मनमुटाव पैदा करने वाला भी मानता है. यही वजह है अपवाद को छोड़कर अधिकांश मंचों से मुस्लिम समाज की तरह से इसको लेकर कोई खास उतावला पन नहीं दिखाया जा रहा है. फिर भी कांग्रेस मुस्लिम कार्ड चल रही है तो इसके पीछे कल्याण मुद्दे को लेकर मुसलमानों की मुलायम से नाराजगी बढ़ी वजह है, इस वजह को कांग्रेस अपने लिए भुनाना चाहती है.

उत्तर प्रदेश के चुनावी घमासान में मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने के लिए जिस तरह का घमासान मचा हुआ है उसमें सभी दल अपने-अपने हिसाब से पेंच तलाश रहे हैं. कांग्रेस के युवराज ने जैसे ही मुसलामानों पर डोरे डालना शुरू किया तो सपा ने एक पुस्तिका की ही तैयारी शुरू कर दी. सपा के वरिष्ठ नेता अहमद हसन कहते हैं, हां, एक पुस्तिका तैयार हो रही है. पुस्तिका में अतीत की घटनाओं को तथ्यपूर्ण तरीके से पेश किया गया है. जिसको पढ़ने के बाद कोई भी धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कांग्रेस को माफ नहीं करेगा. किताब में सपा शासन में मुलसमानों के हितों को ध्यान में रखकर उठाए गए कदमों सहित बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मुलायम को नायक और तत्कालीन केंद्र सरकार को खलनायक की तरह पेश किया गया है. यह पुस्तिका मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बंटवाई जाएगी. बात मुसलमानों की कांग्रेस के तरफ झुकाव की कि जाए तो कांग्रेस लंबे समय के बाद उत्तर प्रदेश में लड़ती हुई दिख रही है. इस लिए कुछ मुसलमानों का रुझान उनकी तरफ बढ़ता दिख रहा हैं. मुसलामों का कांग्रेस के प्रति जो रुख़ बदला है, उसमें कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी दिग्विजय सिंह की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती है, जो लंबे समय से मुसलमानों को ख़ुश करने के लिए लगातार आरएसएस पर हमला बोल रहे थे, तो अपनी ही सरकार में हुए बटाला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करने में भी लगे थे. यहां तक कि मुठभेड़ में मारे गए लड़कों (जिनको पुलिस आतंकवादी मानती थी) के घर जाने से भी नहीं हिचकिचाए थे. दिग्गी राजा का यह प्रयास लम्बे समय से जारी है. अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल गांधी लखनऊ आए और नदवा कॉलेज पहुंचे तो उसी के दूसरे दिन मुस्लिम शिक्षकों और इसी समाज के कुछ लोगों तथा कांग्रेसियों की टीम बना कर प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए. उनको मुसलामनों की समस्याओं से रूबरू किया. मुसलमानों को लुभाने के लिए कांग्रेसी टीम भावना से काम कर रहे हैं. कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य डॉ. शकील अहमद को भी पिछले दिनों लखनऊ में देखा गया. पता चला उनका दौरा नितांत निजी था, लेकिन वह मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलना नहीं भूले. शिक्षा के अधिकार कानून को लेकर उन्होंने भ्रम की स्थिति दूर करने की पूरी कोशिश की. कांग्रेस के मुस्लिम नेता जगह-जगह जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं/नेताओं से मुलाकात करके उनको सब्जसाग दिखा रहे हैं. उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि अब धर्म के आधार पर आरक्षण में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा. बहरहाल, नौकरियों में आरक्षण सहित मुसलमानों की तमाम समस्याओं के सहारे इस वोट बैंक को लुभाने में लगी कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी ने बेहद खूबी से केंद्र के खिलाफ जनता के गुस्से का रुख मोड़ने का जो प्रयास किया है, उसमें इसको कितनी सफलता मिलेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह कांग्रेस मुसलमान-मुसलमान कर रही है, इससे दुखी होकर कुछ बिरादरियां इससे दूर चली जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि वह यूपी के मिशन पर नहीं 2014 के मिशन पर काम कर रहे हैं ताकि उनके प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में कोई रोड़ा न फंसे. वह कहते हैं कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं देता, फिर सुप्रीम कोर्ट का भी तो इस संबंध में आदेश आ चुका है. मुसलामनों को आरक्षण की बात यों ही नहीं हो रही हैं. एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की 403 में से 70 विधानसभा क्षेत्रों में 20 प्रतिशत तथा कहीं-कहीं इससे भी अधिक मुस्लिम वोटर हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 पूर्वी उत्तर प्रदेश की 10 मध्य की पांच तथा बुन्देलखण्ड की एक सीट पर मुस्लिमों की मतदाताओं की संख्या 30 से 45 प्रतिशत तक है. जिस तरह विधान सभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या बढ़ रही है, इससे भी मुसलमानों का वोट हासिल करने में लगे विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के हौसले बुलंद हैं. आंकड़ों के अनुसार 1991 के विधानसभा चुनाव में 17 मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, जिनमें से एक बसपा 3 कांग्रेस तथा 13 अन्य दलों के थे. 1993 में विजयी मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या 28 हो गयी थी जिनमें से 11 समाजवादी पार्टी 10 बसपा दो कांग्रेस तथा 5 अन्य दलों के थे. 1996 के चुनाव में 38 मुस्लिम विधानसभा पहुंचे. जिनमें सपा के 19 बसपा के 13 कांग्रेस के 3 तथा अन्य 3 थे. 2002 के चुनाव में यह संख्या बढ़कर 48 हो गई, जिसमें 24 समाजवादी पार्टी 13 बसपा, चार कांग्रेस तथा 5 अन्य दलों के थे. 2007 में विधानसभा चुनाव में 56 मुस्लिम विधायक जीते, जिसमें सपा के 21 बसपा के 29 तथा अन्य दलों के 6 विधायक थे. अब देखना यह कि 2012 के चुनाव में यह संख्या कहां तक पहुंचती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

इस्लाम नहीं देता ऊंच-नीच की शिक्षा

उत्तर प्रदेश की सियासत में अतिपिछड़े मुसलमानों को आरक्षण भले ही मिल गया हो लेकिन हकीकत यह भी है कि इस्लाम इस तरह के किसी आरक्षण को मंजूरी नहीं देता है. वह एकरूपता की बात करता है. आज हिन्दुस्तान में भले ही मुसलमानों को पिछड़ा-अगड़ों में बांटा जा रहा हो लेकिन अन्य किसी मुस्लिम देश में ऐसा नहीं देखने को मिलता है. यह बात मुस्लिम धर्मगुरू भी अनौपचारिक रूप से मानते हैं. यहां तक कि इस्लाम में तो शिया-सुन्नी शब्द का भी इस्तेमाल नहीं होता. सबकी गिनती मुसलमान के रूप में होती है. फिर हिन्दुस्तान में कैसे होने लगी पिछड़े-अगड़े मुसलमानों की? इस प्रश्न का जवाब लोग हिन्दू धर्म से जोड़कर देते हैं. कहते हैं कि यह हिन्दू धर्म में व्याप्त जातिवादी परम्परा की देन है. हिन्दुस्तान में हिन्दू-मुस्लिम साथ-साथ रहते, उठते-बैठते हैं. इसी का परिणाम है यह. इसे लोग इत्तेफाक से अधिक कुछ नहीं मानते. कहा तो यहां तक जाता है कि हिन्दुस्तानी मुसलमानों की ऐसी ही बदली सोच के कारण कई अरब राज्य हिन्दुस्तानी मुसलमानों की छवि दूसरे रूप में देखी जाती है.

कई अभियंता वर्षों पूर्व अग्रिम राशि को लेकर अब तक दूसरे ज़िलों में स्थानांतरित हो गए या विभाग में प्रोन्नति के बावजूद हिसाब देने की ज़रूरत नहीं समझते.

शेखपुरा में
लीज ख़त्म होते ही वीरानी छाएगी

अरुण साथी

क्रशर के ध्वस्त होने का नजारा.

मंजूर अली, एसडीओ

पत्थर तोड़ने वाले मजदूर

वीरेंद्र प्रसाद यादव

शेखपुरा ज़िले की पहचान पहाड़ों और पत्थरों से है. ज़िले की समृद्धि का एक मात्र कारक पहाड़ को ही माना जाता रहा है पर ज़िले के पहाड़ों पर जैसे-जैसे पत्थर माफ़ियाओं का क़ब्ज़ा हुआ वैसे वैसे शेखपुरा ज़िले की यह पहचान खोती जा रही है. पहाड़ों पर माफियाओं का क़ब्ज़ा हुआ और फिर अवैध उत्खन्न का काम ज़ोर-शोर से होने लगा. इतना ही नहीं अवैध रूप से संचालित क्रशरों का कारोबार परवान चढ़ गया और ज़िला खनन पदाधिकारी झकारी राम ने राज्य सरकार को भेजी रिपोर्ट में जहां 33 अवैध क्रशरों के ज़िले में संचालन की बात कही, वहीं जब ज़िला पदाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद ने सख्ती दिखाते हुए अवैध क्रशरों को ध्वस्त करने का फरमान दिया तो 74 अवैध क्रशरों को ध्वस्त कर दिया गया और इस एक मात्र आंकड़े से जिला खनन विभाग और अवैध पत्थर उत्खनन माफिया की मिलीभगत का खुलासा हो गया.

शेखुपरा ज़िले में पहाड़ों की वजह से पच्चास हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिला है. शेखपुरा की ओर आने वाली सौ किलोमीटर लंबी सड़कों पर चारों ओर अहले सुबह कड़ाके की ठंड में भी मजदूर कुदाल और बेलचा लेकर ट्रक का इंतजार करते रहते हैं और यह सिलसिला देर रात तक चलता है. पर राज्य सरकार ने 2014 के बाद पहाड़ों की लीज खत्म करने का नियम बना दिया. इसके बाद शेखपुरा जिले में सन्नाटा छा जाएगा. इस आशय पर अपनी टिप्पणी देते हुए सीपीआई के राज्य प्रतिनिधि जितेंद्र नाथ की मानें तो शेखपुरा जिले की जीवन रेखा पहाड़ है और इसको बंद करके राज्य सरकार यहां के पच्चास हज़ार मजदूर और कारोबारियों को बेरोज़गार कर रही है. मामला यहीं नहीं थम रहा है. जिलाधिकारी के सख्त तेवर से जिले के लोग वाकिफ हैं. बावजूद जिले में अवैध पत्थर उत्खनन माफिया हावी हैं और अवैध पत्थर उत्खनन का करोबार जारी है. अवैध पत्थर उत्खन का यह करोबार चांदी, बाजीतपुर इत्यादी पहाड़ों पर किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए छापेमारी तो की जाती है पर पहुंच और पैसे वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है. ज़िले में पत्थर माफियाओं के बढ़े मनोबल का ही परिणाम है कि अवैध क्रशरों को तोड़ने में लगे अनुमंडलाधिकारी मंजूर अली को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दे दी गई. इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंजूर अली ने कहा कि अवैध पत्थर के कारोबारियों की इस करतूत से मैं डरने वाला नहीं और उन पर कार्यवाई का सिलसिला जारी रहेगा. पर वे चाहे जो भी कुछ कहें ज़िले में अरियरी प्रखंड के दो पूर्व के वीडीओ की हत्या किये जाने की वजह से यहां के पदाधिकारियों में अपराधियों का खौफ आज भी देखा जाता है. वहीं इस सारे मसले पर जिलाधिकारी वीरेंद्र प्रसाद यादव काफी सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहते हैं कि जिले में अवैध उत्खन का कारोबार नहीं चलने दिया जाएगा और इसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं. ज़िलाधिकारी ने बताया कि ज़िले में अवैध रूप से विस्फोटकों का इस्तेमाल पहाड़ों को तोड़ने में किया जाता है, जिसपर अंकुश लगाने के लिए छः बड़ी कंपनियों के विस्फोटक रखने का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है. कुछ भी हो पर यदि ज़िले से पहाड़ का उत्खनन बंद होने के बाद ज़िले की रौनक के साथ साथ बड़ी संख्या में यहां के मजदूर बेरोज़गार हो जाएगे.

feedback@chauthiduniya.com

बच्चों के लिए मां का दूध अमृत : जनार्दन

जनार्दन प्रसाद सिन्हा मृदुला पांडे

पटना के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ जनार्दन प्रसाद सिन्हा का मानना है कि ठंड में बच्चों के प्रति ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है. ज़रा सी लापरवाही निमोनिया को न्योता दे देती है. बच्चों की सांस फूलने लगती है. ऐसे में तुरंत किसी शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए. उल्टी और दस्त शुरू हो जाएं तो ओआरएस का घोल काफ़ी कारगर होता है. बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मां का दूध तो अमृत की तरह है. सभी माताओं को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा जनार्दन जी की सलाह है कि बच्चों को जिन बर्तनों में खाना खिलाया जाता है, उसकी सफ़ाई ठीक ढंग से होनी चाहिए. इसके साथ ही साथ खाना खिलाने वाले का हाथ भी साफ़ होना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं रखें खाने का ध्यान : मृदुला पाडे

महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत संजीदा नहीं रहती हैं. यह सही तरीका नहीं है. ख़ासकर गर्भवती महिलाओं को तो इस ओर खास ध्यान देना चाहिए. पटना की जानी-मानी स्त्री रोग चिकित्सक मृदुला पांडे मानना है कि कुछ सावधानियां बरत कर महिलाएं बहुत सारी बीमारियों से बच सकती हैं. मृदुला पांडे बताती हैं कि गर्भवती महिलाओं में खून की कमी आम शिकायत है. ऐसा ज्यादा इसलिए होता है कि गर्भ में पल रहे बच्चे की खुराक का तो ध्यान रखा जाता है पर उसे पाल रही मां को भुला दिया जाता है. मां को अच्छी खुराक न मिलने से खून की कमी लाजिमी है. बच्चा तो अपनी खुराक मां से ले लेता है पर मां बहुत सारी कमजोरियों का शिकार हो जाती हैं. इनकी राय है कि गर्भ के समय

महिला की नियमित जांच बेहद ज़रूरी है. मृदुला पांडे का मानना है कि सफाई रख कर महिलाएं बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकती हैं. खासकर पीरियड के समय हाईजीन सफ़ाई ज़रूरी है. साथ ही खान-पान व साफ़-सफ़ाई ठीक रहे तो महिलाएं स्वस्थ रहेंगीं.

अनुमेहा झा
feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Authorised Study Centre of EIILM University. Code-CIIP/101683
Diploma/PG Diploma/Bachelor Degree/PG Degree in the following Subjects :
• Fire Safety Management • Industrial Safety Management • Occupational Safety & Health Management • Environmental Safety & Health Management
Only one Institute of Bihar where students of Bihar, Magadh & Several other Universities and Employees of industrial organizations of all over India get theoretical & Practical training in fire & Safety Management.
Website : www.psfsm.com
410, Ashlana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-3297011, Mob. : 9334107607, 9234929075
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday

सारण
माल सरकार का और अभियंता खेले होली

शुभम रानी चौहान

सारण में सरकार के चहेते अभियंताओं द्वारा निर्माण योजनाओं में अग्रिम के नाम पर करोड़ों रुपये निजी खाते में रख कर हिसाब न देने का सिलसिला वर्षों से जारी है. विभिन्न निर्माण विभागों के कई अभियंता लाखों रुपए अग्रिम लेकर बिना हिसाब दिए मर गए तो कई वर्षों पूर्व रिटायर हो गए. यही नहीं कई अभियंता वर्षों पूर्व अग्रिम राशि को लेकर अबतक दूसरे ज़िले में स्थानांतरित हो गए या विभाग मे प्रोन्नति के बावजूद हिसाब देने की ज़रूरत नहीं समझते. वरीय पदाधिकारियों की कथित उदासीनता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन पदाधिकारियों ने एक तो नियमों को ताक पर रख कर अग्रिम राशि दी, वही वर्षों बाद वसूलने की ज़रूरत को नहीं समझा.

इस प्रकार यह मामला सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर माल महाराज का और मिर्जा खेले होली की कहावत को चरितार्थ करता है. वहीं ग्रामीण कार्य मंडल के तीन डिविजनों भवन निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी, एनआरइपी के विभिन्न सहायक अभियंताओं व कनीय अभियतांओं के यहां करोड़ों का अग्रिम वर्षों से पड़ा हुआ है. किसी भी निर्माण विभाग में एक योजना का अग्रिम देने के बाद जब तक संबंधित अभियंता वाउचर नहीं देते, दूसरी योजना का अग्रिम नहीं दिया जाता. परंतु इन विभागों में नियमों को ताक पर रखकर कम से कम ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता राजबली सिंह, बकाया 8,50,811, ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता राजदेव सिंह अवकाश प्राप्त, बकाया 7,96,128, एनआरइपी के अभियंता सोमारू राम, बकाया 4 करोड़, 7 लाख, 25 हजार 749 रुपये अनिशुर रहमान, बकाया 9 करोड, 24 लाख, 65 हजार, 927 रुपये, कौशल प्रसाद यादव, बकाया, 74 हजार, 866 रुपया, शशिभूषण सिंह, बकाया 8 करोड़ 43 लाख, 45 हजार, 43 रुपये, श्रीनाथ सिंह, रामसेवक महतो, दिनेश प्रसाद सिंह, चंद्रिका ठाकुर, एनआरइपी के पुर्व सहायक अभियता नरेंद्र सिंह, बकाया, 2 लाख , 12 हजार, 933 रुपये, 57 पैसा, कनीय अभियंता विशुनदेव सिंह, बकाया 3 लाख, 29 हजार, 126 रुपये रघुवीर प्रसाद, बकाया एक करोड़, 79 लाख, 62 हजार,314 रुपये, 20 पैसे, सुनील चौधरी, बकाया 51 लाख, 90 हजार, श्रवण कुमार सिंह, 27 लाख, 12 हजार, 623 रूपये, 45 पैसे, नित्यानंद सिंह, बकाया 30 लाख कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल बकाया 50 हजार शिवजी सिंह, बकाया 1.58 लाख, सुभाषचंद्र भट, बकाया 21.8 लाख आदि शामिल है. इनमे कई तो लाखों रुपये बकाया रख कर अन्य विभागों को हिसाब दिये बिना प्रोन्नति भी पाते गए. हालांकि इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा रामसेवक महतो के ख़िलाफ़ वसूली का मुकदमा दर्ज करने तथा अवकाश प्राप्त राजदेव सिंह के अवकाश ग्रहण से प्राप्त होने वाली बकाया राशि से वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है. परंतु इन सभी बकाये में वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं है. एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता रामविलास राम ने कहा कि विभिन्न बकायेदारों के यहां बकाये भुगतान के लिए नोटिस दिया गया है. बकाया भुगतान न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर वसूली की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा की छह माह पूर्व स्थानांतरित होने के बावजूद अग्रिम राशि का भुगतान नहीं देने वालों पर कारवाई शुरू कर दी गयी है.

feedback@chauthiduniya.com

सारण एक नज़र

डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह का स्मृति पर्व

डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह स्मृति संस्थान सारण, जन एकता परिषद छपरा एवं समग्र विकास मंच छपरा सारण के संयुक्त तत्वाधान में प्रखंर समाज सेवी स्व. डॉ. रामेश्वर प्रसाद सिंह का 25वां स्मृति पर्व मनाया गया. समारोह का उदघाटन नगर परिषद छपरा की पूर्व मुख्य पार्षद शोभा देवी ने दीप प्रज्जवलित कर किया. समारोह का शुभारंभ श्वेता रानी, ज्योति रानी, पुष्पाजंली प्रिया, सुरभि सुधा के हर बात को तुम भुलो मगर मां-बाप को मत भूलना नाम गीत से हुआ. समारोह की अध्यक्षता पूर्व शिक्षा पदाधिकारी हरिचरण प्रसाद ने की तथा संचालन अशोक कुशवाहा ने किया. समारोह को रामबाबू शर्मा, अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश, डॉ. जगदीश प्रसाद वर्मा, टुनटुन मिश्रा, विजय कुमार सिंह, छट्ठीलाल प्रसाद, नगर पार्षद जनक नंदनी देवी, प्रमीला देवी, जयचन्द प्रसाद, प्राण कुमार चन्द्रवेशी सुजीत कुमार मोर, चन्देश्वर राय चन्दाबाबू सिंह, प्रकाश राज, सुमन मौर्य राधिका देवी आदि ने सम्बोधित किया.

नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ धरना

भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई का सारण ज़िला कमेटी ने नगरपालिका चौक पर धरना दिया तथा जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा. संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के ख़िलाफ़ ज़ोरदार नारे लगाते हुए नीतीश कुमार के इस्तीफ़े की मांग की. इस अवसर पर माकपा के युवा नेता डॉ. सत्येन्द्र यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा की सरकार युवाओं को नौकरी देने के बजाय ड्रामा कर रही है. संगठन सचिव सुनील राय ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है. इसको सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. एसएफआई के ज़िला संयोजक राजू भाई ने राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा अधिकार कानून की मांग की तथा कहा कि इस इस कानून की अवहेलना करने वाले शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द की जाए. धरना में सगठन के संयुक्त सचिव शैलेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष गोविन्द पासवान कोषाध्यक्ष दलन यादव, प्रेमचन्द्र पासवान, अयज यादव, संगठन के ज़िलाध्यक्ष दीपक तिवारी ने की.

भिखारी ठाकुर जयंती संपन्न

सारण ज़िला भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के नारायण नगर नेवाजी टोला छपरा के तत्वावधान में भोजपुरी साहित्य के सफल लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की जयंती विश्वनाथ शर्मा की अध्यक्षता मे मनाई गई. वक्ताओं में प्रो. चुनचुन पाठक, रामसूरत सिंह, रविशंकर, अमृता कुमारी, ज्योतिष पांडेय, आचार्य सारंगधर, मृत्युजंय कुमार, कमलेश कुमार सिंह, अरुण कुमार दीक्षित, बसंत कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी, सुहैल अहमद हाशमी, मोहन कुमार, पंकज कुमार मिश्र आदि वक्ताओं ने लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला. वयोवृद्ध भोजपुरी चिंतक रामसूरत सिंह ने ठाकुर जी के नाम पर गोल्डनगंज स्टेशन का नाम भिखारी ठाकुर स्टेशन की मांग की. प्रो. चुनमुन पाठक ने कुतुबपुर गांव में उच्च विद्यालय एवं महाविद्यालय खोलने की मांग की. सभा का संचालन आचार्य सारंगधर ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन कमलेश कुमार सिंह ने किया.

दक्ष निरंजन सम्मानित किए गए

सारण ज़िला भोजपुरी साहित्य के तत्वाधान में विधि मंडल भवन 2 में भिखारी ठाकुर की 128वीं जयन्ती राजकिशोर गिरि की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाते हुए उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन एवं माल्यार्पण किए गए तथा भोजपुरी कवि गोष्ठी हुई, जिसमें भोजपुरी कवि दक्ष निरंजन को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया. साथ ही एक प्रस्ताव द्वारा छपरा आरा रेल पुल एवं गोल्डनगंज स्टेशन का नाम भिखारी ठाकुर के नाम किए जाने हेतु सरकार से मांग की गई. जयंती में सर्वश्री वीरेन्द्र कुमार पांडेय, जीतेन्द्र दुबे, चन्द्रभूषण प्रसाद वर्मा, रामकृष्ण राम, गंगोत्री प्रसाद, सुरेन्द्र नाथ चौधरी, नन्दकिशोर गिरी, अजय कृष्ण सिंह, राजेश्वर गिरी, बिन्दा भारती, राजकुमार भारती, परशुराम मिश्र, मधुकान्त गिरी, गौरीशंकर, पिन्टू सिंह आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किये.

जदयू ने बनाए 75 हज़ार सदस्य

सीवान जदयू ज़िलाध्यक्ष मुर्तजा अली कैसर, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव अवधेश कुशवाहा व जदयू प्रभारी मुन्ना सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि ज़िले में जनता दल यूनाईटेड का सदस्यता अभियान काफी रफ्तार पकड़ चुका है और अभी तक निर्धारित लक्ष्य एक लाख के सापेक्ष 75 हज़ार से अधिक प्राथमिक सदस्य बनाए जा चुके हैं. इस बार ज़िले की सभी 293 पंचायतों में कम से कम 10 सक्रिय सदस्य बनाने की योजना है. उन्होंने बताया कि सीएम की सेवा यात्रा के दौरान 11,12, एवं 13 जनवरी प्रवास की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. प्रेस वार्ता में प्रधान महासचिव सुनील कुमार जीरदेई के प्रखंड अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह, मिथिलेश कुमार, रंजीत कुमार, ज़िला महामंत्री नेसार अहमद, मोहम्मद निजामुद्दीन ख़ां भी मौजूद थे.

आर्मी जूनियर एक-शून्य से विजयी

डीपीआर महाविद्यालय के खेल मैदान में दारोगा प्रसाद राय मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामिंट का फाइनल आरके स्टील बनाम आर्मी जूनियर लखनऊ के बीच खेला गया. टूर्नामिन्ट का यह फाइनल मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा. हालांकि इसमें आरके स्टील क्लब के नाईजीरियाई खिलाड़ी मैथ्यूज का जादू नहीं चला और उनकी टीम एक शून्य से पारजित हो गयी. फुटबाल का यह फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे हज़ारों दर्शकों ने खेल शुरू होने से अंत तक हर बेहतरीन शॉट पर तालियां बजाकर हौसला आफ़जाई करते रहे. मध्यांतर के बाद आर्मी जूनियर लखनऊ ने बेहतरीन गोल दाग एक शून्य से टूर्नामिन्ट पर क़ब्ज़ा जमा लिया. मैच के आयोजक पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी ने विजेता टीम आर्मी जूनियर को विजेता कप व आरके स्टील को रनर कप प्रदान किया. मैच में निर्णायक की भूमिका कैशल प्रसाद, सतीश कुमार, मखदुम ख़ान धर्मनाथ यादव ने निभाई, जबकि मंच संचालन प्राचार्य प्रो. सुभाष चंद राय ने किया.

गोपालगंज में रक्तदान शिविर

गोपालगंज के मिंज स्टेडियम में आयेाजित रक्तदान शिविर में पांच सौ से अधिक लोगों ने रक्तदान किया. संत निरंकारी मंडल के तत्वधान में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन मोतिहारी के सिविल जज सह निरंकारी सेवा दल के क्षेत्रीय संचालक विजय किशोर चौधरी ने किया. चौधरी ने कहा कि अप्रैल 1998 में बाबा गुरूचरण दास की हत्या के बाद निरंकारी मंडल पिछले 32 साल से रक्तदान शिविरों का आयोजन करता आ रहा है. इस रक्तदान शिविर में पटना पीएमसीएच के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी उपेन्द्र प्रसाद सिंह के साथ चिकित्सकों का एक दल स्थानीय चिकित्सकों के साथ लगा हुआ था. शिविर के दौरान पांच सौ से भी अधिक स्वंयसेवकों ने रक्तदान किया. रक्त को पटना ले जाने का निर्णय लिया गया ताकि पटना में मरीज़ों को मुफ्त रक्त मिल सके. शिविर में मंडल के ज़िलाध्यक्ष मुखी श्याम लाल सोहन लाल तथा मोहन प्रसाद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे.

गोपालगंज में झोपड़ी से मिलेगी निजात

मार्च माह तक ज़िले के चौदह में से बारह प्रखंडों में रहने वाले हरेक अनुसूचित जाति व जनजाति के ग़रीब व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान हो जाएगा. इस बात का ख़ुलासा ज़िला प्रशासन के आंकड़ों से हुआ है. विभागीय आंकड़े बताते हैं कि 2011 मई तक आवेदनों की जांच हो जाएगी. ग़रीबी रेखा के नीचे केवल 13728 अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवार ऐसे बचे हैं, जिनके पास इंदिरा आवास नहीं है. दूसरे चरण में 12960 इंदिरा आवास अनूसूचित जाति व जनजाति के लोगों को ही देना है. मार्च माह के बाद ज़िले में इस जाति के केवल 768 परिवार ही ऐसे बचेंगे जो इंदिरा आवास से वंचित रह जाएंगे. दूसरे चरण में भी इंदिरा आवास देने के लिए चयनित परिवार के लोगों को सिर्फ एक शपथ पत्र देने की दरकरार है. नियमों के अनुसार लाभुकों के शपथ पत्र के बाद उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद इनका खाता बैंकों में खुलेगा.

लोक अदालत में 50 मामले निपटे

ज़िला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में आयोजित मेगा लोक अदालत में पचास मामलों का निपटारा किया गया. बनाए गए तीनों पीठ में उपस्थित न्यायिक पदाधिकारियों ने आपसी सुलह समझौते के आधार पर मामलों का निबटारा किया गया. इसके पूर्व न्याय सबके लिए अवधारणा के साथ आयेाजित इस लोक अदालत का उदघाट्न जिला सत्र न्यायाधीश डीके शर्मा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने किया. पहले पीठ में सीजेएम एसजेएम एसडीजेएम तथा न्यायिक दंडाधिकारी एस रंजन के न्यायालयों से संबंधित वादों का निपटारा किया गया. इस मौके पर सब जज पांच एसके मोदी तथा सब जज चतुर्थ एके श्रीवास्तव के अलावा तमाम न्यायिक पदाधिकारी व अधिवक्ता मौजूद रहे.

प्रस्तुति- शुभम् रानी चौहान, मनीष कुमार

एनआरएचएम घोटाला

दवा के दलाल

स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के एक पदाधिकारी पंडित जी का नाम भी दवा के दलालों मे शामिल है. पंडित जी की पत्नी के नाम दवा कंपनियां भी चल रही हैं. इन्हीं में से एक हैं मलिकजी. इन्हें ऊपर वालों की मेहरबानी से करीब डेढ़ सौ अस्पतालों में आरओ प्लांट (पेयजल साफ़ करने की मशीन) लगाने का ठेका मिला था.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन (एनआरएचएम) के घोटालों की तह खोलने में लगी सीबीआई अपना काम तेजी से आगे बढ़ा रही है. इसकी तेजी ने कई गुनहागारों के माथे पर सर्द मौसम में पसीना ला दिया है. नाम बदल कर ठेकेदारी और कमिशनख़ोरी का धंधा कर के मोटी कमाई करने वालों में मंत्री से लेकर संतरी तक सभी का नाम आ रहा है. जब सीबीआई का शिकंजा कसा तो कथित बड़ों को बचाने के लिए दवा घोटाला कांड की छोटी मछली समझे जाने वाले ठेकेदार नमित टंडन ने तो मौत को गले ही लगा लिया. सीबीआई की किस्मत अच्छी थी जो नमित बच गया. दवा घोटाले के आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मायावती शासन से पहले जिनकी समाज में कोई पहचान नहीं थी और थोड़े बहुत धन–दौलत के मालिक थे, वह क़रीब पांच सालों में करोड़ों–अरबों की बात करने लगे. इसी में से एक नाम है पीसीएफ के चेयरमैन और एमएलसी रामचंद्र प्रधान का. एनआरएचएम घोटाले में उनका भी नाम है. उन्होंने बसपा सरकार में अपने चहेतों के माध्यम से ठेकेदारी में ख़ूब नाम कमाया. कभी बहनजी के क़रीबी रहे बसपा के कद्दावर नेता बाबू सिंह कुशवाहा का हाथ उनके सिर पर हुआ करता था, लेकिन जब बाबू सिंह ही बसपा के लिए ग़ैर हो गए तो प्रधानजी कि भी पोल पट्टी खुलने लगी.

एनआरएचएम घोटालें की सीबीआई के घेरे में आए ठेकेदार नमित टंडन ने पिछले दिनों दहशत में आकर अपनी जान ही दांव पर लगा दी. टंडन के बारे में कहा जाता था कि वह प्रधान के लिए काम करता था. प्रधान उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे. टंडन पर सीबीआई ने जब शिकंजा कसा तो वह घबरा गया. कहा तो यहां तक जाता है कि उसके ऊपर सीबीआई लगातार दबाब बना रही थी कि वह उन ठेकेदारों का नाम उजागर करे जो बसपा शासन में एनआरएचएम घोटालें में ख़ूब मालामाल हुए हैं. उसे पता था कि अगर वह सच बोलेगा तो ऊपर वाले उसे नहीं छोड़ेंगे और झूठ बोलेगा तो सीबीआई से बचना मुश्किल हो जाएगा. इसी लिए उसने 28 नवंबर को ट्रेन केआगे कूदकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन वह बच गया, उसे गंभीर हालात में ट्रामा में भर्ती किया गया. सीबीआई उस पर पहरा बैठाए हैं और डॉक्टर से इजाजत मिलते ही सीबीआई उससे पूछताछ शुरू कर देगी. सीबीआई जानती है कि टंडन एक मोहरा मात्र है, लेकिन वह कई अहम जानकारियां दे सकता है.

बहरहाल, टंडन ने अपनी ज़ुबान खोल दी तो रामचंद्र प्रधान के साथ–साथ कई बड़े ठेकदारों के चेहरे भी उजागर हो सकते हैं. ठेकेदारों के नाम उजागर होने के बाद स्वभाविक रूप से शिकंजा बसपा के बड़े नेताओं पर कस जाएगा. जहां तक बात प्रधानजी की है तो उन्होंने तो टंडन को पहचानने से ही इंकार कर दिया है. वह कहते हैं कि मेरी हैसियत तो सबको पता है, अगर मुझे काम करना ही रहता तो 100–50 करोड़ रुपए का करता. मैं एक करोड़ के काम के लिए ठेका करने नहीं जा सकता. टंडन ने रमा इंटरप्राइजेज क जरिए जननी सुरक्षा योजना के तहत 27 एएनएम केंद्र बनवाने का काम पैक्सफेड से लिया था. इस काम में श्रेया इंटरप्राइजेज भी शामिल थी. फरवरी 11 से दिसंबर 11 तक रमा इंटरप्राइजेज के खाते में एक करोड़ रुपए आए. नमित टंडन के पैसा आते ही पचास लाख रुपए नक़द और पचास लाख रुपए का चैक कई लोगों के नाम से काट कर प्रधान की ठेकेदारी का काम देखने वाले आगा रिजवान का दिया था. सीबीआई को पता चला था कि यह पैसा बाद में प्रधान के पास पहुंच गया था. दो मंत्रियों का रसूख छीनने और कई स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जान का कारण बना दवा घोटाला आगे भी कुछ और लोगों के जीवन–मरण का कारण बन जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.

सीबीआई के घेरे में आए ठेकेदार नमित टंडन ने पिछले दिनों दहशत में आकर अपनी जान ही दांव पर लगा दी. टंडन के बारे में कहा जाता था कि वह प्रधान के लिए काम करता था. प्रधान उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करते थे. टंडन पर सीबीआई ने जब शिकंजा कसा तो वह हड़बड़ा गया. कहा तो यहां तक जाता है कि उसके ऊपर सीबीआई लगातार दबाब बना रही थी कि वह उन ठेकेदारों का नाम उजागर करे जो बसपा शासन में एनआरएचएम घोटालें में ख़ूब मालामाल हुए हैं.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को करीब से जानने वालों का कहना है कि इस विभाग में करीब एक दर्जन बड़े ठेकेदारों का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसने कई गुना महंगे दामों पर दवा व उपकरणों के घोटाले को अंजाम दिया था. इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी नेता भी शामिल हैं और राजनीतिज्ञ भी. स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी नेताओं ने तो ठेकेदारी के नाम पर इतनी लूटपाट की कि वह दवा कंपनियों के मालिक ही बन बैठे. स्वास्थ्य विभाग के मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन के एक पदाधिकारी पंडित जी का नाम भी दवा के दलालों मे शामिल है. पंडित जी की पत्नी के नाम दवा कंपनियां भी चल रही हैं. इन्हीं में से एक हैं मलिकजी उन्हें ऊपर वालों की मेहरबानी से क़रीब डेढ़ सौ अस्पतालों में आरओ प्लांट(पेयजल साफ़ करने की मशीन)लगाने का ठेका मिला था. उन्होंने जहां चाहा प्लांट लगाए और जहां चाहा नहीं. उनसे किसी ने कुछ नहीं पूछा. मलिक साहब का नाम राष्ट्रीय अध्यक्षता निवारण योजना कार्यक्रम के तहत बांटे जाने वाले चश्मों में धांधली के लिए भी याद किया जाता है. मलिक अकेले घोटालेबाज़ नहीं हैं. एनआरएचएम घोटाले में कई मंत्रियों, नेताओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों आदि के नाम शामिल थे, जिन्होंने जमकर लूटपाट की. सीबीआई अगर इन दलाल किस्म के लोगों पर शिकंजा कसे तो तमाम चौंकाने वाली बातें भी सामने आ सकती हैं.

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मुसलमानों के रहनुमा बनें राहुल

एस.ए.बेताब

कहा जाता है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है. उत्तर प्रदेश की सियासत में जब से बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया है तब से सभी राजनीतिक दलों के आकाओं की रातों की नींद हराम हो गई है. 2007 के विधानसभा चुनाव से पूर्व जब बसपा ब्राह्मण और मुस्लिम सम्मेलन करा रही थी तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह अंदाज़ा नहीं था कि मायावती का यह फ़ार्मूला इतना बड़ा गुल खिला सकता है कि इतने बड़े राज्य में बीएसपी अपने बलबूते सरकार बना सकती है. मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के विरोध की परवाह किए बिना कल्याण सिंह से हाथ मिला रहे थे और मायावती मुसलमानों में अंदर ही अंदर पैठ बना रही थी. सतीशचंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को एक नारा दिया था कि पत्थर रख लो छाती पर और बटन दबा दो हाथी पर. यह नारा अंदर ही अंदर चला और 2007 में बसपा की सरकार बनी और ब्राह्मण समाज को इसका भरपूर लाभ भी मिला. बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के दलितों को सत्ता का जो स्वाद चखाया है, इसी से प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में छटपटाहट है कि जब दलित समुदाय एकता के सूत्र में बंधकर उत्तर प्रदेश में सत्ता के ताले की चाबी तैयार कर सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं? बसपा से टूटकर डॉ. मसूद ने नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी बनाई थी और उन्होंने कैडर दिया और उत्तर प्रदेश में जिला ब्लॉक स्तर तक संगठन भी खड़ा किया. पार्टी का एक सांसद भी जीतकर आया लेकिन डॉ. मसूद अपने साथियों को बांधकर नहीं रख सके पार्टी दो फाड़ हो गई. दूसरा गुट डॉ. अरशद ख़ान वाला था. आज डॉ. मसूद पार्टी का नाम भूलकर समाजवादी पार्टी में जा चुके है और डॉ. अरशद ख़ान के साथ कोई लगने को तैयार नहीं है. अब एक और पार्टी पीस पार्टी आई है. इसने भी काफ़ी शोर शराबा मचा रखा है. कुछ मुसलमानों की सोच है कि जब जाट यादव, दलित अपनी पार्टी बना सकते है तो फिर मुसलमान क्यों नहीं?

मुलायम सिंह मुसलमानों के विरोध की परवाह किए बिना कल्याण सिंह से हाथ मिला रहे थे और मायावती मुसलमानों में अंदर ही अंदर पैठ बना रही थीं. सतीश चंद्र मिश्रा ने ब्राह्मणों को एक नारा दिया था कि पत्थर रख लो छाती पर और बटन दबा दो हाथी पर.

पिछले विधानसभा चुनाव में यूडीएफ नाम की पार्टी भी चुनाव में आई थी, जिसके उत्तर प्रदेश के कर्ता–धर्ता आजकल कहा है, यह सभी जानते है. हाजी शाहिद अख़लाक, काजी रशीद मसूद और अफजाल अंसारी ने भी पार्टी बनाई है. मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में ही अनेक पार्टियां पंजीकृत है. हर कोई मुसलमानों के नाम पर पार्टियां बनाकर मुसलमानों के नाम पर लच्छेदार बाते कर के विधायक या मंत्री बनने का सपना देखने लगता है. आज़ादी के बाद से लेकर 2011 तक देखा जाए तो मुसलमानों ने जब–जब कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है, तब–तब कांग्रेस पार्टी हारी है. इतिहास गवाह है कि संजय गांधी के जबर्दस्ती नसबंदी अभियान के विरोध में मुसलमान कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हुए तो कांग्रेस पार्टी हारी. पी.वी. नरसिंहराव के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ हुए और कांग्रेस पार्टी हारी. मेरठ मलियाना–हाशिमपुरा के दंगों के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता नसीब नहीं हुई. उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से नाराज़गी का सबूत दिया तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 26 सांसद जीतकर आए. और सपा 39 सांसदों से 22 सांसद सीट पर सिमटकर रह गई. कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को विधायक, सांसद, मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तक बनाया. इस बात को मुसलमान समझता है, लेकिन क्या आम मुसलमानों को सुरक्षा व सम्मान का अधिकार भी दिया. आम मुसलमान रेहड़ी, पटरी, घरेलू उघोग धंधे, कबाड़ी से लेकर कूड़ा बीनने तक आ गया है. आतंकवाद के नाम पर दारूल इलूम देवबंद के मौलाना को हवाई जहाज से उतार लिया गया. कहीं भी किसी की टोपी दाढ़ी खींची जाती है उन्हें बेइज्जत किया जाता है लेकिन उस वक्त कांग्रेस पार्टी में बैठे मुस्लिम पावरफुल मंत्री, नेतागण कुछ नहीं बोलते हैं. मालेगांव धमाके, मक्का मस्जिद धमाके के बाद निर्दोष मुसलमानों पर फायरिंग, मलियाना, हाशिमपुरा के दोषियों को सजा क्यों नहीं मिलती है. दिल्ली में ही बटला हाउस एनकाउंटर, जंगपुरा की नूर मस्जिद को शहीद कर दिया गया. दिल्ली में वक्फ की जायदादों से क़ब्ज़े नहीं हटाए गए आख़िर मुसलमानों के नाम पर राज्यसभा में बैठे तथाकथित मुस्लिम रहनुमाओं की बात अब मुसलमान क्यों माने. राहुल गांधी के सारथियों में मुसलमानों को जोड़ने की ज़िम्मेदारी संभालने वाले मो. अदीब सांसद से अपेक्षा किया जा रहा था कि वह मुसलमानों की समस्याओं पर राहुल गांधी को समझा पाएंगे. धारा 341 में संशोधन के मुद्दे पर और राजस्थान के भरतपुर के गोपालगढ़ में मुसलमानों पर हुई पुलिस बर्बरता जिसमें 11 मुसलमान मारे गए थे. उनके दोषियों के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाकर उन्हें सज़ा दिलवाकर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को इंसाफ देने का काम कर सकती है लेकिन मौ. अदीब अभी तक ऐसा कुछ नहीं करवा पाए. जिससे वह उत्तर प्रदेश में मुसलमानों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग सकें. मुस्लिम सांसद रंगनाथ मिश्रा, सच्चर समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए नहीं बोलते है, वहां पर मुलायम सिंह यादव रिपोर्ट लागू कराने के लिए संसद में बोलते है तो फिर मुसलमानों को सपा के साथ जाना चाहिए या गोपालगढ़ बटला हाउस, नूर मस्जिद जैसे जघन्य कांड कराने वाली सरकार के साथ या पीस पार्टी व बसपा के साथ जाना चाहिए. यह फ़ैसला मुसलमान करेंगे कि वो मुसलमानियत के नाम पर आने वाले प्रत्याशी को वोट देंगे या साफ–सुथरी छवि के सेकुलर प्रत्याशी को वोट देंगे. राहुल गांधी के अति प्रचार के बावजूद बिहार में 9 विधानसभा सीटों से घटकर 4 सीटें रह गई थी जबकि उत्तर प्रदेश में 2007 में पार्टी मात्र 22 सीटे ही जीत पाई थी. जबकि लोकसभा चुनाव में राहुल ने कम प्रचार किया तो 26 लोकसभा सीटें जीती थी.

feedback@chauthiduniya.com